राष्ट्रीय संस्करण

2024 के आखिर तक तैयार हो जाएगा जेवर हवाईअड्डा >> 3

वर्ष 7 अंक 242

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 14

जागरण विशेष

यशस्वी प्रधान

महिला प्रधान के प्रबंधन से प्रेरणास्रोत बनी ग्राम पंचायत

देहरादून: जज्बा हो तो अल्प शिक्षा भी आड़े नहीं आती। उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित बड़कोट ग्राम पंचायत की प्रधान सरिता देवी इसका प्रमाण हैं। (पेज-7)

संपादकीय

रंग लाएगा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान: चूंकि जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी अभियान पर विराम लगते नहीं देखना चाहती, इसलिए यदि मोदी सरकार और बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आए तो हैरानी नहीं। **सुरेंद्र किशोर** का दृष्टिकोण।

जिंदगी बदलता जल जीवन मिशन: जल जीवन मिशन स्वास्थ्य जोखिमों को घटाने के साथ ही लोगों के जीवन स्तर में सुधार भी ला रहा है। **गजेंद्र सिंह शेखावत** का आलेख। • पेज 8

विमर्श

देश नव-निर्माण की आसान बनेगी राह: उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित कर दिया है। अन्य राज्यों के लिए भी यह पथ प्रदर्शक का काम करेगी, जिसे विश्लेषित कर रहे हैं, **ज्ञानेंद्र रावत**।

लीक पर चलेंगे या नई लकीर खीचेंगे 'टाइगर': कानूनी कारणों से मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद झारखंड में चम्पाई सोरेन नए सीएम तो बन गए हैं, परंतु यह देखना होगा कि वह लीक पर चलेंगे या फिर नई लकीर खीचेंगे। इसे दर्शाती **प्रदीप सिंह** की डायरी। • पेज-9

दैनिक जागरण सप्तरंग

मनोरंजन की दुनिया का

कमाई अलग है किस्मत अलग

सफलता का इतिहास दोहराने की तैयारी • पेज-13

भाजपा का श्वेत बनाम कांग्रेस का स्याह पत्र

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर मोदी सरकार लाई श्वेत पत्र

कहा, कांग्रेस ने किया था अर्थव्यवस्था को ध्वस्त, हमने शीर्ष पांच में पहुंचाया

राजीव कुमार, नई दिल्ली

- वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया श्वेत पत्र, अंतरिम बजट में की थी घोषणा
- आरोप- संप्रग को मजबूत अर्थव्यवस्था मिली थी, लेकिन उसने इसे पांच कमजोर अर्थव्यवस्था में शामिल कर दिया
- श्वेत पत्र में संप्रग सरकार और मोदी सरकार की वित्तीय स्थिति की पेश की गई तस्वीर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संप्रग सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन को लेकर लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया। (स्क्रीन शाट)। प्रेट्र

बदलती तस्वीर

	संप्रग सरकार		राजग सरकार	
योजना	अवधि	परिणाम	अवधि	परिणाम
किफायती आवास ग्रामीण	2003-2014	2.1 करोड़	2016-2024	2.6 करोड़
शौचालयों का निर्माण	2011-2014	1.8 करोड़	2014-2024	11.5 करोड़
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किफायती पेंशन (लाभार्थी)	2011-2014	36.4 लाख	2015-2023	6.1 करोड़
न्यूनतम शून्य राशि वाले बैंक खाते	2005-2012	10.3 करोड़	2014-2024	51.6 करोड़
ग्रामीण विद्युतीकरण (आवास)	2005-2014	2.15 करोड़	2017-2022	2.86 करोड़
सस्ती दवा के जन औषधि केंद्र	2008-2014	164	2014-2023	10,000
आप्टिकल फाइबर बिछाई	2011-2014	6,577 किमी	2015-2023	6.80 लाख किमी
मातृत्व लाभ योजना के लाभार्थी	2010-2013	9.90 लाख	2017-2023	3.59 करोड़

संप्रग शासनकाल में दुनिया की पांच कमजोर अर्थव्यवस्था में शामिल रही भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच शीर्ष अर्थव्यवस्था में शामिल करने के सफरनामे का दावा करते हुए गुरुवार को मोदी सरकार ने संसद में श्वेत पत्र जारी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 54 पेज का यह श्वेत पत्र लोकसभा में पटल पर रखा। एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करते वक्त उन्होंने इसकी घोषणा की थी। अब इस पर सदन में चर्चा होगी, पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में।

श्वेत पत्र में बताया गया है कि वाजपेयी सरकार से मजबूत आर्थिक विरासत मिलने के बावजूद संप्रग सरकार ने 2004 के बाद अपनी खोखली आर्थिक नीतियों एवं आर्थिक घोटाले की बदौलत देश की अर्थव्यवस्था को कर्ज व राजकोषीय घाटे से लाद दिया। इससे विदेशी निवेशक निवेश से हिचकने लगे, मैन्यूफैक्चरिंग में गिरावट होने लगी, महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई और जनता बिजली, पेयजल, अस्पताल जैसी आधारभूत सुविधाओं के लिए तरसने लगी। सरकार इस श्वेत पत्र के माध्यम से जनता को यह भी बताना चाहेगी कि कैसे संप्रग सरकार के दौरान बजट को गलत तरीके से पेश किया गया, कर्ज की बात को छिपाया गया। साथ ही अब राजग काल में कैसे तस्वीर बदल रही है।

श्वेत पत्र में कहा गया कि विभिन्न सब्सिडी के लिए तेल विपणन, खाद व खाद्य निगम को वर्ष 2006 से 2010 के बीच 1.90 लाख करोड़ रुपये के बांड जारी कर दिए गए और राजकोषीय घाटा व राजस्व घाटा बढ़ने के डर से इस कर्ज को छिपाया गया जिसे अब राजग की सरकार चुका रही है। उस दौरान रक्षा तैयारियों तक से समझौता हो रहा था। नतीजा यह हुआ कि वर्ष 2014 आते-आते दुनिया का भारत की आर्थिक क्षमता व गतिशीलता से भरोसा उठने लगा, वित्तीय अनुशासनहीनता बढ़ने लगी और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। सरकार देश को चमकाने की बजाय अपनी राजनैतिक छवि को चमकाने में अधिक भरोसा करने लगी। मार्च 2013 में कुमार मंगलम बिरला ने अपने एक इंटरव्यू में यहां तक कह डाला कि वह इंडोनेशिया व ब्राजील जैसे देशों में निवेश पसंद करेंगे क्योंकि भारत में लगातार नीतिगत बदलाव से उनकी निवेश योजना प्रभावित हो रही है। बिना जांचे-परखे लोन देने की वजह से संप्रग के काल में बैंकिंग संकट गहरा गया था। बैंकों के एनपीए बढ़ने लगे थे और बैंक अंदर से खोखला हो रहे थे। विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो रहा था और वर्ष 2013 के अगस्त में यह 256 अरब डालर था जोकि वर्ष 2011 में 294 अरब डालर था। राजकोषीय घाटा अधिक होने से वित्त वर्ष 2011-12 में बजटीय प्रविधान की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक बाजार से कर्ज लिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास चरमराने लगा था। सामाजिक व ग्रामीण मामले से जुड़े मंत्रालय के पैसे खर्च तक नहीं किए जा रहे थे। इन विभागों के लिए 2004-14 के दौरान खर्च के लिए आवंटित 94,060 करोड़ रुपये ऐसे ही रखे रह गए।

2014 में एनडीए की सरकार बनी तो अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी पेज>>5

अपने काले कारनामे छिपाने को कांग्रेस ने जारी किया ब्लैक पेपर : भाजपा

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी करने को लेकर गुरुवार को कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने दावा किया कि विपक्षी पार्टी अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए इसे लेकर आई है। उसे दर्द हो रहा है क्योंकि वह भ्रष्टाचार के मामलों में हो रही कार्रवाई को बंद करवाना चाहती है। (पेज-5)

कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 वर्षों को बताया अन्याय काल

- स्याह पत्र जारी कर गिनाई महंगाई-बेरोजगारी से लेकर लोकतंत्र पर प्रहार की लंबी फेहरिस्त
- अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा पर नाकामी गिनाने के साथ एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया

नई दिल्ली में गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र की मोदी सरकार की दस वर्ष की विफलताओं की सूची के साथ ब्लैक पेपर जारी किया। साथ में हैं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा। प्रेट्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस ने श्वेत पत्र के जवाब में भाजपा सरकार की विफलताओं की लंबी फेहरिस्त गुरुवार को स्याह पत्र के रूप में जारी की। इसमें भयंकर बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था और किसानों की बदहाली के दावे करते हुए मोदी सरकार के 10 साल को 'अन्याय काल' करार दिया गया है। सरकार पर सामाजिक अन्याय से लेकर राजनीतिक तानाशाही का आरोप लगाते हुए पार्टी ने कहा है कि महिलाओं, एससी-एसटी और ओबीसी ही नहीं धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। लद्दाख में सीमा पर चीनी अतिक्रमण के बाद बने बफर जोन पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करने, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, गैर भाजपा शासित राज्यों से भेदभाव करने के साथ लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया गया है। संसद में सरकार के श्वेत पत्र रखने से पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रेस कांफ्रेंस कर 57 पेज का स्याह पत्र जारी किया। इसमें सभी प्रमुख क्षेत्रों में सरकार की विफलताओं और वादाखिलाफी को आरोपपत्र के रूप में पेश किया गया है। मोदी की गारंटियों के प्रचार पर प्रहार करते हुए खरगे ने हर वर्ष दो करोड़ नौकरियां देने और किसानों की आय दोगुनी करने जैसे उनके अधूरे वादों का आईना दिखाया। कहा कि पीएम जब संसद में अपनी बात रखते हैं तो नाकामियों को छिपाते हैं और सवालों के जवाब नहीं देते। इसीलिए हम 'स्याह पत्र' लेकर आए हैं। दावा किया गया है कि मोदी सरकार के 10 साल में अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। देश विनाशकारी नोटबंदी की मार से अब तक बाहर नहीं आ पाया है। पेट्रोल, डीजल समेत जरूरी वस्तुओं की कीमतें रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई हैं।

हर वर्ष दो करोड़ रोजगार का पीएम मोदी का वादा 10 साल में भी पूरा नहीं पेज>>5

नहीं बढ़ेगी ईएमआइ, फिर स्थिर रही रेपो दर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- आरबीआइ एमपीसी ने लगातार छठी बार स्थिर रखी प्रमुख नीतिगत दर
- गवर्नर बोले- महंगाई को घटाकर चार प्रतिशत पर लाने में सफल रहेंगे

आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने एक बार फिर रेपो दर को स्थिर रखने का फैसला किया है। इससे होम लोन, आटो लोन व दूसरे तरह के लोन की ब्याज दरें स्थिर रहेंगी। हालांकि, इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि आने वाली कुछ तिमाहियों में ब्याज दरों में राहत मिल सकती है। बीते करीब एक वर्ष से आरबीआइ की प्रमुख नीतिगत दर (रेपो दर) 6.5 प्रतिशत पर स्थिर है। छह से आठ फरवरी तक चली बैठक में एमपीसी के कुल छह में से पांच सदस्य रेपो दर को स्थिर रखने के पक्ष में रहे, जबकि एक सदस्य कटौती के पक्ष में रहे।

आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने अनिश्चित वैश्विक हालातों को लेकर चिंता जताई है और इन्हें ब्याज दरों पर असर पड़ने वाले सबसे बड़े कारक के तौर पर चिह्नित किया है। उन्होंने भरोसा जताया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में खुदरा महंगाई की दर को घटाकर चार प्रतिशत पर लाने में सफल रहेंगे। इसको लेकर उन्होंने केंद्रीय बैंक की प्रतिबद्धता जताई है। आरबीआइ दीर्घकालिक अवधि के लिए देश में महंगाई दर को चार प्रतिशत (दो प्रतिशत ज्यादा या कम) पर बनाए रखने का लक्ष्य लेकर चलता है। इसके लिए ही ब्याज दरों में कमी या वृद्धि की जाती है। 2022 व 2023 की शुरुआत में जब महंगाई के तेवर तल्ख थे, तब आरबीआइ ने रेपो दर में छह बार लगातार वृद्धि की और इसे चार प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया था। खुदरा महंगाई जुलाई 2023 में 7.44 प्रतिशत तक चली गई थी, जो दिसंबर 2023 में 5.69 प्रतिशत रही है। आरबीआइ ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान औसत महंगाई दर 5.4 प्रतिशत रहने के अनुमान को बरकार रखा है।

शक्तिकांत दास। फाइल फोटो

महंगाई में कमी लाने के उपायों का दिख रहा असर

नई दिल्ली : गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अभी तक महंगाई थामने के जो कदम उठाए गए हैं, उनका असर दिख रहा है। महंगाई कम हो रही है। 2024 में यह और कम होगी। (पेज-10)

भारत-म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही रोकी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- आंतरिक सुरक्षा के लिए उठाया कदम : गृह मंत्री अमित शाह
- सरकार ने मुक्त आवाजाही समझौता तत्काल प्रभाव से निलंबित किया
- सीमा पर बाड़ लगाने के साथ-साथ पेट्रोलिंग के लिए ट्रैक भी बनेगा

भारत सरकार ने मणिपुर समस्या की प्रमुख वजह बने म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही को रोकने का फैसला किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट में कहा, विदेश मंत्रालय म्यांमार सरकार से बातचीत कर मुक्त आवाजाही के समझौते को खत्म करने पर काम कर रहा है। इसके पहले गृह मंत्रालय ने इस समझौते को निलंबित कर दिया है। इसके बाद म्यांमार और भारत से लोगों की मुक्त आवाजाही पर तत्काल रोक लग गई है। गृह मंत्रालय ने म्यांमार से सटी 1643 किलोमीटर की पूरी सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है।

शाह ने साफ किया कि मोदी सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए संकल्पबद्ध है। म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही (एफएमआर) पर रोक का फैसला देश की आंतरिक सुरक्षा और पूर्वोत्तर राज्यों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन को लेकर किया गया है। उन्होंने ना सिर्फ म्यांमार की सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया, बल्कि इसकी बेहतर निगरानी के लिए बाड़ के साथ पेट्रोलिंग के लिए ट्रैक भी बनाया जा सकेगा। बाड़ को स्मार्ट बनाने की तैयारी चल रही है। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में एक-एक किलोमीटर में स्मार्ट बाड़ (हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम) को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाया जाएगा।

16 किमी के दायरे की छूट मिलती थी

मुक्त आवाजाही समझौते के तहत सीमा पर 16 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पर्वतीय आदिवासी लोगों को बिना किसी दस्तावेज के सीमा पार आने-जाने की छूट रहती थी। उन्हें इसके लिए सिर्फ एक बार्डर पास लेना पड़ता था, जो एक साल तक मान्य होता है। बार्डर पास पर आने वाला व्यक्ति बिना वीजा के एक बार में 15 दिन तक दूसरे देश में रह सकता था। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एफएमआर पालिसी को 2018 में शुरू किया गया था। लेकिन मणिपुर में नस्ली हिंसा के पीछे मुक्त आवाजाही एक प्रमुख वजह बन गई थी। मणिपुर घाटी में रहने वाले मैतेयी समुदाय ने अवैध घुसपैठ की वजह से सीमावर्ती राज्य में जनसांख्यिकी परिवर्तन किए जाने का आरोप लगाया है। म्यांमार से लगी सीमा को भारत में मुख्यत: ड्रग्स, सोने व हथियारों की तस्करी के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है।

दिल्ली लिंक रोड पर किसानों का आठ घंटे रहा कब्जा

नोएडा : तीन किसान संगठनों के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे और लिंक रोड पर आठ घंटे तक कब्जा रखा। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए नोएडा-दिल्ली को जोड़ने वाले सभी बार्डर पर बुधवार रात ही बैरिकेडिंग कर दी गई। इससे लोगों को दिनभर परेशान होना पड़ा। (पेज-2)

पाकिस्तान में आज सामने आएगी नई सरकार की तस्वीर

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में हिंसा के बीच आम चुनाव के लिए गुरुवार शाम मतदान पूरा हो गया और मतगणना शुरू हो गई, शुक्रवार दोपहर तक ज्यादातर परिणाम आने की उम्मीद है। चुनाव सर्वे में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) को आगे माना जा रहा है। नवाज को सेना का समर्थन माना जा रहा है। (पेज-11)

दिल्ली नगर निगम का बजट बिना पढ़े ही पास हुआ

नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम में वही हुआ, जिसकी आशंका थी। निगम इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब नेता सदन मुकेश गोयल बजट भाषण पढ़ भी नहीं पाए और हंगामे के बीच 2023-24 के संशोधित बजट अनुमान व 2024-25 के बजट अनुमानों को पारित करना पड़ा। (पेज-2)

हेमंत के दिल्ली आवास से जब्त कार के तार धीरज साहू से जुड़े

रांची : झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से जब्त बीएमडब्ल्यू कार का कनेक्शन राज्यसभा सदस्य धीरज साहू से जुड़ा है। ईडी ने पाया कि जब्त कार हेमंत की नहीं है। इसका संबंध झारखंड के कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू से है। कार का रजिस्ट्रेशन साहू के मानेसर स्थित घर के पते पर है। (पेज-6)

हल्द्वानी में बवाल, उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश

हल्द्वानी : उत्तराखंड के हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा में सरकारी भूमि पर बने अवैध मदरसा व नमाज स्थल को ध्वस्त करने गई पुलिस, प्रशासन व नगर निगम की टीम पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया। उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाने पर भी हमला कर दिया। महिला एसडीएम व एसपी समेत करीब 250 से अधिक लोग पथराव में चोटिल लोग अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं। तनावपूर्ण स्थिति को देख डीएम ने रात में ही कर्फ्यू लगाते हुए उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दे दिए हैं। (पेज-7)

गलत फास्टैग के लिए दंडित हों एजेंसियां : संसदीय समिति

नई दिल्ली: संसद की एक स्थाई समिति ने कहा है कि दोषपूर्ण फास्टैग के कारण होने वाली असुविधा के लिए लोगों को नहीं, जिम्मेदार एजेंसियों को दंडित करें। (पेज-3)

राहुल गांधी बोले, मोदी जन्म से ओबीसी नहीं, भाजपा का पलटवार

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं हैं। उन्हें ओबीसी गुजरात की भाजपा सरकार ने बनाया है। (पेज-4)

पिछड़े वर्गों को चुनिंदा तरीके से आरक्षण नहीं दे सकते राज्य

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोटे के भीतर कोटा प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देने में राज्य सरकारें चुनिंदा रवैया नहीं अपना सकतीं क्योंकि इससे यह तुष्टीकरण की खतरनाक प्रवृत्ति बन जाएगी। शीर्ष कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला देगा कि क्या राज्य सरकार को आरक्षण के लिहाज से एससी-एसटी में उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले में जो भी फैसला सुनाएगी, वह आने वाले समय में आरक्षण की दिशा और दशा तय करने वाला होगा। सात जजों की संविधान पीठ इसी मुद्दे पर 2004 में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में दिए गए पांच जजों के फैसले पर भी पुनर्विचार करेगी।

चिन्नैया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी-एसटी आरक्षण में राज्य सरकार को उप-वर्गीकरण करने का अधिकार नहीं है। सात सदस्यीय पीठ में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा भी शामिल हैं। पंजाब सरकार की ओर से एससी वर्ग में ज्यादा पिछड़े और ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए एससी वर्ग के उप-वर्गीकरण को सही ठहराया गया। केंद्र ने भी इस लिहाज से उप-वर्गीकरण को सही कहा। दूसरी ओर कई पक्षों ने एससी-एसटी वर्ग के उप-वर्गीकरण का विरोध किया और चिन्नैया मामले में दी गई व्यवस्था का समर्थन किया। गुरुवार को जब एक पक्षकार की ओर से राज्य द्वारा उप-वर्गीकरण किए जाने के विरोध में दलीलें दी जा रहीं थी, तब पीठ की अगुआई कर रहे प्रधान न्यायाधीश ने टिप्पणी की, मान लीजिए कि इस मामले में उन्होंने (राज्य सरकार ने) सिर्फ वाल्मीकियों को चुना और मजहबी सिखों को छोड़ दिया, तो क्या मजहबी यह तर्क नहीं दे सकते थे कि हम भी वाल्मीकियों की तरह पिछड़े हैं, आपने हमें क्यों छोड़ दिया। सीजेआइ ने कहा, हम सिर्फ वाल्मीकियों का उदाहरण दे रहे हैं, स्थिति इससे उलट भी हो सकती है। कहने का अर्थ यह है कि जिन लोगों को बाहर रखा गया है, वे हमेशा वर्गीकरण को अनुच्छेद-14 के तहत समानता के आधार पर चुनौती दे सकते हैं। लेकिन जवाब में राज्य कह सकता है कि हम पिछड़ेपन की स्थिति को देखकर जाति का वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसा जस्टिस गवई ने कहा। (**यह तुष्टीकरण की खतरनाक प्रवृत्ति बन जाएगी : पेज-13**)

विदाई

राज्यसभा ने 68 सांसदों को दी विदाई, इनमें भाजपा अध्यक्ष नड्डा सहित नौ मंत्री भी, कांग्रेस के स्याह पत्र को पीएम ने बताया काला टीका, कहा-उनके कामों को नजर न लगे इसलिए लाया गया

लोकतंत्र के प्रति मनमोहन सिंह की प्रतिबद्धता प्रेरणादायी : पीएम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में रिटायर्ड होने वाले सदस्यों के विदाई के मौके पर उन्हें शुभकामना दीं (स्क्रीन ग्रैब- संसद टीवी)। एएनआइ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की लोकतंत्र के प्रति निष्ठा की खूब सराहना की और कहा कि जब भी देश में लोकतंत्र की चर्चा होगी तब उनके योगदान को याद किया जाएगा। इस मौके पर व्हील चेयर से उनके संसद पहुंचने की घटना को भी याद किया। हालांकि पीएम मोदी कांग्रेस पर हमला करने से नहीं चूके और उनकी ओर से अपने दस सालों के काम-काज को लेकर लाए गए स्याह पत्र को काला टीका बताया।

पीएम मोदी राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे करीब 68 सदस्यों के विदाई के मौके पर बोल रहे थे। इनमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित मोदी सरकार के नौ मंत्री भी शामिल हैं। साथ ही इनमें वह पांच महिला सांसद भी शामिल हैं जो मौजूदा समय में राज्यसभा में उपसभापति के पैनल में हैं। इस मौके पर सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों ने राज्यसभा से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। सेवानिवृत्त होने वाले सभी सदस्यों को इस मौके पर शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राज्यसभा एक जीवंत विश्वविद्यालय है ऐसे में यहां से निकलने वाले सांसद जहां भी रहेंगे अपनी चमक बिखेरेंगे। वहीं, कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, हमारे यहां कोई बच्चा अच्छा काम करता है। अच्छे कपड़े पहन लेता है, तो उसे काला टीका कर दिया जाता है। आज देश दस साल में समृद्धि के नए शिखर को छू रहा है। एक भव्य-दिव्य वातावरण बना है। ऐसे में काला टीका लगाने का प्रयास किया है। ऐसे में खरगे जी ने जो प्रयास किया है, उसका स्वागत करता हूं। मैं सोच रहा था कि सब काले कपड़े में आएंगे, लेकिन वह स्याह पत्र तक ही आ पाए। राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को विदाई देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि उन्हें खुशी है कि पीएम मोदी कांग्रेस के जिन दस सालों के कार्यकाल को लेकर श्वेत पत्र लेकर आई है, उस कालखंड के पीएम रहे मनमोहन सिंह के कामों की उन्होंने सराहना भी की है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सरकार को विधेयकों को पारित करने में जल्दबाजी से बचना चाहिए।

पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे से पूछा- क्या आपकी पार्टी आपका पीएम बनना बर्दाश्त करेगी?

पूर्व प्रधानमंत्री व जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे से अपनी नजदीकियों का जिक्र करते हुए सवाल किया क्या आपकी पार्टी आपके पीएम बनने को बर्दाश्त करेगी। साथ ही भाजपा से दोस्ती के अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को जवाब भी किया और कहा कि कुछ कांग्रेसियों के हाथों अपनी पार्टी को बर्बाद होने से बचाने के लिए उन्होंने भाजपा का साथ पसंद किया। उन्होंने इस मौके पर यह दावा किया कि वह अपने बेटे की जगह कर्नाटक का मुख्यमंत्री खरगे को ही बनते देखना चाहते थे लेकिन कांग्रेस आलाकमान इससे सहमत नहीं हुआ और इस बात पर जोर दिया कि कुमारस्वामी को ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए।

****

आज का मौसम

सुबह में हल्की धुंध होगी

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
9 फरवरी	23.0	08.0
10 फरवरी	23.0	07.0
नोएडा		
9 फरवरी	19.0	07.0
10 फरवरी	21.0	08.0
गुरुग्राम		
9 फरवरी	21.0	08.0
10 फरवरी	21.0	09.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

दिल्ली के विकास में डीडीए का बड़ी भूमिका : उपराज्यपाल

नई दिल्ली : दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली के विकास में डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) की बड़ी भूमिका है। उपराज्यपाल, दक्षिणी दिल्ली सांसद रमेश बिधूड़ी और श्रीनिवासपुरी के पार्षद राजपाल सिंह ने गुरुवार को नेहरू प्लेस में स्काईवाक और नवीनीकरण कार्यों का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने कहा कि नेहरू प्लेस में बनाए गए स्काईवाक और अन्य कार्यों में करीब 75 करोड़ रुपये की लागत आई है। यह स्काईवाक शहर की सुंदरता को बढ़ाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि डीडीए न केवल शहरी क्षेत्रों के उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी में उपेक्षित गांवों के विकास के लिए भी काम कर रहा है। मौके पर डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा व आल नेहरू प्लेस डवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल मौजूद रहे। (जासं)

कारोबारी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत 13 तक बढ़ी

नई दिल्ली : आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत अदालत ने 13 फरवरी तक बढ़ा दी। ईडी द्वारा महेंद्रू की याचिका पर आवेदन का जवाब देने के लिए कुछ समय मांगे जाने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने अंतरिम जमानत बढ़ाते हुए 13 फरवरी को ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। महेंद्रू की अंतरिम जमानत नौ फरवरी को समाप्त होने वाली है। उससे पहले उसने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग कर तर्क दिया कि उसकी पत्नी को सर्जरी के बाद की जटिलताओं के कारण फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, महेंद्रू आबकारी नीति के उल्लंघन के प्रमुख लाभार्थियों में से एक था, क्योंकि वह न केवल एक मादक पेय-विनिर्माण इकाई चला रहा था, बल्कि उसे अपने रिश्तेदारों के नाम पर थोक लाइसेंस और कुछ खुदरा लाइसेंस भी दिए गए थे। (जासं)

हंगामे में बिना पढ़े ही पास हुआ बजट

दिल्ली नगर निगम का बजट : 400 करोड़ का अतिरिक्त प्रविधान कूड़ा प्रबंधन में महापौर के विवेकाधिकार फंड से

7000 करोड़ खर्च का प्रविधान किया गया वित्त वर्ष 2024-25 में कूड़ा प्रबंधन के मद में

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली नगर निगम में आखिर वही हुआ, जिसकी आशंका जताई जा रही थी। निगम इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब नेता सदन मुकेश गोयल बजट भाषण पढ़ भी नहीं पाए और हंगामे के बीच 2023-24 के संशोधित बजट अनुमान और 2024-25 के बजट अनुमानों को पारित करना पड़ा। नेता सदन ने हंगामे के चलते बजट भाषण को पढ़ा हुआ माने की मांग करते हुए कटमोशन (बजट संशोधन) को ध्वनि मत से पारित कराया। निगम बजट के आय और व्यय में निगमायुक्त द्वारा प्रस्तावित मद में कोई बदलाव नहीं किया गया है, हालांकि कटमोशन के तहत विभिन्न मदों के फंड में जोड़ा और घटाया है।

1000 करोड़ का प्रविधान सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए किया: बजट में सड़कों व गलियों के निर्माण और मरम्मत के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित बजट अनुमान व 2024-25 के बजट अनुमान भी 500-500 करोड़ रुपये के साथ महापौर का विवेकाधिकार फंड बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। कूड़ा प्रबंधन के मद में 6600 करोड़ के निगमायुक्त द्वारा प्रस्तावित राशि में 400 करोड़ रुपये बढ़ाने का प्रविधान किया गया है। अब वित्त वर्ष 2024-25 में निगम 7000 करोड़ रुपये की राशि खर्च का प्रविधान होगा। वर्ष 2022-23 में इस मद में मात्र 4173 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए थे।

निगम के बजट पर सोमवार से चर्चा शुरू हुई थी। मंगलवार को कटमोशन के प्रस्तावों की सूचना जैसे ही विपक्ष को लगी, तो भाजपा ने विरोध करना शुरू कर दिया था।

मंगलवार और बुधवार को दोनों ही दिन निगम के बजट पर चर्चा नहीं हो पाई थी। हंगामे की वजह से बजट बैठक स्थगित हो गई थी। ऐसे में आप सरकार को पहले से ही बजट के दौरान हंगामे की आशंका थी। इसलिए आप की महिला पार्षद पहले ही महापौर के आसन पर घेरा बनाकर खड़ी हो गई थीं।

महापौर डा. शैली ओबेराय जैसे ही सदन में पहुंचीं भाजपा पार्षद भी महापौर के आसन के सामने आ गए। कटमोशन में महापौर का विवेकाधिकार फंड बढ़ाने के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग करने लगे। इस बीच नेता सदन मुकेश गोयल ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया, लेकिन शोर-शराबे के बीच बजट भाषण पढ़ना संभव नहीं हो पा रहा था। इसे देखते हुए उन्होंने सदन से बजट भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए कि गुजारिश करते हुए कटमोशन को हंगामे के बीच पास कराया। इसमें सत्ता पक्ष द्वारा किए गए कटमोशन के प्रस्तावों को पारित कर दिया गया। जबकि विपक्ष के सभी कटमोशन प्रस्तावों को निरस्त कर दिया। निगम बजट में कोई भी नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं है। न ही विकास परियोजना की कोई घोषणा की गई है।

नया कर का प्रस्ताव नहीं, गत वर्ष की भांति रहेंगी टैक्स दरें

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023-24 का बजट	2023-24 का संशोधित बजट	2024-25 का बजट अनुमान
प्रारंभिक जमा	508.23	1275.52	1004
आय	15523.96	15952.52	15686.99
व्यय	16024.46	16224.05	16683.02
जमा शेष	7.73	1004	7.97

(नोट : राशि करोड़ रुपये में)

पेशेवर कर लगाने का प्रस्ताव निरस्त

निगम के बजट में नेता सदन मुकेश गोयल ने कोई भी नया कर न लगाने की घोषणा की है। इससे निगमायुक्त ज्ञानेश भारती द्वारा नौ दिसंबर को पेश किए गए बजट में प्रस्तावित पेशेवर कर लगाने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। गोयल ने कहा कि हम बिना नया कर लगाए जनता के कार्य करेंगे।

सिविक सेंटर में हंगामे के बीच नगर निगम का बजट पास हुआ। एक ओर भाजपा पार्षद विरोध कर रहे थे तो दूसरी ओर आप पार्षदों ने महापौर के आसन के पास जाकर समर्थन में नारे लगाए। हरीश कुमार

बजट में निगम एक्ट की अवेहलना पर भाजपा ने की एलजी से शिकायत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

निगम सदन में आप सरकार द्वारा पारित बजट में निगम एक्ट की अवेहलना का आरोप लगा भाजपा ने एलजी वीके सक्सेना से शिकायत की है। नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह के नेतृत्व में पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने राजनिवास को दी शिकायत में लिखा है कि निगम के अंदर सरेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। महापौर डा. शैली ओबेराय ने सदन में प्रस्ताव बिना चर्चा के पास कर 10 करोड़ रुपये के अपने विवेकाधिकार फंड को 1500 करोड़ कर लिया है।

नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने कहा, देश में कोई भी निगम ऐसा नहीं है, जहां महापौर को 1500 करोड़ रुपये के आवंटन की शक्ति हो, जबकि संवैधानिक समितियां चाहे वह स्थायी समिति हो या फिर शिक्षा समिति और वार्ड समितियां हो उन सभी की शक्तियों को महापौर लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य कर रही है। राजा इकबाल ने कहा कि भाजपा बजट पर चर्चा करना चाहती थी, लेकिन आप पार्षद पहले से ही हंगामे के बीच इसे पास कराना चाहते थे। इसलिए नेता सदन और महापौर का घेरा आप पार्षदों ने बना लिया था। निगम की आप सरकार ने दिल्ली के नागरिकों को करों में कोई भी रियायत नहीं दी है। साथ ही आम माफी योजना की भी कोई घोषणा नहीं की गई है। भाजपा का कहना है कि आप सरकार ने निगमायुक्त व निगम सचिव की गैरमौजूदगी में बजट को पारित कराया, जो गैरकानूनी एवं निगम एक्ट 1957 की अवहेलना है।

भाजपा ने बजट के दौरान किया हंगामा : मुकेश गोयल

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम के नेता सदन मुकेश गोयल द्वारा पेश बजट पारित होने के बाद उन्होंने भाजपा पर हंगामा करने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने 15 साल के कार्यकाल की पोल खुलने के डर से निगम सदन में हंगामा कर रही थी। बजट को हंगामे के बीच पारित करना पड़ा। नेता सदन ने कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई 10 गारंटी को पूरा करने का हमने जनता से वादा किया है। इसे पूरा करेंगे।

असंवैधानिक तरीके से मेयर ने बजट पारित कराया : कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: निगम में सदन के पूर्व नेता व कांग्रेस के एमसीडी प्रभारी जितेन्द्र कोचर ने निगम में असंवैधानिक तरीके से बजट पारित करने की आलोचना की। कहा, निगम ने जहां अनधिकृत कालोनियों, शिक्षा, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, स्वच्छता कमेटियों, लैंड स्कैपिंग के लिए आवंटित बजट को तो कम किया ही है, वहीं अनधिकृत कालोनियों व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का बजट घटाकर महापौर द्वारा अपना विवेकाधिकार फंड बढ़ाना गरीबों निवासियों को धोखा देने जैसा है।

गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन का हिस्सा गिरा, एक की मौत, चार घायल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- सड़क पर स्कूटी और मोटरसाइकिल सवारों पर गिरा मेट्रो स्टेशन के स्लैब का मलबा
- दिल्ली मेट्रो ने दो अधिकारियों को किया निलंबित, मृतक के स्वजन व घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा
- दिल्ली सरकार ने विशेषज्ञ समिति गठित कर घटना की जांच कराने के लिए निर्देश

गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे फैला मलबा व लटका हुआ स्लैब का भाग। वीडियो ग्रैब

दीवार गिरने पर गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे मलबे में दबा वाहन सवार। वीडियो ग्रैब

स्लैब के बाहरी हिस्से पर लगी थी शीट

स्लैब के बाहरी हिस्से में शीट लगी थी, जिससे पता नहीं चल पा रहा था कि इसमें कोई दरार है। दिल्ली मेट्रो का कहना है कि जांच के बाद ही हादसे का कारण स्पष्ट हो पाएगा। स्लैब में दरार की कभी शिकायत नहीं मिली थी।

चार घंटे परिचालन बाधित

हादसे के बाद गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन पर मौजपुर से शिव विहार के बीच मेट्रो परिचालन 11.04 बजे से लेकर 11.23 बजे तक बंद कर दिया गया। इसके बाद मौजपुर से शिव विहार के बीच सिंगल लाइन पर मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ, लेकिन गोकलपुरी स्टेशन को बंद रखा गया। मौजपुर से शिव विहार के लिए मेट्रो भी देरी से मिल रही थी। गोकलपुरी स्टेशन पर घटनास्थल के पास बैरिकेडिंग के बाद दोपहर 2.53 बजे से मेट्रो परिचालन सामान्य हुआ।

मृतक के स्वजन को 25 लाख रुपये मुआवजा

डीएमआरसी ने मृतक के स्वजन और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक (जनसंपर्क) अनुज दयाल ने बताया, मृतक के स्वजन को 25 लाख, गंभीर रूप से घायलों को पांच लाख व मामूली घायल हुए लोगों को को एक-एक लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा।

दिल्ली मेट्रो के सबसे बड़े कारिडोर पिंक लाइन (मजलिस पार्क-मौजपुर-शिव विहार) के गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन के स्लैब का हिस्सा ढहने से एक शख्स की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान करावल नगर निवासी विनोद कुमार के रूप में हुई।

घायलों में लोनी के रहने वाले अजीत कुमार और मो. ताजिर और गोकलपुरी के रहने वाले संदीप और मोनू शामिल हैं। घायलों के हाथ व पैर में फ्रैक्चर हैं। सभी को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली मेट्रो के इतिहास में इस तरह की यह पहली घटना है। इससे डीएमआरसी की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। गोकलपुरी थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ लापरवाही से मौत व दूसरों के जीवन को खतरे में डालने सहित कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि ठेकेदार का पता लगाया जा रहा है। नाम का पता चलते ही प्राथमिकी में जोड़ दिया जाएगा। वहीं, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने भी घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद स्टेशन के ढांचे के रखरखाव से संबंधित सिविल विभाग के प्रबंधक और जूनियर इंजीनियर को प्राथमिक तौर पर घटना का जिम्मेदार मानते हुए तत्काल निलंबित कर दिया गया है। वहीं, दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने डीएमआरसी को विशेषज्ञ कमेटी गठित कर मामले की जांच कराने और एक निश्चित अवधि में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि डीएमआरसी ने जांच रिपोर्ट देने का समय नहीं बताया है। रिपोर्ट आने की अवधि तय होनी चाहिए। जिला पुलिस उपायुक्त डा. जाय टिर्की ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह 11:04 बजे हादसा हुआ। स्टेशन के प्लेटफार्म (अप) के निचले हिस्से के स्लैब का मलबा सड़क पर गिरने लगा। इस दौरान सड़क से गुजर रहे दो स्कूटी व दो मोटरसाइकिल सवार इसकी चपेट में आ गए। विनोद कुमार स्कूटी पर सवार थे। स्टेशन के बगल में ही गोकलपुर व दयालपुर थाना है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची साथ ही अग्निशमन विभाग व एंबुलेंस को भी सूचना दी गई। अग्निशमनकर्मी की मदद से मलबा हटाकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सभी मेट्रो कारिडोर की होगी सुरक्षा जांच

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन की घटना के बाद दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने दिल्ली मेट्रो के सभी कारिडोर की सुरक्षा जांच करने का निर्देश दिया है। अधिकारी सर्वे कर पता लगाएंगे कि ढांचे में किसी तरह की खामी तो नहीं है। खामी पाए जाने पर उसे दूर करने लिए डीएमआरसी आवश्यक कदम उठाएगा। एनसीआर में मेट्रो की कुल 12 लाइनें हैं और नेटवर्क की कुल लंबाई 393 किलोमीटर व 288 मेट्रो स्टेशन हैं। इसमें गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो व नोएडा की एक्वा लाइन शामिल है। एनसीआर में दिल्ली मेट्रो का अपना नेटवर्क करीब 350.42 किलोमीटर है, जिस पर कुल 256 मेट्रो स्टेशन हैं। पिंक लाइन व मर्जेंटा लाइन का निर्माण फेज तीन में हुआ था। इन दोनों कारिडोर को बने करीब छह वर्ष ही हुए हैं। दिल्ली मेट्रो की सबसे पुरानी रेड लाइन का बड़ा हिस्सा 23 वर्ष पुराना हो चुका है। इस कारिडोर के स्टेशनों का कोरोना के दौरान नवीनीकरण हुआ था। स्टेशनों व कारिडोर के बुनियादी ढांचे, मेट्रो ट्रैक, सिग्नल सिस्टम, ओएचई की सुरक्षा जांच की जाएगी।

जैसे देश का सबसे बड़ा आतंकी मैं ही हूं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- ईडी के नोटिस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने साधा निशाना
- कहा-केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों के विरुद्ध छेड़ रखा है युद्ध

जंतर-मंतर पर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन में शामिल (दांए से बाएं) वामदल नेता डी राजा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, वामदल नेता सीताराम येचुरी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जागरण

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नोटिस को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। कहा कि हमें रोकने के लिए केंद्र ने इतने केस कर दिए, कभी ईडी का तो कभी सीबीआइ का नोटिस आ गया। मुझे तो समझ में नहीं आता, जैसे देश का सबसे बड़ा आतंकी मैं ही हूं।

केजरीवाल गुरुवार को द्वारका सेक्टर-एक में सरकारी स्कूल भवन के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर का एक-एक कतरा देश को समर्पित है। बोले, वे (केंद्र सरकार) मुझे चोर कहते हैं, मेरा सवाल है कि फ्री बिजली पानी देने वाला चोर होता है या महंगी बिजली देने वाला। इलाज मुफ्त कराने वाला चोर है या महंगा करने वाला? मनीष सिसोदिया को भी उन लोगों ने चोर कहा, जबकि मनीष ने गरीब बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनाए। उनको भविष्य दिया।

आप संयोजक केजरीवाल केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन की ओर से केंद्र सरकार के विरुद्ध जंतर-मंतर पर आयोजित धरना-प्रदर्शन में भी शामिल हुए। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। केजरीवाल ने विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों के खिलाफ भाजपानीत केंद्र सरकार पर युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया। कहा कि विपक्ष शासित राज्य सरकारों को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार सभी हथकंडे अपना रही है। उसने भारत-पाकिस्तान वाली स्थिति कर दी है। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष शासित सरकारों के कामकाज में राज्यपालों के माध्यम से हस्तक्षेप कर रही है। विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है, अब मुझे और पी. विजयन को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ईडी उनका नया हथियार है। इस मौके पर भाकपा नेता डी राजा व माकपा नेता सीताराम येचुरी के साथ ही जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। एक दिन पहले बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन किया था।

दिल्ली लिंक रोड पर किसानों का आठ घंटे रहा कब्जा

जागरण संवाददाता, नोएडा

- चिल्ला बार्डर से तीन किलोमीटर पहले ही रोक दिए गए किसान
- मांगों को लेकर उच्चस्तरीय कमेटी बनाने का मिला आश्वासन

दिल्ली कूच करने से पुलिस द्वारा बैरिकेट लगाकर रोके जाने के बाद दिल्ली-नोएडा लिंक रोड स्थित दलित प्रेरणा स्थल के सामने सड़क पर बैठे किसान। जागरण

किसानों की प्रमुख मांगें

- 1997 के बाद के सभी किसानों को बढ़ी दर से मुआवजा दें। चाहे वह कोर्ट गए हो या नहीं गए हो।
- किसानों को उनकी जमीन का 10 प्रतिशत प्लाट आबादी में दिया जाए।
- रेगुलेशन की 450 वर्गमीटर सीमा को बढ़ाकर 1,000 प्रति वर्गमीटर किया जाए।
- मकानों की ऊंचाई को बढ़ाए जाने की अनुमति दी जाए।
- 5 प्रतिशत प्लाट पर व्यावसायिक गतिविधियां चलने की अनुमति दी जाए।
- गांवों में पुस्तकालय बनाए जाएं।

एनटीपीसी से 24 गांवों के किसानों की मांगें

- एक समान दर से मुआवजा दिया जाए।
- बच्चों के लिए स्कूल और एनटीपीसी में नौकरी दी जाए।
- एनटीपीसी से प्रभावित सभी किसानों को उनकी जमीन का 10 प्रतिशत प्लाट आबादी में दी जाए।
- एनटीपीसी दादरी के 5 किमी के दायरे में रहने वाले भूविस्थापित को फ्री में बिजली दी जाए।
- 200 बेड का अस्पताल बनाया जाए। दादरी में 4 डिग्री कालेज खुलवाया जाए।

तीन किसान संगठनों के बैनर तले किसानों ने मांगों को लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे और लिंक रोड पर आठ घंटे तक कब्जा रखा। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए नोएडा-दिल्ली को जोड़ने वाले सभी बार्डर पर बुधवार रात ही बैरिकेडिंग कर दी गई। ग्रेटर नोएडा से आगे बढ़े किसानों से महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-18 फ्लाईओवर तक तीन बार पुलिस प्रशासन ने वार्ता की।

चिल्ला बार्डर से करीब तीन किलोमीटर पहले ही उनको बैरिकेड लगाकर रोक लिया गया। इस बीच किसानों ने प्रयास किया, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। सुबह करीब 10:30 बजे नोएडा-दिल्ली लिंक रोड बंद होने के कारण नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे, डीएनडी और कालिंदी कुंज से दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। देर शाम करीब साढ़े छह बजे उच्चस्तरीय कमेटी बनाने और एक सप्ताह में प्राधिकरण व प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ वार्ता कराने के पुलिस कमिश्नर के आश्वासन के बाद किसानों ने प्रशासन को सात दिन का समय दिया और सड़क खाली की। हालांकि किसान नोएडा प्राधिकरण और एनटीपीसी सेक्टर-24 पर धरना जारी रखेंगे। सुबह करीब 10 बजे ग्रेटर नोएडा से चले किसानों को वहीं रोक दिया गया। बादलपुर गांव के किसानों को हिरासत में लेकर अंबेडकर पार्क में भेजा गया। साढ़े 12 बजे एनटीपीसी पर धरनारत किसानों को बैरिकेड कर रोक दिया गया।

उच्चस्तरीय कमेटी गठन का मिला आश्वासन : किसान संगठन अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस कमिश्नर की तरफ से आश्वासन मिला है। एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया जा रहा है। कमेटी में औद्योगिक मंत्री, आइडीसी चेयरमैन मनोज सिंह, एसीएस एसपी गोयल, तीनों प्राधिकरण के सीईओ, पुलिस आयुक्त और जिले के जनप्रतिनिधि शामिल रहेंगे। एनटीपीसी के लिए किसानों के साथ पावर सेक्रेट्री और सीएमडी बैठक करेंगे।

आयोजन

प्रगति मैदान के हाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में होगा आयोजित, मेले में अतिथि देश के रूप में होगा सम्मिलित सऊदी अरब

विश्व पुस्तक मेला कल से, दिखेगी बहुभाषी भारत की झलक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

विश्व पुस्तक मेले की पत्रकार वार्ता को संबोधित करते राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक युवराज मलिक साथ मौजूद न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलिंद मराठे (बाएं) व सऊदी अरब के प्रतिनिधि अब्दुल लतीफ। जागरण

साहित्य प्रेमियों का इंतजार खत्म होने वाला है। 51वां विश्व पुस्तक मेला शनिवार से शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) और भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आइटीपीओ) के संयुक्त तत्वावधान में प्रगति मैदान के हाल नंबर एक, दो, तीन, चार व पांच में पुस्तक मेला लगेगा। शुभारंभ भारत मंडपम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। मेले में सऊदी अरब अतिथि देश के रूप में सम्मिलित होगा। उद्घाटन के मौके पर सऊदी अरब के राजदूत भी उपस्थित होंगे।

गुरुवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में एनबीटी के अध्यक्ष प्रो. मिलिंद मराठे ने बताया कि इस बार की थीम है- बहुभाषी भारतः एक जीवंत परंपरा। थीम मंडप के साथ-साथ बाल मंडप भी आकर्षण का केंद होगा। मेले में सभी के लिए किताबें होंगी। देश-विदेश के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। एनबीटी के निदेशक युवराज मलिक ने बताया कि उद्घाटन समारोह में ही राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय लांच किया जाएगा। पहले चरण में इस पर विजुअल बुक्स उपलब्ध होंगी, फिर चरणबद्ध तरीके से सभी किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। नेत्रहीनों के लिए कुछ ब्रेल बुक्स भी लांच होंगी। युवराज मलिक ने बताया कि हाल नं. पांच खास आकर्षण का केंद्र रहेगा। यहां थीम मंडप में जम्मू कश्मीर का इतिहास, वर्तमान व वहां की संस्कृति बयां करती प्रदर्शनी होगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की एक झांकी भी होगी। हाल नंबर चार में विदेशी मंडप होगा, तीन नंबर हाल बच्चों के लिए रहेगा। हाल नं. दो में बहुभाषी भारत की झलक मिलेगी जबकि हाल नं. एक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की किताबें मिलेंगी।

मेले में शामिल होंगे 14 देश

मेले में एक हजार से अधिक प्रकाशक और दो हजार से अधिक बुक स्टाल होंगे। विदेशों से सऊदी अरब के अलावा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, तुर्की, इटली, रूस, ताइवान, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, आस्ट्रिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल सहित 14 देश भाग ले रहे हैं। पाकिस्तान इस बार भी नहीं होगा। 45 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में आयोजित होने जा रहे इस मेले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी फोकस होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम एम्फी थियेटर में होंगे।

वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों को निशुल्क प्रवेश : 18 फरवरी तक चलने वाले मेले में स्कूली बच्चे, वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों को निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। टिकट दर बच्चों के लिए 10 रुपये व व्यस्क के लिए 20 रुपये रखी गई है। मेला सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा। मेले के टिकट www.itpoonline.gov.in पर आनलाइन खरीद सकते हैं।

****

पूर्व कोयला सचिव समेत दो के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कोल ब्लाक आवंटन मामले में अदालत ने कान्टिस्टील लिमिटेड, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और पूर्व संयुक्त सचिव केएस क्रोफा के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि झारखंड में स्थित कोल ब्लाक हुटार और हुरिलोंग से संबंधित कोयला ब्लाक आवंटन मामले में पांच मार्च को आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे।

विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने कहा कि कंपनी के खिलाफ गंभीर अपराध का आरोप है। इसके अलावा, एचसी गुप्ता और केएस क्रोफा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ठोस अपराध का आरोप बनता है। घटनाओं का कालक्रम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आरोपितों के कृत्यों में सह-संबंध और सुसंगतता थी। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय से धोखाधड़ी कर कोल ब्लाक आवंटन के लिए पांच अगस्त 2008 का प्रस्ताव पत्र प्राप्त कर लिया गया। सरकारी कर्मचारियों ने निजी व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। कोर्ट ने कहा कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां साजिश का आरोप भी बनता है। अदालत के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि गुप्ता और क्रोफा ने प्रकाशित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया और कोल ब्लाकों के आवंटन के लिए अयोग्य कंपनी की सिफारिश की गई। अदालत के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया गया कि एचसी गुप्ता ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को भी गुमराह किया था कि इस कंपनी की झारखंड राज्य ने जोरदार सिफारिश की है, जबकि झारखंड ने इस कंपनी को कोल ब्लाक आवंटन का विरोध किया था।

496 उड़ानें रद्द की गईं और 8038 उड़ानें विलंबित हुईं जनवरी माह में कोहरे के कारण। सरकार ने कम दृश्यता की स्थिति में काम करने के लिए प्रशिक्षित पायलटों की नियुक्ति नहीं करने पर स्पाइसजेट, एयर इंडिया और इंडिगो को 31 जनवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

मालदीव में सैन्य कर्मियों की जगह तकनीकी कर्मी भेजेगा भारत

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल बोले, महत्वपूर्ण विकास साझीदार बना रहेगा भारत

इस वर्ष के अंतरिम बजट में विकास के लिए 600 करोड़ का आवंटन

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि मालदीव में दो हेलीकाप्टरों और एक एयरक्राफ्ट का संचालन कर रहे सैन्य कर्मियों के स्थान पर भारत सक्षम भारतीय तकनीकी कर्मियों को भेजेगा। साथ ही भारत इस द्वीपीय देश का महत्वपूर्ण विकास साझीदार बना रहेगा।

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु ने सोमवार को कहा था कि भारतीय सैन्य कर्मियों का पहला दल 10 मार्च तक और बाकी सैन्य कर्मी 10 मई से पहले वापस चले जाएंगे। वर्तमान में मालदीव में भारत के 80 सैन्य कर्मी तैनात हैं। चीन समर्थक मोइज्जु ने राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद कहा था कि वह भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस भेजने का अपना चुनावी वादा पूरा करेंगे। पिछले वर्ष नवंबर में मुइज्जु के पदभार संभालने के बाद भारत-मालदीव के संबंधों में कुछ तनाव आ गया था।

भारत की विकास सहायता के तहत मालदीव को बजटीय आवंटन पर जायसवाल ने कहा कुछ राशि आवंटित की गई थी और इसे संशोधित किया जा सकता है। 2023-24 के लिए मालदीव को 400 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया था, लेकिन संशोधित अनुमान बताते हैं कि यह बढ़कर 770.90 करोड़ तक पहुंच गया। 2024-25 के अंतरिम बजट में मालदीव के विकास के लिए 600 करोड़ रुपये रखे गए हैं। जायसवाल ने कहा कि आगे की प्रगति पर स्पष्टता होने पर नई धनराशि को संशोधित किया जा सकता है।

रणधीर जायसवाल। फाइल

'म्यांमार के रखाइन प्रांत में सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक'

म्यांमार के मुद्दे पर **रणधीर** जायसवाल ने कहा, 'रखाइन प्रांत में स्थिति चिंताजनक है। हमने अपने नागरिकों को रखाइन छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है और जो वहां जाने की योजना बना रहे हैं, उनसे वहां नहीं जाने को कहा है।' उन्होंने कहा कि रखाइन प्रांत में रह रहे भारतीयों की सही संख्या के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। जायसवाल ने कहा, 'सित्तवे में हमारा वाणिज्य दूतावास है। सुरक्षा स्थिति का हमारे वाणिज्य दूतावास पर असर पड़ सकता है। हम हालात पर नजर रख रहे हैं और देखेंगे कि इससे कैसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से निपटा जा सकता है।' म्यांमार की सीमा पर स्थिति को गंभीर बताते हुए उन्होंने और कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया।

कनाडा के चुनावों में हस्तक्षेप के आरोपों को भारत ने नकारा

नई दिल्ली, एएनआइ : कनाडा के चुनावों में भारतीय हस्तक्षेप के आरोपों को विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को आधारहीन बताकर खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि कनाडा ही भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने वे मीडिया रिपोर्टें देखी हैं जिसमें कनाडा के एक आयोग द्वारा चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप की जांच किए जाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा, 'कनाडा के चुनावों में भारतीय हस्तक्षेप के ऐसे आधारहीन आरोपों को हम दृढ़ता से खारिज करते हैं।

भारत सरकार की नीति दूसरे देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की नहीं है, बल्कि इसके उलट

विदेश मंत्रालय ने कहा, कनाडा ही भारत के आंतरिक मामलों में करता है हस्तक्षेप

कनाडा ही हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता रहा है।' जायसवाल ने जोर देकर कहा कि भारत लगातार कनाडा से उसकी प्रमुख चिंताओं का निवारण करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए कहता रहा है।

उन्होंने कहा, 'हम उनके साथ नियमित तौर पर यह मुद्दा उठाते रहे हैं।' कनाडाई मीडिया के मुताबिक, कनाडा का विदेशी हस्तक्षेप की जांच का संघीय आयोग देश के पिछले दो आम चुनावों में भारत के कथित दखल की जांच कर रहा है। आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने संघीय सरकार से इन आरोपों से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है।

जल प्रदूषण से जुड़े छोटे मामले अपराध से बाहर करने वाला बिल पारित

नई दिल्ली, प्रेट्र : जल प्रदूषण से जुड़े छोटे-मोटे मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और औद्योगिक संयंत्रों की कुछ श्रेणियों को वैधानिक प्रतिबंधों से छूट प्रदान करने वाला विधेयक गुरुवार को संसद से पारित हो गया।

लोकसभा में जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, विधेयक के प्रविधानों से जल प्रदूषण से जुड़े विभिन्न मुद्दों से निपटने में ज्यादा पारदर्शिता आएगी। जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन के लिए लाए गए इस विधेयक को राज्यसभा ने मंगलवार को पारित किया था। चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि विधेयक के प्रविधान पर्यावरण संरक्षण कानूनों या संघीय ढांचे को कमजोर करने का प्रयास हैं पर यादव ने कहा, 1974 के कानून में कड़े प्रविधान थे जिनमें छोटे-मोटे प्रविधानों के लिए जेल की सजा शामिल है।

विधेयक के उद्देश्यों व कारणों के अनुसार, संशोधन में आपराधिक प्रविधानों को तार्किक बनाने और यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया गया है कि नागरिक, कारोबारी व कंपनियां छोटी-मोटी, तकनीकी या प्रक्रियागत गलतियों के लिए कारावास की सजा से डरे बिना काम कर सकें। साथ ही किसी अपराध के दंडात्मक परिणाम की प्रकृति अपराध की गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिए। 1974 के कानून के मुताबिक, ऐसा कोई भी उद्योग या ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) की अनुमति अनिवार्य है जो सीवेज को प्रवाहित कर सकता है।

संसद प्रश्नोत्तर

2024 के आखिर तक तैयार हो जाएगा जेवर हवाईअड्डा : सिंधिया

नई दिल्ली, प्रेट्र: नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि नोएडा के जेवर में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा इस साल के अंत तक परिचालन के लिए तैयार हो जाएगा। सिंधिया ने यह भी कहा कि भारत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के मामले में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा विमानन बाजार है। 2030 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन जाएगा। सिंधिया ने कहा, उत्तर प्रदेश में छह हवाईअड्डे थे। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद हमने राज्य में चार और हवाईअड्डे बनाए हैं। जल्द ही पांच और हवाईअड्डे तैयार हो जाएंगे। इस साल के अंत तक जेवर एयरपोर्ट भी परिचालन के लिए तैयार हो जाएगा।

ज्योतिरादित्य सिंधिया। फाइल

इस वर्ष के अंत तक उत्तर प्रदेश में 16 हवाईअड्डे होंगे। सिंधिया ने कहा कि 2014 से पहले देश में सिर्फ 74 हवाईअड्डे थे और अब यह संख्या 149 हो गई है। यात्रियों की संख्या भी कई गुना बढ़ गई है। कुछ वर्षों में देश में घरेलू विमान यात्रियों की संख्या 30 करोड़ तक पहुंच जाएगी।

जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली के लिए सलाहकार नियुक्त

नई दिल्ली, प्रेट्र: राष्ट्रीय राजमार्गों पर जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू करने के लिए सरकार सलाहकार नियुक्त कर चुकी है। हालांकि यह प्रणाली फास्टैग के साथ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जाएगी।

नितिन गडकरी। फाइल

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में सवाल के लिखित जवाब में बताया कि शुरुआत में जीएनएसएस आधारित इलेक्ट्रानिक टोल कलेक्शन (ईटीसी) राष्ट्रीय राजमार्गों के चयनित खंडों पर शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) फास्टैग यूजर्स को आरबीआइ के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपनी केवाईसी को पूरा करने के प्रति जागरूक कर रही है। इस पहल का उद्देश्य टोल प्लाजा पर लोगों को असुविधा से बचाना है।

चेन्नई-बेंगलुरु ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को दिसंबर तक पूरा करने का प्रयास

गडकरी ने गुरुवार को कहा कि चेन्नई-बेंगलुरु ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के इस साल दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद चेन्नई से बेंगलुरु तक की दूरी महज दो घंटे में तय की जा सकेगी। लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए गडकरी ने कहा कि मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम दिसंबर से पहले एक्सप्रेसवे को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु और केरल सरकार से परियोजना के लिए निर्माण सामग्री उपलब्ध करा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की सहायता करने का अनुरोध किया।

सिल्क्यारा सुरंग मामले में एनएचआइडीसीएल को नोटिस

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि गत वर्ष हुए सिल्क्यारा-बारकोट सुरंग का एक हिस्सा ढहने के मामले की जांच के लिए गठिति विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट के आधार पर एनएचआइडीसीएल के डीपीआर सलाहकार, प्राधिकरण इंजीनियर, ईपीसी ठेकेदार, परियोजना निगरानी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

40 जिलों के मुख्यालय हाइवे से जोड़े जाने शेष

केंद्र सरकार अब तक 766 में 40 जिलों के मुख्यालयों को राष्ट्रीय राजमार्गों से नहीं जोड़ सकी है। इनमें तेलंगाना में सर्वाधिक छह जिले हैं और इसके बाद मध्य प्रदेश में पांच व राजस्थान के चार जिले शामिल हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि गत पांच वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति 30 किमी प्रति दिन रही।

संसद ने पारित किया अंतरिम बजट

नई दिल्ली, प्रेट्र : वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट को संसद ने गुरुवार को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने वित्त विधेयक 2024 और विनियोग विधेयक पारित कर लोकसभा को लौटा दिए। जम्मू-कश्मीर से संबंधित विनियोग विधेयक भी पास कर लोस को लौटा दिया। बजट पर चर्चा व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद विधेयकों को लोकसभा में लौटाया गया। लोकसभा ने बुधवार को इन विधेयकों को पास किया था। राज्यसभा द्वारा इन सभी विधेयकों को लोस को लौटाने के साथ बजट पारित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

निर्मला सीतारमण। फाइल

12 हजार करोड़ की छह रेल परियोजनाओं को मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र: आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने लगभग 12,343 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली रेल मंत्रालय की छह परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने आठ स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को भी मंजूरी दी है। इसका आधार मूल्य 96,317.65 करोड़ रुपये रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों की सराहना की और कहा कि रेलवे परियोजनाओं की मंजूरी से बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। इससे व्यस्त मार्गों पर भीड़ कम होगी और कारोबार के साथ-साथ कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट किया-राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नगालैंड में 12,343 करोड़ रुपये की छह मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद। सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से परिचालन में आसानी होगी और भीड़भाड़ कम होगी। इससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक ढांचागत विकास होगा। सरकार ने कहा कि ये रेल परियोजनाएं छह राज्यों के 18 जिलों को कवर करेंगी। इन परियोजनाओं से रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 1,020 किमी का विस्तार होगा और यह लगभग तीन करोड़ मानव दिवस रोजगार प्रदान करेंगी।

नरेन्द्र मोदी। फाइल

छह राज्यों से जुड़ी हैं रेल मंत्रालय की परियोजनाएं

पीएम मोदी ने कहा, व्यस्त मार्गों पर कम होगी भीड़

96,317 करोड़ के आधार मूल्य पर स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 96,317.65 करोड़ रुपये के आधार मूल्य पर मोबाइल फोन सेवाओं के लिए आठ स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को मंजूरी दे दी। दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कुछ दूरसंचार कंपनियों के पास मौजूद स्पेक्ट्रम को भी इस नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा। इन स्पेक्ट्रम की अवधि इसी साल खत्म हो रही है। 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए रखे जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सेवा प्रदाता दूरसंचार सेवाओं में व्यवधान को रोकने के लिए अंतरिम अवधि के दौरान नीलामी-निर्धारित कीमतों का भुगतान करके स्पेक्ट्रम का उपयोग जारी रख सकते हैं। कैबिनेट की यह मंजूरी पांच सर्किलों में भारती एयरटेल के स्पेक्ट्रम की समाप्ति से ठीक एक दिन पहले आई है।

'73.93% ग्रामीण घरों में नलों से पानी की आपूर्ति'

नई दिल्ली, प्रेट्र: जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत चार फरवरी तक देश के 19.27 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 14.24 करोड़ (73.93 प्रतिशत) से अधिक परिवारों के घरों में नल से पानी की आपूर्ति हो रही है। शेष परिवारों को भी समय-सीमा के भीतर आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की संभावना है।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में सवाल के जवाब में बताया कि जल जीवन मिशन के शुरू होने के बाद से ग्रामीण घरों तक नल से पानी पहुंचाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जेजेएम की घोषणा के समय 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों में नल से जल की आपूर्ति हो रही थी। अब 11.01 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल से पानी मुहैया कराया जा रहा है।

नमामि गंगे कार्यक्रम में 457 में से 280 परियोजनाएं पूर्ण: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर तक 38,438.05 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 457 परियोजनाओं में से 280 पूरी हो चुकी हैं अथवा शुरू हो चुकी हैं। नदी में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषण का मुख्य कारण होने की वजह से अधिकांश परियोजनाएं सीवेज बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित हैं। यह जानकारी जलशक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडु ने लोकसभा में लिखित जवाब में दी।

गजेंद्र सिंह शेखावत। फाइल

घरेलू सौर उद्योग में सिंगापुर, ब्रिटेन मारीशस शीर्ष तीन एफडीआई स्रोत: गत तीन वर्षों में घरेलू सौर उद्योग में 3,860 करोड़ डालर के कुल निवेश में सिंगापुर, ब्रिटेन और मारीशस शीर्ष तीन योगदानकर्ता हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने लोकसभा में बताया कि सिंगापुर से विदेश प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) 78.07 करोड़ डालर, ब्रिटेन का 77.82 करोड़ डालर और मारीशस का 63.25 करोड़ डालर रहा। इसके अतिरिक्त संयुक्त अरब अमीरात से 54.32 करोड़ डालर, नीदरलैंड्स से 25.61 करोड़ डालर, जापान से 20.07 करोड़ डालर और नार्वे से 19.66 करोड़ डालर का एफडीआइ आया।

लक्षद्वीप को माडल के रूप में विकसित करने की है कोशिश: लक्षद्वीप द्वीपों के विकास की समग्र रणनीति अद्वितीय सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विशेषताओं को संरक्षित कर द्वीपवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने पर आधारित है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने राज्यसभा में कहा, लक्षद्वीप के विकास के लिए बनाई जा रही रणनीति में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता का लाभ उठाना, मजबूत व लचीली अर्थव्यवस्था बनाना व स्थानीय समुदायों के बीच गर्व और कल्याण की भावना को बढ़ावा देना शामिल है।

जनवरी में बिजली वितरण कंपनियों पर बकाया 50 हजार करोड़ रहा: बिजली मंत्री आरके सिंह ने गुरुवार को लोस में बताया कि जनवरी 2024 में बिजली वितरण कंपनियों पर बकाया घटकर 50 हजार करोड़ रुपये रह गया है। जनवरी 2024 में यह 1,39,947 करोड़ रुपये था। मंत्री ने कहा, नए नियम लागू होने के बाद बिजली कंपनियों से बकाये की वसूली में सुधार हुआ है। कंपनियों मौजूदा बकाये का भी समय पर भुगतान कर रही हैं। उन्होंने बताया कि बीते तीन वर्षों के दौरान 2.3 गीगावाट क्षमता के कोयला आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र बंद हुए हैं।

संसदीय समिति ने कहा- मनरेगा के तहत मजदूरी अपर्याप्त

नई दिल्ली, प्रेट्र: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) के तहत मिलने वाली दैनिक मजदूरी अपर्याप्त है। यह जीवनयापन की बढ़ती लागत के अनुरूप नहीं है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने संसद में गुरुवार को रखी गई एक रिपोर्ट में ये बातें कही हैं।

समिति की रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में 221 रुपये है। वहीं अरूणाचल प्रदेश में 224 रुपये, बिहार एवं झारखंड में 228, सिक्किम की तीन ग्राम पंचायतों में 354 रुपये, निकोबार में 328 रूपये व अंडमान में 311 रुपये है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2008 के बाद से मनरेगा मजदूरी अपर्याप्त है। यह बढ़ती जीवनयापन की लागत के अनुरूप नहीं है। समिति ने न्यूनतम मजदूरी पर अनूप सत्पथी समिति की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है, जिसने सिफारिश की थी कि मनरेगा के तहत मजदूरी 375 रुपये प्रतिदिन होनी चाहिए। संसदीय समिति ने योजना के लिए बजट आवंटन को लेकर भी चिंता जताई है।

रेलवे ट्रैक पर पशुओं के आने के कारण दो साल में हुए पांच ट्रेन हादसे : वैष्णव

नई दिल्ली, प्रेट्र: 2021-22 और 2022-23 में पशुओं के भटक कर ट्रैक पर आने के कारण देश में पांच ट्रेन हादसे हुए हैं। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में दी। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में 110 किमी प्रति घंटा से 130 किमी प्रति घंटे के लिए संवेदनशील स्थानों और 130 किमी प्रति घंटा से अधिक की गति होने पर पूरे ट्रैक पर बाड़ लगाने का प्रविधान है।

भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने रेल मंत्री से पशुओं के कारण देश में हुए हादसों व ट्रैक पर फेंसिंग के संबंध में सवाल पूछा था। रेल मंत्री वैष्णव ने फेंसिंग के जोनवार आंकड़ों को साझा करते हुए बताया कि उत्तर मध्य रेलवे जोन सर्वाधिक 949 किमी ट्रैक की फेंसिंग कर चुका है।

इसके बाद पश्चिमी मध्य जोन 726 किमी व पश्चिमी जोन 720 किमी ट्रैक पर फेंसिंग कर चुके हैं और कुल मिलाकर 4469 किमी ट्रैक की फेंसिंग देशभर में की जा चुकी है।

हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनाएगी चेन्नई की आइसीएफ : रेलवे ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली ट्रेन डिजाइन की है। इसके उत्पादन की योजना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आइसीएफ), चेन्नई द्वारा बनाई गई है।

हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन के विकास के लिए परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है। यह ट्रेन रेलवे में हाइड्रोजन तकनीक के उपयोग का प्रदर्शन करेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।

अश्विनी वैष्णव। फाइल

मानव तस्करी मामलों की मानव तस्करी मामलों की जांच का आरपीएफ को अधिकार नहीं

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को मानव तस्करी के मामलों की की जांच करने का अधिकार नहीं है। ऐसे मामलों की जानकारी आरपीएफ इसकी सूचना पुलिस को देती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकारें अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) अथवा जिला पुलिस के माध्यम से अपराध को रोकने, पता लगाने, पंजीकृत करने व जांच करने के साथ ही रेलवे परिसरों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं।

संसदीय समिति

टोल संग्रह की निगरानी और आडिट के लिए नए तंत्र का सुझाव, समिति ने कहा, दोषपूर्ण फास्टैग के मामलों को गंभीरता से ले सरकार

गलत फास्टैग के लिए दंडित हों एजेंसियां

मनीष तिवारी, नई दिल्ली

संसद की एक स्थाई समिति ने कहा है कि दोषपूर्ण फास्टैग के कारण होने वाली असुविधा के लिए लोगों को नहीं, जिम्मेदार एजेंसियों को दंडित किया जाना चाहिए। समिति ने सरकार से कहा है कि वह टोल संग्रह की निगरानी और स्वतंत्र आडिट के लिए नया तंत्र बनाए।

समिति की यह टिप्पणी इसलिए अहम है, क्योंकि फास्टैग में गड़बड़ी की शिकायतों से चिंतित केंद्र सरकार ने पिछले दिनों एक वाहन, एक फास्टैग की नीति लागू की है और यूजर्स से 29 फरवरी तक केवाईसी अपडेट करने के लिए कहा है। सरकार को शिकायतें मिली हैं कि अनेक वाहनों को एक फास्टैग से जोड़ा गया है।

परिवहन से संबंधित संसदीय समिति ने कहा है कि दोषपूर्ण फास्टैग के अनेक मामले वाहनों की आवाजाही में बाधा डालते हैं। इसके चलते लोगों को दोगुना टोल देना पड़ता है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इस लापरवाही की सजा लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। समिति ने टोल का कुछ हिस्सा राज्यों के साथ भी साझा करने का सुझाव देते हुए कहा कि इस प्रणाली को दूर-दराज के इलाकों तक ले जाने की जरूरत है। समिति ने जानबूझकर या बार-बार अधिक टोल वसूली के दोषी पाए जाने वाले प्लाजा संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और ऐसे संचालकों को भविष्य में बोली प्रक्रिया से बाहर करने का सुझाव दिया है। हाल में कुछ स्थानों पर फर्जी टोल प्लाजा बनाए जाने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए समिति ने कहा, इसे रोकने के लिए पूरे देश में सर्वेक्षण की जरूरत है। फर्जी टोल प्लाजा के संदर्भ में मंत्रालय को अपने कर्तव्यों में लापरवाही के लिए कठोर सजा देने की जरूरत है।

प्रतीकात्मक

भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नंबर प्लेट से हो वसूली

संसदीय समिति के अनुसार नंबर प्लेटों को हालमार्क किया जाता है और इन्हें उच्च रिजोल्यूशन कैमरों द्वारा पहचाना जा सकता है। जहां टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ ज्यादा है, वहां स्वचालित नंबर प्लेट रीडर (एएनपीआर) कैमरे लगाकर क्लोज्ड टोलिंग प्रणाली लागू की जा सकती है। समिति ने सुझाव दिया है कि जब तक एएनपीआर पूरी तरह नहीं लागू हो जाता तब तक एक उपाय यह अपनाया जा सकता है कि अगर कोई वाहन चालक किसी समय भुगतान करने में असमर्थ है तो वाहन को छोड़ देना चाहिए और उसे लेन से बाहर ले जाना चाहिए ताकि यातायात में कोई रुकावट न हो। बाद में टोल टैक्स के भुगतान के लिए वाहन नंबर से जुड़े मोबाइल पर एक पाठ्य संदेश भेजा जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति टोल टैक्स की चोरी करता है तो उसके वाहन नंबर व तस्वीर के आधार पर एफआइआर या चालान जारी किया जा सकता है।

****

एक साल में विमानों में आईं 478 तकनीकी खामियां : वीके सिंह

नई दिल्ली, प्रेट्र: देश में एक साल की अवधि में विभिन्न एयरलाइंस को विमानों से संबंधित 478 तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ा। यह जानकारी नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा में दी है।

वीके सिंह। फाइल

केंद्रीय मंत्री ने जनवरी 2023 से जनवरी 2024 के बीच के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि इस अवधि में इंडिगो को 246 और एअर इंडिया को 63 तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ा। वहीं विस्तारा ने 79, स्पाइसजेट ने 47, एयर एशिया (इंडिया) लिमिटेड ने 22, एलायंस एयर ने सात, अकासा एयर ने छह, फ्लाई बिग ने पांच, ब्लू डार्ट एविएशन ने और ग्राउंडेड गो फर्स्ट ने एक खामी की जानकारी दी।

कह कर रहेंगे — माधव जोशी

'जंगलराज वालों को सत्ता से बाहर करने के लिए नीतीश कुमार का दिया है साथ'

राज्य ब्यूरो, पटना

सम्राट चौधरी।

'धन्यवाद, सम्मान एवं संकल्प सभा' में बोले बिहार के भाजपा अध्यक्ष

बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पार्टी जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं के बीच सत्ता में वापसी के बाद बड़े आयोजन में जोश भरने का भरपूर प्रयास किया। श्रीकृष्ण मेमोरियल सभागार में पार्टी की ओर से आयोजित 'धन्यवाद, सम्मान एवं संकल्प सभा' को सम्राट संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जंगलराज वालों को सत्ता से बाहर करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ दिया है, लेकिन बिहार में भाजपा की सरकार बनाने के संकल्प पर अब भी कायम हैं। सम्राट की इस घोषणा पर सभागार तालियों से गूंज उठा। भाजपा ने कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यकर्ताओं ने एक मिनट तक ताली बजाई और मोबाइल का टार्च रोशन कर नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। इसके बाद बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा एवं मंत्री बने प्रेम कुमार को सम्मानित किया गया। आखिरी में 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 की 40 सीटें जीतने का संकल्प भी लिया। सम्राट ने राजद प्रमुख लालू यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर वे रोजगार का फार्मूला ही बताना चाहते हैं तो प्रदेश की जनता को बता दें कि डेढ़ वर्ष का बच्चा अरबपति कैसे बन सकता है। उन्होंने कहा भाजपा मंडल के साथ है तो कमंडल के साथ भी है। दूसरी ओर राजद का आरक्षण अपने परिवार तक सीमित है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने 2024 के चुनाव में राज्य की 40 संसदीय सीट जीत कर नरेन्द्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने की अपील की।

नीतीश सरकार के विश्वासमत से पहले बोधगया में रहेंगे भाजपा विधायक

राज्य ब्यूरो, पटना

बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद महागठबंधन में कांग्रेस ही नहीं, राजग में भाजपा भी सतर्क हो गई। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने पार्टी विधायकों को दो दिनों के लिए बोधगया में प्रशिक्षण के बहाने तलब कर लिया है। अहम यह है कि बोधगया में आयोजित प्रशिक्षण शिविर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 फरवरी को दो घंटे वर्चुअल रूप से विधायकों को संबोधित करेंगे।

इसके बाद 11 फरवरी को अन्य वरिष्ठ नेता प्रशिक्षण शिविर में कक्षा लेंगे। प्रदेश नेतृत्व ने प्रशिक्षण शिविर का नाम लोकसभा चुनाव तैयारी को लेकर दो दिवसीय कार्यशाला दिया है। पार्टी ने विधायकों को प्रशिक्षण शिविर में बोधगया बुलाने का दायित्व मुख्य सचेतकों को दिया है। विधानसभा एवं विधान परिषद के मुख्य सचेतक सभी सदस्यों को बाकायदा फोन कर प्रशिक्षण शिविर में आने की सूचना दे रहे हैं।

बोधगया में भाजपा विधायक तलब

भाजपा के विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि नेतृत्व अपने विधायकों पर पूरी तरह से नजर रख रहा है। अचानक से बुधवार को भोज के बहाने सभी विधायकों को पटना बुलाया गया। विधानमंडल दल के नेता एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर भोज के बहाने सभी विधायकों को जुटाया गया। इसके बाद वरिष्ठ नेता सभी विधायकों के आवभगत करते देखे गए। यही नहीं, विधायकों को खूब अहमियत दी जा रही थी। गुरुवार की सुबह विधायकों को 10 फरवरी से बोधगया में प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना दी गई। साथ ही नौ फरवरी की शाम तक बोधगया पहुंचने का फरमान भी सुना दिया गया। 10 एवं 11 को पूरे दिन प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगले दिन यानि 11 फरवरी को बोधगया से वापस लौटने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा का सत्र 12 फरवरी से शुरू है। पहले दिन ही एनडीए सरकार को विश्वास मत हासिल करना है। इसके पहले सत्ता पक्ष के विधायकों को पूरी तरह से एकजुट रखने की कोशिश जारी है।

नीतीश ने कहा- चिंता मत कीजिए सब ठीक

नीतीश कुमार। फाइल

राज्य ब्यूरो, पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को दिल्ली से पटना लौट आए। दिल्ली में उन्होंने अपने पार्टी सांसदों के साथ बैठक भी की। हवाई अड्डा परिसर में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में मुख्यमंत्री से जब 12 फरवरी को विधानसभा में एनडीए सरकार द्वारा बहुमत साबित करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। पूर्व मंत्री संजय झा भी मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली से वापस लौटे। मुख्यमंत्री से जब एनडीए की प्रदेश सरकार के विषय में विशेष रूप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए। वर्ष 2005 से हम तो लगातार विकास की बात कर रहे। सारी बातें हो चुकीं हैं। पार्टी के अपने साथियों से भी सारी बात हो चुकी है। हम काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे।

देव-दर्शन से लेकर चोखा तक

राज्य ब्यूरो, पटना

हैदराबाद के निकट रिजार्ट में ठहराए गए बिहार के कांग्रेस विधायकों की हर इच्छा हो रही पूरी

हैदराबादी बिरयानी लाजवाब है, लेकिन जुबान को लगा देसी जायका रह-रह कर बिहार के लिए तड़प बढ़ा दे रहा। यह स्थिति कांग्रेस के उन विधायकों की है, जो हैदराबाद से 36 किलोमीटर दूर इब्राहिमपत्तम् के पास एक रिजार्ट में ठहराए गए हैं। ऐसा नहीं कि वहां फरमाइशें पूरी नहीं हो रही हों! आर्डर पर उन्हें बिहार के अंदाज में बनाया गया चोखा भी परोसा जा रहा, जबकि इच्छा व्यक्त करने पर आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम् (सेल्लम) में भगवान मल्लिकार्जुन का दर्शन भी कराया जा चुका है। चारमीनार देखने की उनकी मुराद भी आजकल में पूरी कर दी जाएगी।

बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक दलों के भीतर खलबली-सी मची हुई है। चंचल चित्त वालों पर विरोधी खेमे की ओर से डोरे डाले जाने की चर्चा द्वैतरफा है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस से बताई जा रही। भनक लगने पर आलाकमान ने तीन फरवरी को सभी विधायकों को दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया। वहां से उन्हें श्री नेचर वैली रिजार्ट में शिफ्ट कर दिया गया। रिजार्ट में उनकी सुख-सुविधा से लेकर पसंद तक का पूरा ध्यान रखा जा रहा। एक-एक कर उनकी इच्छाएं भी पूरी की जा रहीं। पसंद पूछकर देसी अंदाज वाले चोखा से लेकर स्वादिष्ट सब्जी व मांसाहारी व्यंजन तक परोसे जा रहे। मोबाइल फोन उनके पास ही है और एक-दूसरे से मिलने-जुलने पर मनाही भी नहीं, लेकिन गुट में संवाद की गुंजाइश कम है। ऐसी ही तड़प के साथ कांग्रेस विधायकों ने श्रीभ्रामरांबिका मल्लिकार्जुन मंदिर में पूजा-अर्चना की इच्छा व्यक्त की। आलाकमान के निर्देश पर वह इच्छा भी पूरी कर दी गई है।

कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा पुराने मंत्रियों को ड्राप करना

राज्य ब्यूरो, रांची : राज्य कैबिनेट में फेरबदल की संभावनाओं के बीच यह तो तय माना जा रहा है कि कांग्रेस को एक बार फिर चार मंत्री पद मिलेंगे, लेकिन पार्टी स्तर से ही यह बात फैल रही है कि एक से दो मंत्री के चेहरे बदले जा सकते हैं। इस संभावना मात्र से कांग्रेस के कई नेता सक्रिय हो गए हैं। कुछ नेताओं के नाम अभी से चर्चा में आ गया है। प्रदीप यादव, दीपिका पांडेय सिंह, अनूप सिंह आदि के नाम अग्रणी पंक्ति में हैं। यह तो तभी होगा जब कुछ नेताओं को कैबिनेट से हटाने का निर्णय ले लिया जाए। यह निर्णय इतना आसान भी नहीं है। पहले से ही कई प्रकार का विरोध झेल रही पार्टी में मंत्रियों के हटने से समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ऐसा कोई रिस्क पार्टी नहीं लेना चाहेगी। दूसरी ओर, यह बातें भी कही जा रही हैं कि पार्टी उन नेताओं को ही कैबिनेट से हटाएगी, जिन्हें अगले चुनाव में बेटिकट करने की मंशा है। कांग्रेस के लिए मंत्रियों को हटाने का निर्णय इतना सहज भी नहीं होगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 14 फरवरी को पलामू के रास्ते प्रवेश कर रही है। इस यात्रा के गुजरने से पहले किसी प्रकार का जोखिम प्रदेश नेतृत्व नहीं उठाना चाहता है। यही कारण है कि मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को एक सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। पहले यह गुरुवार को होना था। अब 16 फरवरी को संभावित है।

छोटे दलों संग भाजपा की बड़ी रणनीति, साधे पूरब से पश्चिम तक समीकरण

मिशन 400 पार ▸ उप्र में पार्टी 80 सीटों के लक्ष्य की ओर, बढ़ सकती हैं विपक्ष की चुनौतियां

पूर्वांचल में अपना दल, निषाद पार्टी और सुभासपा तो रालोद संग पश्चिम में संतुलन

दो लोकसभा चुनावों के परिणाम बताते हैं कि अवध, ब्रज व बुंदेलखड में भाजपा के लिए खास चुनौती नहीं, बाकी पर पकड़ बनाने की कोशिश

जितेंद्र शर्मा, नई दिल्ली

लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजग के लिए 'अबकी बार 400 पार' का नारा सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सरकार के कामकाज की ताकत के साथ-साथ भाजपा संगठन की ठोस रणनीति के आधार पर दिया। इस बड़े लक्ष्य के लिए भाजपा की प्रदेश इकाइयां किस तरह 'माइक्रो मैनेजमेंट' कर रही हैं, उसकी बानगी उत्तर प्रदेश में साफ दिखाई देती है। प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने के लिए भाजपा छोटे दलों संग बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। ब्रज, अवध और बुंदेलखंड पहले से मजबूत थे। कुछ दलों को साथ लेकर सपा के प्रभाव वाले पूर्वांचल को साधा और अब राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के सहारे चुनौतीपूर्ण माने जा रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संतुलन बनाने की भी तैयारी कर ली है।

भाजपा की रणनीति। फाइल

सर्वाधिक संसदीय सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अंचलवार क्षेत्रीय दलों का जातीय प्रभाव है। पिछले दो लोकसभा चुनावों के परिणाम बताते हैं कि अवध, ब्रज और बुंदेलखड में भाजपा के लिए कोई खास चुनौती नहीं है, लेकिन पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनौतीपूर्ण जरूर था। यहां दलितों और पिछड़ों की आबादी अच्छी संख्या में है। इसी कारण 2019 में सपा, बसपा और रालोद ने प्रदेश में गठबंधन कर चुनाव लड़ा तो सपा के गढ़ मैनपुरी और कांग्रेस की पारंपरिक सीट रायबरेली सहित भाजपा को पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सात-सात सीटों पर पराजय मिली। लिहाजा, इस बार इन दोनों अंचलों में भाजपा सभी जातीय समीकरणों को दुरुस्त कर लेना चाहती है।

पूर्वांचल की बात करें तो यहां जिन जातियों का मजबूत प्रभाव है, उनमें यादव, कुर्मी, निषाद, राजभर और लोनिया मजबूत स्थिति में हैं। यादव मजबूती से सपा के साथ हैं, लेकिन छह प्रतिशत भागीदारी और प्रदेश की करीब 10 सीटों पर असर डालने वाली कुर्मी बिरादरी को साधने के लिए भाजपा ने सरकार और संगठन में इस वर्ग के नेताओं को प्रतिनिधित्व देने के साथ अपना दल (एस) का दामन 2014 से थाम रखा है। जदयू के राजग में शामिल होने से नीतीश कुमार का भी कुछ प्रभाव इस जाति-वर्ग पर पड़ेगा।

निषाद पार्टी भाजपा के साथ है और चार प्रतिशत वोट की हिस्सेदारी वाली राजभर जाति के असरदार नेता ओमप्रकाश राजभर को भाजपा वापस अपने साथ ले आई, जो 2022 में सपा के साथ चले गए थे। लोनिया चौहान जाति का भी कुछ असर पूर्वांचल की सीटों पर देखते हुए इस जाति के नेता दारा सिंह चौहान को वापस भाजपा में शामिल कर एमएलसी बना दिया गया है। इस तरह वाराणसी से सांसद प्रधानमंत्री मोदी के आकर्षण के साथ छोटी-छोटी जातियों के सहारे पूर्वांचल को साधने की कोशिश भाजपा ने की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रतिशत वोट जाटों का है। जाटों की राजनीति करने वाला रालोद 2019 में सपा और बसपा के साथ मिलकर लड़ा। वह खुद कोई सीट नहीं जीत सका, लेकिन सपा और बसपा के लिए समीकरण दुरुस्त कर दिए, जिसकी वजह से भाजपा को यहां की सात सीटों पर हार मिली। अभी तक रालोद मुखिया जयन्त चौधरी सपा का हाथ थामे आइएनडीआइए में थे, लेकिन अचानक घटनाक्रम बदला और भाजपा के साथ उनकी बातचीत अंतिम दौर में है। भाजपा ने जिस तरह 2024 के लिए पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जातीय गोलबंदी की है, वह विपक्षी दलों के लिए चुनौती बढ़ा सकती है।

रालोद से दोस्ती, कान्हा की नगरी में भाजपा की राधे-राधे

विनीत मिश्र, मथुरा

राजनीति

ब्रज में सक्रिय जयन्त का साथ भाजपा को गढ़ में देगा मजबूती

सपा, बसपा और कांग्रेस मथुरा में पहले से हैं काफी कमजोर

रालोद से दोस्ती के बाद कान्हा की नगरी में भाजपा की राधे-राधे हो जाएगी। यह दोस्ती जितनी जयन्त के लिए फायदेमंद होगी, उतना ही लाभ भाजपा को भी होगा। कारण साफ है। भाजपा के बाद यहां सबसे मजबूत स्थिति में रालोद है। अयोध्या, मथुरा, काशी के नारे के बीच मथुरा भगवा खेमे के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीट है। गठबंधन में भाजपा किसी दूसरे दल को यह सीट नहीं देगी। यह भी लगभग तय है। जयन्त से दोस्ती के बाद भाजपा को उन जाटों का वोट भी मिलेगा, जो सीधे तौर पर रालोद से जुड़े हैं।

जयंत चौधरी। फाइल

19 लाख मतदाताओं वाली मथुरा लोकसभा सीट में करीब साढ़े तीन लाख जाट मतदाता हैं। लगभग इतनी ही संख्या ब्राह्मण मतदाताओं की है। यह क्षेत्र रालोद के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 1967 में चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी ने गोकुल विधानसभा सीट से भारतीय क्रांति दल के टिकट पर चुनाव जीता। 2004 में चौधरी चरण सिंह की बेटी ज्ञानवती ने मथुरा लोकसभा से रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2009 में जयन्त चौधरी चुनाव लड़े और मथुरा के सांसद बने। सांसद रहते ही उन्होंने 2012 में मांट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और यहां से लगातार छह बार विधायक रहे श्याम सुंदर शर्मा को पराजित किया। हालांकि बाद में जयन्त ने सीट छोड़ दी और उपचुनाव में श्याम सुंदर शर्मा फिर विधायक बने। 2014 के चुनाव में जयन्त को भाजपा की हेमा मालिनी से हार का सामना करना पड़ा। भले ही जयन्त चुनाव हारे, लेकिन यहां उनका संपर्क बराबर रहा। तीन पीढ़ियों से उनका मथुरा से नाता रहा है। यहां बड़ी संख्या में जाट मतदाता रालोद के साथ जुड़े हैं। यही कारण था कि आइएनडीआइए ने यह सीट रालोद के खाते में दे दी थी।

भाजपा के एजेंडे में मथुरा प्रमुख: भाजपा के लिए मथुरा अब मजबूत गढ़ है। साफ है कि भाजपा रालोद को यह सीट नहीं देगी। हां, रालोद के साथ आने से स्थिति और मजबूत होगी।

राहुल ने कहा-मोदी जन्म से ओबीसी नहीं, भाजपा का पलटवार

जेएनएन, नई दिल्ली

कांग्रेस नेता ने कहा, सीएम बनने के बाद अपनी जाति ओबीसी में बदल दी

अमित मालवीय ने राहुल पर लगाया सरासर झूठ बोलने का आरोप

ओडिशा में गुरुवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते कांग्रेस नेता राहुल गांधी। एएनआइ

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं हैं। उन्हें ओबीसी गुजरात की भाजपा सरकार ने बनाया है। राहुल के इस बयान के बाद भाजपा ने पलटवार करते हुए उन पर पिछड़े वर्ग का अपमान करने का आरोप लगाया। भाजपा के हमलों के बाद राहुल ने सत्तारूढ़ पार्टी को धन्यवाद दिया और कहा कि उसने इस बात की पुष्टि कर दी कि पीएम मोदी जन्म से ओबीसी नहीं हैं।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में ओडिशा के झारसुगुड़ा पहुंचे राहुल गांधी ने अपने संक्षिप्त भाषण में कहा कि आपको नरेन्द्र मोदी की जाति के बारे में यह सच पता है? मोदी 'सामान्य वर्ग' में पैदा हुए। राहुल ने कहा, मोदी जी लोगों को यह कहकर गुमराह कर रहे हैं कि वह ओबीसी हैं। वह घांची जाति में पैदा हुए, जिसे गुजरात की भाजपा सरकार ने वर्ष 2000 में ओबीसी की सूची में शामिल किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी ने अपनी जाति ओबीसी में बदल दी। इसलिए वह जन्म से ओबीसी नहीं हैं। राहुल ने कहा, मैंने जातिवार जनगणना और सामाजिक न्याय की बात की तो पीएम मोदी ने कहा-देश में सिर्फ दो जातियां हैं, अमीर और गरीब। अगर दो जातियां हैं तो आप क्या हैं? गरीब तो आप हैं नहीं। आप करोड़ों का सूट पहनते हैं। दिन में कई बार कपड़े बदलते हैं, फिर झूठ बोलते हैं कि मैं ओबीसी वर्ग का आदमी हूं। भाजपा आइटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय, राज्यसभा सदस्य नरहरि अमीन के साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल के बयान पर जबर्दस्त पलटवार किया। 2012 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले अमीन ने कहा, मैं कांग्रेस सरकार में गुजरात का उपमुख्यमंत्री था, जब राज्य सरकार ने 25 जुलाई, 1994 को मोढ़-घांची को ओबीसी के रूप में अधिसूचित किया था। यह वही जाति है जिससे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आते हैं। राहुल गांधी झूठ बोलकर ओबीसी समुदाय का अपमान कर रहे हैं। राज्य सरकार का यह फैसला और उसके बाद भारत सरकार की अधिसूचना जब आई, उस समय नरेन्द्र मोदी सांसद या विधायक भी नहीं थे। अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी का दावा सरासर झूठ है। अपनी बात के समर्थन में मालवीय ने नरहरि अमीन का पोस्ट भी साझा किया। एक अन्य पोस्ट में मालवीय ने कहा कि 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में पहली बार ओबीसी दर्जा अस्तित्व में आया। इसलिए 1992 से पहले किसी जाति के लिए ओबीसी वर्ग में शामिल किया जाना संभव नहीं था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि या तो राहुल गांधी सच में नासमझ हैं या फिर उन्हें लगता है कि बार-बार झूठ बोलने से झूठ को ही सच मान लिया जाता है।

ममता ने चुनाव से पहले एनआरसी, यूसीसी मुद्दे उठाने पर भाजपा की आलोचना की

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले सीएए, एनआरसी और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जैसे मुद्दे उठाने के लिए गुरुवार को भाजपा की आलोचना की और कहा कि बंगाल रास्ता दिखाएगा कि कैसे भाजपा की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए।

राज्य का बजट पेश होने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने आगामी चुनावों से पहले संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के मुद्दे को अवसरवाद के रूप में उठाया है। ममता ने कहा, वे (भाजपा) चुनाव से पहले एनआरसी, सीएए और यूसीसी के बारे में बोल रहे हैं। यह राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। इसमें देश का कोई भला नहीं है।

उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि हम अपने अधिकारों और अपने बकाया कोष के लिए लड़ेंगे। बंगाल विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ने का रास्ता दिखाएगा।

राजभर का दावा 12 को एनडीए में आएंगे जयन्त, सुप्रिया को नहीं पता-कौन हैं प्रमोद कृष्णम!

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में एनडीए और आइएनडीआइए गठबंधन में पालाबंदी तेज हो गई है। रालोद की भाजपा के साथ गठबंधन की चल रही चर्चाओं के बीच एनडीए के सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार को पत्रकारों के सामने बड़ा दावा किया। कहा, जयन्त चौधरी 12 फरवरी को एनडीए में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से संबंधित सवाल पर साफ कहा कि प्रमोद कृष्णम कौन हैं, मैं नहीं जानती।

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहीं थीं। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बारे में पूछे गए सवाल से पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने कहा कि यह कौन हैं, मैं उन्हें नहीं जानती। आचार्य कृष्णम कुछ समय से कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बयान देने की वजह से चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी की।

'कुछ सटकर तो कुछ हटकर बनवा रहे मोदी को प्रधानमंत्री'

सुभासपा प्रमुख ने ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि इस बार विपक्षियों ने ठाना है, 2024 में नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सटकर तो कुछ हटकर नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि '12 फरवरी तक रुक जाइए और देखिएगा नतीजा क्या होगा।' उन्होंने कहा कि सपा को रसातल में पहुंचाने के लिए ही स्वामी प्रसाद मौर्य को भेजा गया है। हालांकि, मौर्य के इस तरह के बयान के लिए अखिलेश भी जिम्मेदार हैं।

राजभर। फाइल

तैयारी

आम आदमी पार्टी के इस कदम से असमंजस में हैं मंत्री, उनको अनुकूल परिणाम न आने पर मंत्री पद जाने का सता रहा है डर

पंजाब में आप अपने मंत्रियों को उतार सकती है लोकसभा चुनाव में

इन्द्रप्रीत सिंह . चंडीगढ़

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी (आप) लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए पंजाब में कुछ संसदीय सीटों पर पार्टी के बड़े चेहरों को उतार सकती है। चूंकि, इस समय ज्यादातर बड़े चेहरे कैबिनेट में मंत्री हैं, ऐसे में उन्हें ही उतारने पर विचार किया जा रहा है। पार्टी की ओर से ऐसे पांच मंत्रियों की पहचान भी की गई है। दूसरी तरफ मंत्री लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर असमंजस हैं। उनका मानना है कि अगर परिणाम पार्टी के अनुकूल नहीं आए तो ऐसा न हो कि मंत्री पद भी गंवाना पड़े।

पार्टी की ओर से जिन पांच मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़वाने की बात चल रही है, उनमें कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को बठिंडा, सामाजिक सुरक्षा मंत्री डा. बलजीत कौर को फरीदकोट, अमन अरोड़ा अथवा गुरमीत सिंह मीत हेयर को संगरूर और खाद्य आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क को होशियारपुर से मैदान में उतारने पर विचार किया जा रहा है। पार्टी आलाकमान नियमित रूप से कार्यकर्ताओं और कुछ एजेंसियों के माध्यम से इन मंत्रियों के बारे में निर्वाचन क्षेत्रों से फीडबैक ले रहा है।

खास बात यह है कि यदि इन पांच मंत्रियों को मैदान में उतारा गया तो आने वाले समय में एक बार फिर से कैबिनेट में फेरबदल की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंत्रियों की कारगुजारी को लेकर कई मंत्रियों की अच्छी तरह से क्लास लगाई थी। उससे भी यह अहसास होने लगा था कि कुछ मंत्रियों के काम से वह खुश नहीं हैं। चूंकि, इस समय ईडी की जांच को लेकर जिस प्रकार से राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा हुआ है, ऐसे में मंत्रिमंडल में फेरबदल का काम पिछड़ता जा रहा है।

आप ने असम में तीन लोकसभा सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

पार्टी को उम्मीद, आइएनडीआइए उसके फैसले का करेगा समर्थन

कहा, पंजाब अलग-अलग चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस और आप

आइएनडीआइए के प्रमुख घटक आम आदमी पार्टी ने एकतरफा फैसला लेते हुए असम की तीन लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी के संगठन महामंत्री व राज्यसभा सदस्य डा. संदीप पाठक ने कहा कि डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से मनोज धनोवर, गुवाहाटी से भाबेन चौधरी और सोनितपुर से ऋषिराज आप के उम्मीदवार होंगे। इन तीन सीटों पर हम जल्द चुनाव प्रचार शुरू कर देंगे। उम्मीद है कि आइएनडीआइए इसको स्वीकार करते हुए अपना समर्थन देगा और ये तीनों लोकसभा सीटें आप को दे दी जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर आप की कांग्रेस से बातचीत जारी है, लेकिन पंजाब में दोनों अलग-अलग लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। वहां कोई गठबंधन नहीं होगा।

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, पंजाब कांग्रेस के संगठन महामंत्री कैप्टन संदीप संधू। जागरण

गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में संदीप पाठक ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर लंबे समय से वार्ता चल रही है। हमें जल्द इस बातचीत को निष्कर्ष तक ले जाना पड़ेगा। आप पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ आइएनडीआइए का हिस्सा बनी रहेगी। आप गठबंधन का धर्म निभाएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की तारीख लगभग तय हो चुकी है। चुनाव में कुछ माह ही शेष रह गए हैं। इतने कम समय में हमें चुनाव की तैयारी करनी है और चुनाव भी लड़ना है। हमने चुनाव जीतने के लिए गठबंधन किया है और चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी पड़ेगी।

राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस-आप एक साथ: अलका लांबा

उधर, चंडीगढ़ में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस और आप एक साथ हैं। आप आइएनडीआइए का हिस्सा है। पंजाब में दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर अभी चर्चा चल रही है।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद

श्रेय लेने की होड़, आप और कांग्रेस के आक्रामक तेवर

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़: मेयर चुनाव का विवाद ठंडा नहीं होने दिया जा रहा है। अब इस विवाद का श्रेय लेने की होड़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में शुरू हो गई है। आप पहले से ही नगर निगम कार्यालय के बाहर क्रमिक अनशन पर है। अब कांग्रेस भी कई दिनों से आक्रामक तेवर दिखा रही है। वीरवार को युवा कांग्रेस ने एमसी कार्यालय पहुंचकर मेयर कार्यालय पर ताला जड़ने का प्रयास किया। हालांकि बड़ी संख्या में पहले से मौजूद पुलिस बल ने ऐसा होने नहीं दिया।

पुलिस और कांग्रेस की लगातार दूसरे दिन भिड़ंत हुई। पुलिस ने उन्हें खदेड़ा और बाकी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बसों से थाने ले गई। वहीं, आम आदमी पार्टी का एमसी कार्यालय के बाहर अनशन जारी रहा। आप अब सभी वार्ड में कैंडल मार्च भी निकाल रही है। दोनों ही दलों में अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस विवाद का श्रेय लेने की होड़ मच गई है।

617 अरब डालर तक पहुंच गया 2024 के जनवरी में विदेशी मुद्रा का भंडार इसकी तुलना में। जबकि वर्ष 2014 में विदेशी मुद्रा का भंडार 303 अरब डालर था।

अपने काले कारनामे छिपाने को कांग्रेस ने जारी किया ब्लैक पेपर : भाजपा

रविशंकर प्रसाद बोले– भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा, जनता का पैसा लूटने वालों के लिए कोई जगह नहीं

कांग्रेस परेशान, भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई कराना चाहती है बंद

रविशंकर प्रसाद।

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी करने को लेकर गुरुवार को कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने दावा किया कि विपक्षी पार्टी अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए इसे लेकर आई है। उसे दर्द हो रहा है क्योंकि वह भ्रष्टाचार के मामलों में हो रही कार्रवाई को बंद करवाना चाहती है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा केंद्र सरकार की कथित विफलताओं को उजागर करने के लिए ब्लैक पेपर जारी करने के बाद यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा–'लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। जनता का पैसा लूटने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। हम आपके काले कारनामों का पर्दाफाश करेंगे।'

भाजपा नेता ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और लाखों करोड़ रुपये के घोटालों में शामिल हैं, वे ब्लैक पेपर ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि घोटालों की कहानी खत्म हो गई है और देश मोदी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सरकारी योजनाओं के 10 करोड़ से अधिक फर्जी लाभार्थियों के खातों को बंद कर दिया है। प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार जब सत्ता में थी तब भारत को कमजोर अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जाता था और उसकी पहचान नीतिगत पंगुता वाली थी जबकि अब यह पांचवीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था है और इसका विदेशी मुद्रा भंडार और विदेशी निवेश बढ़ रहा है।

उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और बेरोजगारी के कांग्रेस के दावे को खारिज कर दिया और आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने बहुत सारे रोजगार पैदा किए हैं और संप्रग की तुलना में महंगाई से बेहतर ढंग से मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को बेनकाब करेंगे। जनता उसे कोई भाव नहीं देगी।

पीएम मोदी गारंटी योजना। फाइल

- वर्ष 2004–14 में 1.8 करोड़ शौचालय का निर्माण
- वर्ष 2014–24 में 11.5 करोड़ शौचालय का निर्माण
- संप्रग काल के 2004–2014 में 2.15 करोड़ ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण
- राजग काल के 2017–22 में 2.86 करोड़ ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण
- सस्ती दवा के लिए संप्रग काल में 2008–14 के बीच 164 जन औषधी केंद्र खोले गए
- राजग के 2014–2023 के कार्यकाल के दौरान 10, 000 स्टोर खोले गए
- संप्रग सरकार के दौरान 2011–14 में 6,577 किलोमीटर आप्टिकल फाइबर बिछाई गई
- राजग सरकार के दौरान 2015–23 में 6.8 लाख किमी आप्टिकल फाइबर बिछाई गई
- वर्ष 2010–2013 के दौरान 9.9 लाख लाभार्थियों को मातृत्व योजना लाभ मिला
- राजग काल में वर्ष 2017–23 के दौरान 3 .59 करोड़ को मिला मातृत्व योजना का लाभ

संप्रग व राजग सरकार में देश का प्रदर्शन

वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने गुरुवार को अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पेश किया है। इसमें बताया गया है कि संप्रग सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल और राजग के 10 वर्ष के कार्यकाल में अलग–अलग क्षेत्र में देश का प्रदर्शन कैसा रहा।

क्षेत्र	यूपीए	एनडीए
महंगाई (प्रतिशत में)	8.2	5.0
जीडीपी प्रति व्यक्ति आय (डालर में)	3,889	6,016
पूंजीगत खर्च (जीडीपी का प्रतिशत)	1.7	3.2
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (अरब डालर में)	305	59,6.5
बहुआयामी गरीबी (आबादी का प्रतिशत)	29.2	11.3
मेट्रो रेल (शहरों की संख्या)	5	20
बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई (हजार किलोमीटर)	25.7	54.9
राजमार्ग निर्माण की गति (किमी/प्रतिदिन)	12	28.3
विद्युतीकृत रेल नेटवर्क (हजार किलोमीटर)	21.8	60.8
हवाई अड्डों की संख्या	74	149
औसत टोल प्लाजा प्रतीक्षा समय (मिनट)	12.2	0.47
कुल स्थापित बिजली क्षमता (गीगा वाट)	249	429
स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता (गीगा वाट)	76	181
मासिक डाटा का इस्तेमाल (जीबी)	0.06	18.39
वायरलेस डाटा टैरिफ (रुपये प्रति जीबी)	269	10.1
मेडिकल कालेज की संख्या	387	706
मेडिकल कालेज में सीटों की संख्या	51,348	1,08,940
विश्वविद्यालयों की संख्या	676	1,168
वैश्विक नवाचार सूचकांक (रैंकिंग)	81	40
ट्रेडमार्क का पंजीकरण (लाख में)	8.8	17.9
इलेक्ट्रानिक्स का निर्यात (अरब डालर में)	7.6	22.7
अप्रत्यक्ष कर दर (प्रतिशत में)	15	12.2
स्टार्ट अप की संख्या	350	1,17,257
हार्वर्ड कांप्लेक्सिटी इंडेक्स (रैंकिंग)	52	42
रेल दुर्घटनाएं (दुर्घटनाओं की औसत संख्या)	233	34
लाजिस्टिक्स परफार्मेंस इंडेक्स (रैंकिंग)	54	38
मोबाइल ब्राडबैंड सब्सक्राइबर (करोड़ में)	6	90
एलपीजी कनेक्शन की संख्या (करोड़ में)	14.5	31.4
पीएनजी कनेक्शन की संख्या (लाख में)	22.3	119
विद्युतीकरण की स्थिति (प्रतिशत)	85.1	100
बिजली की औसत उपलब्धता ग्रामीण (घंटे)	12	20.6
पेयजल कनेक्शन की संख्या ग्रामीण (करोड़ में)	3.2	13.8
डीबीटी लाभार्थियों की कुल संख्या (करोड़ में)	10.8	166
वंचित परिवारों को राशि हस्तांतरण (करोड़ रु.)	7,367	7,16,396
शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कचरा निस्तारण (पैदा हुए कुल कचरे का प्रतिशत)	18	76

नोट : आंकड़े संबंधित विभागों, मंत्रालयों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से लिए गए हैं।

संप्रग सरकार में राजनीतिक हस्तक्षेप से पैदा हुआ बैंकिंग संकट

जेएनएन, नई दिल्ली : संप्रग सरकार को पिछली सरकार से एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली मिली थी जिसमें फंसे हुए कर्ज का अनुपात कम था। लेकिन संप्रग सरकार के कार्यकाल में राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फंसे हुए कर्ज (एनपीए) का अनुपात बढ़ कर 12.3 प्रतिशत हो गया था। इसमें पुनर्गठित कर्ज भी शामिल था। अटल बिहारी बाजपेयी की अगुवाई वाली राजग सरकार का कार्यकाल खत्म होने पर एनपीए का अनुपात 7.8 प्रतिशत था। केंद्र सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था पर पेश किए गए श्वेत पत्र में यह बात कही गई है।

श्वेत पत्र के मुताबिक, 2014 का बैंकिंग संकट बहुत बड़ा था और बहुत बड़े पैमाने पर राशि दांव पर लगी थी। मार्च, 2004 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सकल अग्रिम सिर्फ 6.6 लाख करोड़ रुपये था। वहीं मार्च 2012 में सकल अग्रिम बढ़ कर 39.0 लाख करोड़ हो गया। संप्रग सरकार में आर्थिक कुप्रबंधन की स्थिति इतनी गंभीर थी कि सभी समस्याग्रस्त कर्ज की पहचान भी नहीं की गई। मार्च 2014 में प्रकाशित रेटिंग एजेंसी क्रेडिट सुईस की रिपोर्ट के अनुसार एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली शीर्ष 200 कंपनियों पर बैंकों का लगभग 8.6 लाख करोड़ रुपये बकाया था। ऐसे कर्ज का करीब 44 प्रतिशत समस्याग्रस्त कर्ज के तौर पर नहीं माना गया था। अगर ऐसा किया जाता तो एनपीए के अनुपात में 6.7 प्रतिशत और जुड़ जाता। 2018 में संसदीय समिति को दिए गए लिखित जवाब में आरबीआइ के पूर्व गवर्नर ने कहा, 'बड़ी संख्या में खराब कर्ज 2006–2008 के बीच दिए गए कर्ज से सामने आए।

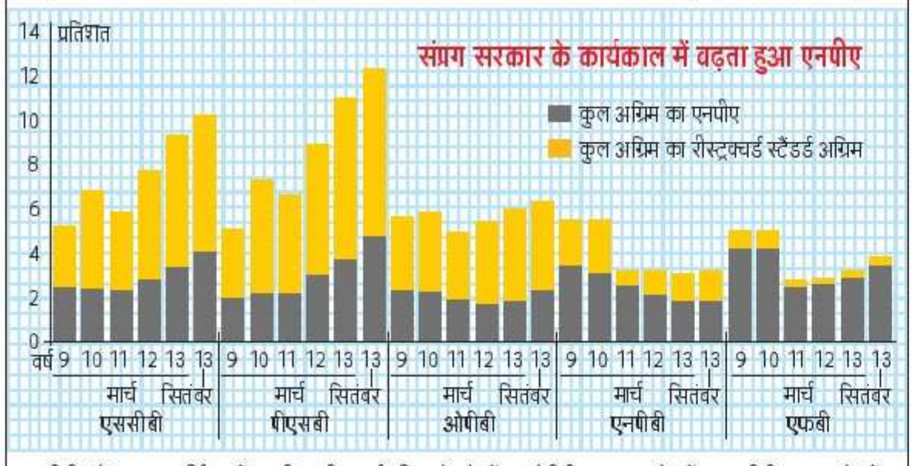

एससीबी : शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पीएसबी : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ओपीबी : अन्य प्राइवेट बैंक, एनपीबी : न्यू प्राइवेट बैंक, एफबी : फाइनेंशियल बैंक

इसलिए लाया गया श्वेत पत्र

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने श्वेत पत्र के जरिए संप्रग शासनकाल के दस सालों के कारनामों की लोगों को फिर से याद दिलाई है। साथ ही यह भी बताया है कि 2014 में उन्हें जब सत्ता मिली थी, तो उस समय देश के हालात कैसे थे। आर्थिक स्थिति कैसी थी। श्वेत पत्र लाने के पीछे उद्देश्य को भी इस दौरान सरकार ने साफ किया है।

सरकार ने बताया था कि श्वेत पत्र लाने के पीछे उनके चार उद्देश्य हैं, पहला– संसद सदस्यों और देश की जनता को वर्ष 2014 में सत्ता में आने के दौरान विरासत में मिले संसाधन, आर्थिक स्थिति से अवगत कराना। दूसरा– देशवासियों को अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए और अमृतकाल में लोगों के विकास के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराना। तीसरा– राजनीतिक लाभ के बजाय राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए उठाए गए कदमों को लेकर लोगों में भरोसा जगाना और चौथा– संभावनाओं और अवसरों की उपलब्धता को देखते हुए देश को नई प्रेरणाओं और नए संकल्पों के साथ राष्ट्रीय विकास के तैयार करना।

क्या होता है श्वेत पत्र और स्याह पत्र: श्वेत पत्र किसी विशिष्ट विषय या मुद्दे पर व्यापक जानकारी, विश्लेषण और प्रस्ताव प्रदान करता है। यह अक्सर सरकारों, संगठनों और विशेषज्ञों द्वारा नीति को आकार देने के लिए तैयार किया जाता है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार नीति और विनिमय दर नीति जैसे विभिन्न विषयों पर पिछले कुछ वर्षों में सरकार की समग्र आर्थिक नीति का वर्णन, मूल्यांकन और विश्लेषण करता है। इसे सरकार की नीतियां व उपलब्धियां बताने और जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए भी पेश किया जाता है। इसके उलट ब्लैक पेपर (स्याह पत्र) किसी विषय, मुद्दे या नीति पर असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है।

श्वेत पत्र से जनता को रूबरू कराने को राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी भाजपा

भाजपा श्वेत पत्र की मुख्य बातों से जनता को अवगत कराने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगी। सूत्रों के अनुसार देशभर में भाजपा की प्रदेश इकाइयां श्वेत पत्र में दर्ज विस्तृत जानकारी लोगों को देंगी ताकि आजमन कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित अन्य मामलों में किए गए खिलवाड़ से अवगत हो सके। इसके साथ ही 2014 के बाद से राजग सरकार के कार्यकाल के दौरान अर्थव्यवस्था व अन्य क्षेत्रों में उठाए गए सुधारात्मक कदमों से अवगत कराएगी। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा का मानना है कि यह श्वेत पत्र अप्रैल–मई में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले जनता के बीच कांग्रेस और उसके सहयोगियों की अयोग्यता और नाकामी तथा पीएम मोदी के सक्षम नेतृत्व का संदेश देगा।

संप्रग सरकार की प्राथमिकता में नहीं था सामाजिक विकास

- श्वेत पत्र में मोदी सरकार ने बताया–2004 से 2014 के बीच नहीं खर्च हुए 94 हजार करोड
- किसानों की कर्ज माफी जैसे वोट बैंक वाले कदमों से रुकी प्रगति की रफ्तार

आर्थिक विकास। फाइल

मनीष तिवारी, नई दिल्ली

मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था पर लाए गए श्वेत पत्र में याद दिलाया है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के कार्यकाल में किस तरह सामाजिक क्षेत्र की कई योजनाओं के लिए पैसा खर्च करने में कोताही बरती गई और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि सरकार की योजनाओं का प्रभाव ही खत्म हो गया। सरकार ने आंकड़ों के साथ उन दिनों की नीतिगत निष्क्रियता और दिशाहीनता बयान की है और यह भी बताया है कि मोदी सरकार के 10 सालों में सशक्त और प्रभावी डिलिवरी सिस्टम ने लोक कल्याण की पूरी तस्वीर ही सुनहरी कर दी है।

श्वेत पत्र में सरकार ने बताया है कि 2004 से 2014 के बीच समाज और ग्रामीण विकास से जुड़े 14 मंत्रालयों और विभागों में संप्रग सरकार ने कुल बजटीय व्यय का 94,060 करोड़ रुपये खर्च ही नहीं किया। यह इस अवधि में कुल बजटीय अनुमान का 6.4 प्रतिशत था। इसके विपरीत राजग सरकार के दौरान 2014 से 2024 के बजटीय व्यय की एक प्रतिशत से भी कम राशि अप्रयुक्त रही। ये सभी मंत्रालय सीधे तौर पर सामाजिक और ग्रामीण विकास से जुड़े हैं। इनमें कृषि और किसान कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अल्पसंख्यक कार्य, ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन, सामाजिक न्याय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, जनजातीय कार्य, महिला और बाल विकास, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय शामिल हैं।

सरकार ने श्वेत पत्र में कहा है कि संप्रग शासन के दौरान भारतीय परिवारों के लिए स्वास्थ्य व्यय भी चिंता का विषय था। उस समय स्वास्थ्य व्यय गरीब परिवारों के लिए गरीबी का मार्ग तो था ही, यह लोगों की जेबें भी खाली कर रहा था। इसके लिए सरकार ने 2014 में देश के कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) में आउट आफ पाकेट व्यय (ओओपीई) 64.2 प्रतिशत होने के तथ्य का हवाला दिया है। मोदी सरकार ने यह तथ्य भी बताया है कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने अनुत्पादनकारी खर्च को प्राथमिकता दी। इसका मतलब था–निवेश के बजाय उपभोग के लिए महत्वपूर्ण धन का आवंटन। उदाहरण के लिए छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर गलत तरीके से अमल तथा 2008 की कृषि कर्ज माफी और ऋण राहत योजना, जिस पर 52 हजार करोड़ रुपये (जीडीपी का एक प्रतिशत) खर्च हुए। सरकार ने अपनी बात के समर्थन में विश्व बैंक के एक शोध पत्र का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि कर्ज माफी से बेहतर निवेश, खपत या बढ़ी हुई मजदूरी का कोई सुबूत नहीं मिलता है। एक अर्थशास्त्री ने उस वक्त टिप्पणी की थी कि संप्रग सरकार आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए डरपोक रवैया अपना रही है। श्वेत पत्र में कहा गया है कि इस निराशाजनक तस्वीर के मुकाबले मोदी सरकार में सामाजिक कल्याण के माध्यम से सशक्तीकरण का रास्ता चुनकर सबका साथ, सबका विकास की विचारधारा को अपनाया गया है।

मोदी सरकार ने सशक्त निगरानी तंत्र लागू किया

मोदी सरकार ने यह रेखांकित किया है कि उसने किस तरह तकनीक का इस्तेमाल करके सशक्त निगरानी तंत्र लागू किया है। जैम ट्रिनिटी यानी जनधन, आधार और मोबाइल की तिकड़ी ने एक नए युग को जन्म दिया है। डीबीटी यानी प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण से लीकेज की आशंका समाप्त हो गई है। उदाहरण के लिए एलपीजी सब्सिडी हस्तांतरण से लीकेज में 24 प्रतिशत की कमी आई है। आधार की उपयोगिता ने डीबीटी के तहत 1167 करोड़ लाभार्थियों को 34 करोड़ रुपये से अधिक की सुविधा प्रदान की है। इसके साथ ही सरकार ने स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ जैसे सामाजिक कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन से देश के ढांचे में बुनियादी बदलाव का रास्ता तैयार किया है। वन नेशन, वन राशन कार्ड के माध्यम से राज्यों में राशन कार्ड की निर्बाध पोर्टेबिलिटी का विस्तार देश भर की पूरी आबादी तक हो गया है।

हर वर्ष दो करोड़ रोजगार का पीएम मोदी का वादा 10 साल में भी पूरा नहीं

प्रथम पृष्ठ से आगे

कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा, पहले कार्यकाल के वक्त हर वर्ष दो करोड़ रोजगार का पीएम मोदी का वादा 10 साल में भी पूरा नहीं हो पाया। किसानों के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं देने से लेकर सब्सिडी घटाने जैसे मुद्दों का जिक्र किया गया है। स्याह पत्र में सरकार पर कुछ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए विशेष रूप से अदाणी समूह का जिक्र किया गया है। सामाजिक अन्याय से जुड़े आरोपों में एससी–एसटी और ओबीसी की सत्ता में वाजिब भागीदारी नहीं होने पर निशाना साधते हुए जनगणना और जातिवार जनगणना नहीं कराने को सरकार की नाकामी बताया गया है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म सरीखी अन्याय की घटनाएं बढ़ने का हवाला देते हुए महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में सरकार की उदासीनता पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा विशेष रूप से सीमा पर चीन के साथ 2020 से जारी टकराव के क्रम में मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया गया है कि किसी के सीमा में नहीं घुसने के पीएम के बयान का खामियाजा देश भुगत रहा है। एलएसी पर भारत अपने 65 में से 26 पेट्रोलिंग प्वाइंट पर नहीं जा सकता, क्योंकि वह बफर जोन बना दिया गया है। इसकी वजह से हमारी काफी जमीन चीन के प्रभुत्व में चली गई है। रक्षा बजट में कटौती से लेकर अग्निवीर योजना की खामी गिनाते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया गया है। राजनीतिक अन्याय का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार चुनी हुई गैरभाजपा सरकारों को गिरा रही है और सीबीआइ, इडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। इससे देश के लोकतंत्र को खतरा है। खरगे ने दावा किया कि इन केंद्रीय एजेंसियों के जरिये दानदाताओं को डरा–धमका कर भाजपा सरकार चुनावी बांड से पैसा जुटा रही है और इसी पैसे का इस्तेमाल लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। खरगे ने कहा कि बीते 10 वर्षों के दौरान कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गैरभाजपा सरकारों को गिराने के लिए भाजपा द्वारा 411 विधायकों को 'खरीदा' जा चुका है। चुनावी निरंकुशता को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए पार्टी ने कहा है कि मोदी सरकार ने संघवाद को भी कमजोर करते हुए गैरभाजपा शासित राज्यों को वित्तीय मदद देने में अड़चनें पैदा की हैं। राज्यपालों के जरिये विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को लगातार अस्थिर किया जा रहा है। खरगे ने यह भी कहा कि 2024 में कांग्रेस विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए के दलों के साथ मिलकर भाजपा शासन के 10 सालों के अन्याय काल से देश को मुक्ति दिलाएगी।

2014 में एनडीए की सरकार बनी तो अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी

प्रथम पृष्ठ से आगे

लोकसभा चुनाव 2024 की बढ़ी सरगर्मियों के बीच जारी श्वेत पत्र के मुताबिक ऐसी अवस्था में वर्ष 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो अर्थव्यवस्था के नाजुक स्थिति में होने की वजह से उनके समक्ष चुनौती बड़ी थी। फिर शुरू हुआ आर्थिक मोर्चे पर कठोर निर्णय लेने का सफर ताकि अर्थव्यवस्था को फिर से गतिशील बनाई जा सके, निवेशकों के मन में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति सकारात्मक भाव पैदा किया जा सके और देश को शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया जा सके। इस काम के लिए समग्र रूप से आर्थिक सुधार कार्यक्रम की प्रक्रिया अपनाई गई। राष्ट्र पहले (नेशन फर्स्ट) की नीति अपनाने से इन्फ्रास्ट्रक्चर और लाजिस्टिक सिस्टम में सुधार किया गया ताकि निवेश को आकर्षित किया जा सके और भारत वैश्विक वैल्यू चेन में शामिल हो सके। नेशनल हाईवे, रेल रूट का विद्युतीकरण, एयरपोर्ट की संख्या में बढ़ोतरी के साथ जीरो बैलेंस वाले बैंक खाते, शौचालय का निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, सस्ती दवाइयां, ग्रामीण इलाकों में सस्ते मकान, आप्टिकल फाइबर, असंगठित क्षेत्रों को पेंशन सुविधा जैसे कई सामाजिक सुधार कार्यक्रम अपनाए गए। कर के मोर्चे पर जीएसटी को लागू किया गया और करदाताओं का भरोसा जीतकर आयकर का दायरा भी बढ़ाया गया। वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार ने राजस्व खर्च में लगातार कमी की और पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी की गई। वित्त वर्ष 2013–14 में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर होने वाला खर्च 1.9 लाख करोड़ था जो वित्त वर्ष 2023–24 में बढ़कर 9.5 लाख करोड़ हो गया। टेलीकाम सेक्टर को बढ़ाते हुए 5जी सेवा तक शुरू की गई जिससे डिजिटल सेवा में भारत दुनिया का नेता बन गया और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की मदद से सभी सेक्टर को वैल्यू एडीशन करने का मौका मिला।

संप्रग काल में एक के बाद एक घोटालों ने किया विकास को बाधित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जारी श्वेत पत्र में मोदी सरकार ने आरोप लगाया है कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान एक के बाद एक बड़े घोटाले हुए। श्वेत पत्र के दूसरे भाग को पूरी तरह से घोटाले को समर्पित कर सरकार ने संप्रग काल के दौरान हुई वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के उद्देश्य से लिए गए फैसलों को उजागर किया है। श्वेत पत्र में मनमोहन सिंह सरकार के 15 हाईप्रोफाइल घोटालों को गिनाते हुए ध्यान दिलाया गया है कि इन घोटालों के खिलाफ अन्ना हजारे के नेतृत्व में शुरू हुए अनशन ने जनआंदोलन का रूप ले लिया था।

श्वेत पत्र में मोदी सरकार ने याद दिलाया है कि मनमोहन सिंह सरकार के 10 सालों में किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन से लेकर सरकारी खरीद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अहम खरीद तक में घोटाले हुए। इसकी वजह से जहां सरकारी खजाने को लाखों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, वहीं इसने आम जनता के भरोसे को भी हिला दिया। सीएजी की रिपोर्ट से लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई और अदालती सुनवाई तक में इन घोटालों की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही थी। सीएजी ने कोयला घोटाले में 1.86 लाख करोड़ रुपये और 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में 1.76 लाख करोड़ रुपये का सरकारी खजाने को नुकसान होने का अनुमान लगाया था। श्वेत पत्र के अनुसार ये घोटाले सिर्फ आरोप भर नहीं थे, बल्कि एजेंसियों की जांच के बाद अदालती सुनवाई में इनमें शामिल दोषियों को सजा भी हो रही है। श्वेत पत्र के अनुसार घोटाले और एजेंसियों द्वारा उनमें शामिल हाईप्रोफाइल आरोपितों के खिलाफ की गई कार्रवाई ने मनमोहन सरकार में पालिसी पैरालाइसिस (नीतिगत पंगुपन) की स्थिति पैदा कर दी। घोटाले के कारण 2जी स्पेक्ट्रम और कोयला खदानों के आवंटन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने से निवेशकों के विश्वास को झटका लगा और वे विदेश में निवेश की ओर रुख करने लगे। अधिकारी फैसला लेने में डरने लगे और रक्षा उत्पादों की खरीद तक के फैसले नहीं लिए जा सके।

संप्रग सरकार के हाईप्रोफाइल घोटाले

- **कोयला घोटाला :** कोयला ब्लाकों के आवंटन में घोटाले के कारण सुप्रीम कोर्ट ने 204 आवंटनों को रद्द कर दिया।
- **राष्ट्रमंडल खेल घोटाला :** देश की प्रतिष्ठा के अहम खेल आयोजन की तैयारियों में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए।
- **2जी स्पेक्ट्रम घोटाला :** घोटाले की भेंट चढ़े स्पेक्ट्रम आवंटन को सुप्रीम कोर्ट से रद्द किए जाने से भारत में टेलीकाम विस्तार योजनाओं को गहरा धक्का लगा।
- **शारदा चिटफंड घोटाला :** पोंजी स्कीम के सहारे लाखों निवेशकों से जुटाए गए करोड़ों रुपये का बंदरबाट किया गया।
- **आइएनएक्स मीडिया घोटाला :** मीडिया कंपनी में विदेशी निवेश की मंजूरी देने में अनियमितता और मनी लांड्रिंग।
- **एयरसेल–मैक्सिस घोटाला :** दूरसंचार कंपनी में विदेशी निवेश को मंजूरी देने में अनियमितता और रिश्वत लेने का आरोप।
- **एंट्रिक्स–देवास घोटाला :** इसरो के एस–बैंड के आवंटन में गड़बड़ी कर देवास मल्टीमीडिया को अनुचित लाभ पहुंचाया गया
- **नौकरी के बदले जमीन घोटाला :** रेलवे में नौकरी देने की एवज में जमीन हड़पने का मामला
- **पंचकूला और गुरुग्राम में प्राइम लैंड आवंटन घोटाला :** प्राइम लैंड को अधिग्रहण से मुक्तकर और औद्योगिक भूमि को नजदीकी सहयोगियों को देने का मामला
- **जम्मू–कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला :** फर्जी बैंक खाते खोलकर 44 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई।
- **एम्ब्रेयर डील घोटाला :** ब्राजील की कंपनी एयरोस्पेस से जहाज खरीद में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी।
- **पिलाटस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट घोटाला :** वायुसेना के लिए 75 पिलाटस ट्रेनर विमानों की खरीद में भ्रष्टाचार
- **हाक विमान खरीद घोटाला :** रोल्स रायस से हाक विमानों की खरीद में भ्रष्टाचार।
- **आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला :** सेना की जमीन पर अपार्टमेंट बनाने और उनके आवंटन में गड़बड़ी।
- **अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर खरीद घोटाला :** वीवीआइपी के लिए हेलीकाप्टर खरीद में बड़े पैमाने रिश्वतखोरी के आरोप

नई दिल्ली में गुरुवार को केंद्र सरकार के विरोध में जंतर–मंतर पर प्रदर्शन में शामिल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सीपीआइ नेता सीताराम येचुरी, केरल के सीएम पिनाराई विजयन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सीपीआइ नेता डी राजा और नेशनल कांफ्रेंस प्रमुख फारूख अब्दुल्ला। जागरण

आइएनडीआइए 'भ्रष्टों का समूह', भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से जनता खुश : भाजपा

- भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी की लड़ाई को समर्थन दे रहे सभी भारतीय

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने के विपक्षी दलों के आरोपों को लेकर गुरुवार को उन पर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भ्रष्ट लोगों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से जनता 'खुश' है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लोगों को लगता है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और मोदी सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबले के लिए विपक्षी दलों द्वारा गठित 'आइएनडीआइए' गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह 'भ्रष्टों का गठबंधन' है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि हम भ्रष्टाचार के दीमक को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों को लोगों को एक–एक पाई लौटानी होगी और भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। भाटिया ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री की लड़ाई को 140 करोड़ भारतीय समर्थन दे रहे हैं।

****

19 फरवरी से विशाखापत्तनम में मेगा नौसैनिक युद्धाभ्यास 'मिलन' की मेजबानी भारत करेगा। इस युद्धाभ्यास में 50 देशों की नौसेनाओं के शामिल होने की संभावना है। मिलन द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। यह 1995 में भारत की 'लुक ईस्ट' की नीति के तहत इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 9 फरवरी, 2024

तीन माह में तैयार हो जाएगा राम मंदिर का प्रथम तल

प्रवीण तिवारी, अयोध्या

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के शेष हिस्से का निर्माण शुरू हो गया है। मंदिर निर्माण समिति की बैठक में तय हुआ कि प्रथम तल का अवशेष कार्य मात्र तीन माह में पूरा कर लिया जाएगा।

प्राण प्रतिष्ठा के पहले मंदिर का भूतल पूर्ण रूप से तैयार कर दिया गया था, लेकिन प्रथम तल का 80 प्रतिशत निर्माण ही हो सका है। मंदिर के छह शिखरों में रंग, नृत्य, भजन-कीर्तन व प्रार्थना मंडप के शिखर तैयार हैं। अब गुड़ी मंडप का निर्माण प्रारंभ हो गया है। मंदिर के द्वितीय तल के साथ ही मुख्य शिखर का निर्माण भी प्रारंभ हो जाएगा। मंदिर के दूसरे तल का निर्माण इसके समानांतर प्रारंभ होगा। दूसरे तल में कुल एक लाख 82 हजार घन फीट गढ़ी हुई शिलाएं प्रयुक्त होनी हैं। शिलाओं की आपूर्ति राजस्थान के सिरोही जिले की कार्यशालाओं से होगी। इन शिलाओं की आपूर्ति भी जल्द प्रारंभ होगी। समिति के सदस्यों ने वेंडरों के साथ मिल कर इसकी योजना तैयार की है। राम जन्मभूमि परिसर में ही अतिथियों के निवास करने के लिए रेस्ट रूम का निर्माण किया जाएगा। यात्री सुविधा केंद्र के शेष हिस्से का निर्माण किया जाएगा।

फास्ट लेन से कम समय में दर्शन: रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु तीन लेन से गुजरते हैं। जब भक्तों की संख्या कम होती है तो इसमें एक लेन को वीआइपी लेन बना दिया जाता है। इसके अतिरिक्त फास्ट लेन से जाकर कम समय में रामलला का दर्शन किया जा सकता है।

रामलला के दरबार में अरुणाचल, सूरीनाम के बाद फिजी की हाजिरी

जागरण संवाददाता, अयोध्या

श्रीराम मात्र किसी समूह-संप्रदाय तक सीमित नहीं हैं, वह समग्र मानवता के प्रेरक-मार्गदर्शक हैं। रामलला के सम्मुख यदि मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश की सरकार और बुधवार को सूरीनाम की नेशनल असेंबली के सदस्य नतमस्तक हुए तो गुरुवार को फिजी के उप प्रधानमंत्री बिमानप्रसाद रामलला के सम्मुख शरणागत हुए और पूजन-प्रार्थना के साथ रामलला की आरती भी की। इस अवसर पर फिजी के उप प्रधानमंत्री ने रामलला के प्रति स्वयं के साथ अपने संपूर्ण देश की आत्मीयता अर्पित की। यह बता कर कि भारत की तरह फिजी भी राम भक्ति की भावधारा से अनुप्राणित है। लीला एवं कथा की मंडलियां जगह-जगह अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से रामकथा का प्रचार-प्रसार करती हैं। बिमानप्रसाद ने याद दिलाया कि भारत का फिजी से बहुत पुराना संबंध है और यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। स्पष्ट किया कि फिजी की नौ लाख 25 हजार की जनसंख्या में 28 प्रतिशत हिंदू हैं और इनमें से अधिकांश के पूर्वज उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ही थे।

सरकारें नतमस्तक : फिजी के उप प्रधानमंत्री ने किया रामलला को नमन

फिजी के उप प्रधानमंत्री बिमानप्रसाद (बाएं) का स्वागत करते मंत्री अनिलराजभर (मध्य में) एवं जिलाधिकारी नितीश कुमार (दाएं)। जागरण

शृंगवेरपुर में निषादराज गुह के किले से हटवाकर रहूंगा मस्जिद : संजय निषाद

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

मत्स्य मंत्री ने विधान परिषद में कहा-गलत ढंग से बनी है मस्जिद

बोले- मछुआ समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे मोदी

अयोध्या में भगवान श्रीराम के विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद एक-एक कर हिंदू धर्म स्थलों पर बनाई गईं मस्जिदों को हटाने के लिए विरोध तेज हो गया है। बाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण के बाद अब प्रयागराज के शृंगवेरपुर में निषादराज गुह के किले में बनाई गई मस्जिद को हटाने के लिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष व राज्य के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने ताल ठोंक दी है। गुरुवार को विधान परिषद में उन्होंने कहा कि अवैध ढंग से बनाई गई मस्जिद को हटाने के लिए संघर्ष करेंगे।

मत्स्य मंत्री निषाद ने कहा कि वर्ष 1977 में केंद्र सरकार ने शृंगवेरपुर में निषादराज के किले की खुदाई कराई थी, उस समय वहां कोई मस्जिद नहीं थी। ऐसे में गलत ढंग से बनी मस्जिद हटाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को पूरी तरह तैयार हैं। निषादराज के किले से मस्जिद हटवाने के लिए पूरा मछुआ समाज एकजुट है। उन्होंने कहा कि मछुआ समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए वह प्रयासरत हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि मोदी सरकार जल्द यह तोहफा देगी। ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है।

संजय निषाद। फाइल

आरोप लगाया कि केंद्र में पूर्ववर्ती कांग्रेस गठबंधन की सरकार व प्रदेश में सपा-बसपा सरकार ने हमारे समाज के साथ हमेशा अन्याय ही किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मत्स्य संपदा योजना से कल्याण हो रहा है। मछुआ कल्याण कोष से गांवों में मैरिज हाल बनाए जा रहे हैं और इसमें डिजिटल लाइब्रेरी भी बनवाई जा रही है।

...पानी में पैसा डालिए, डेढ़ साल में होगा दोगुणा : विधान परिषद में बजट पर चर्चा के दौरान मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने चुटकी भी ली। बोले, आप बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो वह 10 वर्ष में दोगुणा होता है। अगर आप यह पैसा पानी में डालेंगे तो डेढ़ वर्ष में ही दोगुणा हो जाएगा। उनके कहने का मतलब था कि मत्स्य पालन में काफी संभावनाएं हैं।

न्यूज गैलरी

इंजीनियर को हनी ट्रैपिंग में फंसाने में तीन गिरफ्तार

चेन्नई : ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने साफ्टवेयर इंजीनियर को हनी ट्रैपिंग में फंसाने में युवती समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया। युवती अपने दो साथियों के साथ मिलकर इंजीनियर से उसके अश्लील फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर पैसों की मांग कर रही थी। इस पर इंजीनियर ने आरोपितों को 25 हजार रुपये डिजिटल ट्रांसफर कर दिए और शेष पैसे बाद में देने को कहा। आरोपितों के मानने पर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। (आइएएनएस)

चेन्नई में निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी

चेन्नई : चेन्नई शहर के कुछ निजी स्कूलों को गुरुवार को ई-मेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस सूचना पर स्कूलों के बाहर अभिभावकों की भीड़ लग गई। पुलिस और बम स्क्वाड जांच के लिए स्कूल पहुंच गई। पुलिस ई-मेल भेजने वाले आरोपितों की तलाश में जुट गई है। इसके साथ ही पुलिस ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। (प्रेट्र)

मंत्री सेंथिल बालाजी के घर की ईडी ने फिर ली तलाशी

चेन्नई : ईडी ने गुरुवार को जेल में बंद तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के करुर स्थित आवास पर छापेमारी की। इस घर पर मंत्री के माता-पिता रहते हैं। 13 जून के बाद मंत्री के पारिवारिक आवास पर यह दूसरी छापेमारी है। पांच अधिकारियों की टीम ने सात माह से फरार बालाजी के भाई अशोक कुमार के ठिकाने के बारे में पूछताछ की। गत वर्ष 14 जून को मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार बालाजी अभी पुझल जेल में बंद हैं। (आइएएनएस)

बाबा सिद्दीकी ने छोड़ी कांग्रेस अब राकांपा में होंगे शामिल

मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी ने गुरुवार को कहा कि उन्हें पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वह जल्द ही अजीत पवार के नेतृत्व वाले राकांपा में शामिल होंगे। मिलिंद देवड़ा के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना में शामिल होने के बाद सिद्दीकी एक माह के भीतर कांग्रेस छोड़ने वाले दूसरे नेता है। सिद्दीकी का बेटा जीशान कांग्रेस विधायक है लेकिन उन्होंने कहा कि वह अपना फैसला खुद करेगा। (प्रेट्र)

विशाखापत्तनम में हादसा, मालगाड़ी पटरी से उतरी

विशाखापत्तनम : आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में चिमिदिपल्ली रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वालटेयर मंडल रेल प्रबंधक सौरभ प्रसाद ने बताया कि सूचना पर अधिकारियों ने घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लिया। (एएनआइ)

हेमंत के दिल्ली आवास से जब्त कार के तार कांग्रेस के धीरज साहू से जुड़े

शिकंजा ▶ पूछताछ के लिए ईडी ने राज्यसभा सदस्य धीरज साहू को किया समन

29 जनवरी को दिल्ली में छापेमारी के दौरान ईडी ने जब्त की थी कार

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से जब्त बीएमडब्ल्यू एसयूवी कार का कनेक्शन राज्यसभा सदस्य धीरज साहू से जुड़ा है। ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि जब्त कार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नहीं है। इसका संबंध झारखंड के कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू से है। कार का रजिस्ट्रेशन साहू के मानेसर स्थित घर के पते पर है। इस मामले में ईडी ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू को समन भेजकर 10 फरवरी को पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी के जोनल कार्यालय में बुलाया है।

राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तलाश में दिल्ली स्थित झारखंड के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर 29 जनवरी को छापेमारी की थी। इस दौरान सोरेन नहीं मिले थे। आवास परिसर से ईडी ने एक बीएमडब्ल्यू एसयूवी कार जब्त की थी। अब इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने राज्यसभा सदस्य धीरज साहू को बुलाया है।

ईडी साहू से हेमंत सोरेन और बीएमडब्ल्यू कार से संबंधित सवाल करेगी। चर्चा है कि यह कार धीरज साहू ने हेमंत सोरेन को गिफ्ट में दी थी। हालांकि ईडी द्वारा साहू से पूछताछ के बाद सच्चाई सामने आएगी। ईडी की टीम इस मामले की गहन पड़ताल की जाएगी।

350 करोड़ की बरामदगी के बाद चर्चा में आए थे कांग्रेस सांसद धीरज साहू

आयकर विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के ओडिशा स्थित बौध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड (बीडीपीएल) में पिछले साल छापेमारी की थी। इस दौरान 351.8 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे। इसके बाद साहू देशभर में चर्चा में आ गए थे। ईडी को संदेह है कि दिल्ली स्थित सीएम आवास से जब्त कार किसी बेनामी तरीके से साहू और हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ है।

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू।

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जारी है पूछताछ

जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद से रिमांड पर ईडी की पूछताछ जारी है। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अन्य अचल संपत्तियों के अर्जित करने के मामले में भी पूछताछ शुरू की है। बरियातू की 8.5 एकड़ जमीन को हड़पने की कोशिश मामले में ईडी की पूछताछ लगभग पूरी हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को भी ईडी मोबाइल का डेटा निकालने के लिए बुलाएगी ताकि इस प्रकरण में कुछ और तथ्य जुटाया जा सके।

झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन।

राजभवन आने से पहले ही ईडी की हिरासत में थे हेमंत सोरेन : राज्यपाल

राज्य ब्यूरो, रांची

राजभवन से राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की एक अखबार में छपी खबर का किया खंडन

राज्यपाल ने हेमंत और आइएनडीआइए द्वारा राजभवन पर लगाए आरोपों को किया खारिज

झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तथा सरकार बनाने के लिए न्योता देने में देरी को लेकर हेमंत सोरेन और गठबंधन के नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने सरकार बनाने का न्योता देने से पहले राजभवन से राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा से जुड़ी एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर (दैनिक जागरण में नहीं) का भी खंडन किया। गुरुवार को राजभवन में पत्रकारों से राज्यपाल ने कहा, ईडी द्वारा हेमंत को राजभवन में गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने राजभवन आने से पहले ही ईडी की हिरासत में थे। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए 26.5 घंटे के अंदर झारखंड में नई सरकार का गठन करा दिया। उन्होंने यह कतई नहीं कहा कि नई सरकार 24 घंटे में बहुमत साबित करे। इसके लिए उन्हें 10 दिनों का समय दिया गया था। सवाल उठाया कि लोग कैसे कह सकते हैं कि पूरे मामले में राजभवन की कोई भूमिका है और सरकार गिराने में राजभवन भी शामिल है? राज्यपाल ने कहा, हेमंत सोरेन ने ही अपने इस्तीफे में स्वीकार किया है कि वे ईडी की हिरासत में हैं तथा वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। ईडी ने उनके प्रधान सचिव डा. नितिन मदन कुलकर्णी को फोन कर कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद मुख्य सचिव एल खियांगते ने भी उनके प्रधान सचिव को फोन कर बताया कि हेमंत इस्तीफा देना चाहते हैं। सीएमओ से भी ऐसी जानकारी आई।

सीपी राधाकृष्णन। फाइल

राज्यपाल ने कहा, उन्हें पहले सूचना नहीं दी गई थी कि हेमंत के साथ आनेवाले विधायक सरकार बनाने का दावा करेंगे। अचानक उन्होंने 43 विधायकों का समर्थन होने की बात कहते हुए दावा प्रस्तुत कर दिया। सरकार बनाने का न्योता देने में देरी के सवाल पर राज्यपाल ने कहा, मीडिया में जो खबरें आ रही थीं, उससे लग रहा था कि चम्पाई सोरेन के पास बहुमत नहीं है। उनके पास एक-दो फोन भी आए थे, जिसमें समर्थन नहीं देने की बात कही गई थी। ऐसी परिस्थिति में सरकार बनाने का न्योता देने में कुछ समय लेना जरूरी था। उन्होंने कहा कि कि सरकार बनाने का न्योता देने से पहले उन्होंने कानूनी सलाह ली। हेमंत सोरेन के आफिस आफ प्राफिट मामले में उन्होंने कहा कि वे चुनाव आयोग के बंद लिफाफे को भी देखेंगे।

रोजी-रोटी की तलाश में सुबह अमृतसर से निकले और शाम को श्रीनगर में हो गया हमला

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

12 घंटे मौत से जूझने के बाद रोहित मसीह ने भी तोड़ा दम, अमृतपाल की मौके पर हो गई थी मौत

अमृतसर से रोहित मसीह बड़ी उम्मीदों से बुधवार सुबह अपने दोस्त अमृतपाल सिंह के साथ श्रीनगर के लिए निकला था। रोहित अपने स्वजन को यकीन दिलाकर आया था कि कश्मीर में वह रोजी रोटी कमाएगा और उनका भी सहारा बनेगा, लेकिन उसी रोज शाम को आतंकियों ने दोनों दोस्तों पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया। शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, सौरा अस्पताल में लगभग 12 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद गुरुवार सुबह रोहित ने दम तोड़ दिया। घर से निकलने के अगले ही दिन अमृतसर के चमियारी अजनाला गांव में रोहित के स्वजन तक उसकी मौत की खबर भी पहुंच गई।

अमृतपाल सिंह। फाइल

रोहित मसीह। फाइल

बताया जा रहा है कि रोहित मसीह के परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। इसके साथ ही इस हमले में मरने वालों की संख्या दो हो गई है। अमृतपाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। वर्ष 2019 के बाद से टारगेट किलिंग में ईसाई समुदाय के किसी व्यक्ति की हत्या की कश्मीर में यह पहली घटना है। पुलिस ने बताया कि आतंकियों ने श्रीनगर के शाला कदल क्षेत्र में बुधवार शाम को अमृतपाल सिंह और रोहित मसीह पर उस समय हमला किया था, जब वह अपने किराये के कमरे में लौट रहे थे। आतंकियों ने दोनों पर सात गोलियां दागी थीं। रोहित के पेट में गोलियां लगीं थीं। अमृतपाल बढ़ई था और वह पांच वर्ष से श्रीनगर में काम कर रहा था। रोहित को अमृतपाल सिंह ही अपने साथ लाया था। अमृतपाल और रोहित के करीबियों ने बताया कि दोनों आतंकियों के हमले का शिकार होने से कुछ समय पहले ही अमृतसर से श्रीनगर पहुंचे थे। बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आतंकियों को इस बात की पहले से जानकारी थी कि अमृतपाल सिंह व रोहित मसीह शाम को अमृतसर से श्रीनगर पहुंच जाएंगे। वहीं संबंधित अधिकारियों ने बताया कि जिस जगह हमला हुआ है, वहां से कुछ सुराग जमा किए गए हैं।

दोनों दोस्त की मौत भी साथ आई

अमृतसर : पंजाब के जंडियाला के गांव चमियारी निवासी अमृतपाल और रोहित मसीह बचपन के दोस्त थे। अमृतपाल सिंह बढ़ई का काम करता था। गुरदासपुर के ठेकेदार की ओर से उसे श्रीनगर में काम करने लिए भेजा गया तो वह अपने दोस्त रोहित को अपने साथ सहयोगी के रूप में लेकर मंगलवार को ही श्रीनगर रवाना हुआ था। श्रीनगर में दोनों दोस्त की एक साथ हुई मौत के बाद गांव में हर कोई भावुक था। अमृतपाल का शव गुरुवार सुबह करीब 11 बजे गांव पहुंचा और दोपहर को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अमृतपाल के पिता ने शव को मुखाग्नि दी। बता दें कि सात भाई-बहनों में सबसे छोटे अमृतपाल की एक महीने पहले ही सगाई हुई थी। रोहित का शव खबर लिखे जाने तक गांव नहीं पहुंचा था।

पाक के मेडिकल कालेजों में प्रवेश की आड़ में आतंकी फंडिंग में लिप्त हुर्रियत नेता गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

पाकिस्तान के मेडिकल कालेजों में प्रवेश की आड़ में कश्मीर में आतंकी फंडिंग के खेल में लिप्त एक हुर्रियत नेता अब्दुल्ला शाह को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी उससे पूछताछ में जुट गई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने वर्ष 2021 में पाक के मेडिकल, इंजीनियरिंग व अन्य कालेजों में प्रदेश के छात्रों के दाखिले की आड़ में होने वाली आतंकी फंडिंग का मामला दर्ज किया था। बीते माह ईडी ने दक्षिण कश्मीर के मीरबाइज काजी यासिर समेत विभिन्न आरोपितों की पांच करोड़ की चल-अचल संपत्ति को अटैच किया था।

कुपवाड़ा का अब्दुल्ला शाह हुर्रियत कान्फ्रेंस की दूसरी पंक्ति के नेताओं में गिना जाता रहा है। जांच में पता चला कि वह पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना मंजूर अहमद शाह के सीधे संपर्क में था। उसके जरिये एमबीबीएस व अन्य पाठ्यक्रमों में कश्मीरी छात्रों के दाखिले के एवज में मोटी रकम जमा करता था। अब्दुल्ला को ईडी ने श्रीनगर के सीबीआइ विशेष अदालत में पेश किया। कोर्ट ने उसे 13 फरवरी तक रिमांड पर भेजा है।

ईडी की कार्रवाई

- आरोपित सीमा पार आतंकी हैंडलर मंजूर अहमद के लगातार संपर्क में था
- ईडी ने पूछताछ के लिए अदालत से 13 फरवरी तक के रिमांड पर ले लिया
- कश्मीरी छात्रों के दाखिले के लिए मोटी रकम वसूली जाती थी

आरोपितों ने व्यक्तिगत खातों में जमा कराया पैसा

ईडी ने जांच में पता लगाया कि यह पैसा आरोपितों ने अपने व्यक्तिगत खातों और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित अल-जबार ट्रस्ट के बैंक खातों में प्राप्त किया। इसके बाद पाक में बैठे हैंडलरों मंजूर अहमद शाह और अल्ताफ अहमद बट के निर्देशानुसार इस पैसे का प्रयोग देश में आतंकी गतिविधियों में किया था।

कई हुर्रियत नेता व उनके करीबी पकड़े जा चुके

ईडी के अनुसार, पाकिस्तान सरकार अपने देश में कश्मीरी आतंकियों और अलगाववादियों के बच्चों को एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आरक्षण प्रदान करती है। इन सीटों पर कश्मीर से कई लोगों को अलगाववादी दाखिला दिलाते रहे हैं। इसकी आड़ में वह पैसा जुटाकर उसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में करते रहे हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने वर्ष 2021 में इस मामले की जांच शुरू की थी। अब तक एक दर्जन हुर्रियत नेता व उनके करीबियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अदालत में जो आरोपपत्र दायर किया है, उसके आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपपत्र में मोहम्मद अकबर भट, फातिमा शाह, अल्ताफ अहमद भट, काजी यासिर सैयद खालिद गिलानी उर्फ खालिद अंद्राबी और अन्य को आरोपित बनाते हुए दावा किया कि ये लोग पाक में बैठे हैंडलरों की मदद से जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए पाकिस्तान के कालेजों में एमबीबीएस व अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिला सुनिश्चित बनाते थे।

भू- अधिग्रहण में कुप्रबंधन

संसद की लोक लेखा समिति ने सदन के पटल पर रखी रिपोर्ट, इस परियोजना में बिहार के चार जिले वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण शामिल हैं

83 गुना बढ़ी हाजीपुर-संगौली रेल लाइन की लागत

नई दिल्ली, प्रेट्र : वर्ष 2003-04 में 24.66 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृत हाजीपुर-सगौली नई लाइन परियोजना पर रेलवे प्रशासन की अनिर्णय की स्थिति भारी पड़ी और जनवरी 2019 में इसकी लागत में 2,066.78 करोड़ रुपये की भारी वृद्धि दर्ज की गई। संसद की लोकलेखा समिति (पीएसी) ने अपनी रिपोर्ट यह बात कही है।

बुधवार को लोकसभा में 'भूमि अधिग्रहण के मामले में रेलवे प्रशासन के अनिर्णय के कारण नुकसानः पूर्व मध्य रेलवे' शीर्षक से पेश गई यह रिपोर्ट नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की 2021 की रिपोर्ट के निष्कर्षों में से एक पर आधारित है।

पीएसी ने कहा है कि विस्तृत जांच करने के बाद उसने पाया कि रेलवे में विवेकपूर्ण निर्णय लेने और समय पर भुगतान के अभाव के कारण हाजीपुर-सगौली परियोजना की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई जिसे टाला जा सकता था। यह सावधानीपूर्वक वित्तीय योजना और भूमि अधिग्रहण नीतियों के पालन के महत्व को रेखांकित करता है।

प्रतीकात्मक

2003
में परियोजना की अनुमानित लागत थी 24.66 करोड़ रुपये

2019
में इसकी लागत 2,066.78 करोड़ रुपये हो गई

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2003-04 में रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत हाजीपुर-सगौली नई लाइन परियोजना में भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं में कई वित्तीय खामियां होती गईं, जिससे इसकी लागत में भारी बढ़ोतरी हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस परियोजना में बिहार के चार जिले वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि समिति की जांच के दौरान पूर्वी चंपारण में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में कुप्रबंधन का पता चला है। राज्य के अधिकारियों के बार-बार अनुरोध के बावजूद रेलवे प्रशासन 962.59 एकड़ के अधिग्रहण के लिए 2006 में अत्यधिक राशि मानकर 58.76 करोड़ रुपये जमा करने में विफल रहा।

रिपोर्ट के अनुसार रेलवे ने शुरुआत में अपर्याप्त कोष की समस्या बताई, जिसके फलस्वरूप भूमि अधिग्रहण के लिए भुगतान में देरी हुई। लागत में इस तरह की भारी वृद्धि को रोकने के लिए मंत्रालय की ओर से भविष्य में मजबूत वित्तीय नियोजन तंत्र लागू करने की आवश्यकता जताई गई है।

एक अन्य मामले में पीएसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा एक अतिरिक्त सीएनसी होरिजेंटल बोरिंग और मिलिंग मशीन की अविवेकपूर्ण खरीद से रेलवे को 25.43 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ। यह रिपोर्ट भी बुधवार को लोकसभा में पेश की गई।

रिपोर्ट में मंत्रालय को भविष्य में इस तरह के निरर्थक व्यय की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तय निर्देशों के अनुरूप खरीद नीतियों की आवधिक समीक्षा के लिए एक तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की गई है। एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा टैरिफ मीटर के प्रविधान में देरी के कारण रेलवे को 75 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा।

****

गंभीर अपराध मामले में सुनवाई में देरी के आधार पर नहीं मिल सकती जमानत

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने एक खालिस्तानी आतंकी को जमानत देने से इन्कार करते हुए गुरुवार को कहा कि गंभीर अपराध मामले में सुनवाई में देरी के आधार पर जमानत नहीं जा सकती है। आरोपित पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए हैं। आरोपित प्रतिबंधित संगठन सिख फार जस्टिस (एसएफजे) का सदस्य है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि एसएफजे के सदस्यों द्वारा समर्थित आतंकी गतिविधियों में आरोपित की संलिप्तता है, जिसमें विभिन्न माध्यम से बड़ी मात्रा में धन का आदान-प्रदान शामिल है। यदि आरोपित को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो पूरी आशंका है कि वह मामले के प्रमुख गवाहों को प्रभावित करेगा जिससे न्याय की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। जस्टिस एमएम सुंदरेश व जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) द्वारा जांच किए गए यूएपीए मामले में गुरविंदर सिंह उर्फ गुरप्रीत सिंह गोपी को जमानत देने से इन्कार करने वाले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। 19 अक्टूबर, 2018 को अमृतसर में एक फ्लाईओवर पर खालिस्तान समर्थक बैनर लटकाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पंजाब पुलिस ने जांच के दौरान एसएफजे माड्यूल का भंडाफोड़ किया था। अप्रैल 2020 में मामले की जांच एनआइए को सौंपी गई। कोर्ट ने गुरविंदर सिंह के वकील की दलील को भी खारिज किया कि टेरर फंडिंग चार्ट में अपीलकर्ता का नाम नहीं है, इसके बावजूद गुरविंदर पिछले पांच साल से जेल में है इसलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए है।

खालिस्तानी आतंकी को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इन्कार

1983 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में स्थित श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर का अधिग्रहण किया था। न्याय के ताजा फैसले के बाद अब यहां मंदिर में 50 पुजारी होंगे जिसमें प्रधान, कनिष्ठ व सहायक पुजारी आदि श्रेणियां होंगी।

हल्द्वानी में बवाल, उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश

सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़ने गई थी टीम, एक की मौत, कर्फ्यू लगाया

उपद्रवियों ने घेरकर किया पथराव, गोलियां चलाई और की आगजनी, आज बाजार और स्कूल बंद

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी

उत्तराखंड के हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा में सरकारी भूमि पर बने अवैध मदरसा व नमाज स्थल को ध्वस्त करने गई पुलिस, प्रशासन व नगर निगम की टीम पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाने पर भी हमला कर दिया। वहां खड़े पुलिस व मीडियाकर्मियों के दर्जनों वाहनों में आग लगा दी। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह थाने से भागकर जान बचाई। महिला एसडीएम व एसपी समेत करीब 250 से अधिक लोग पथराव में चोटिल लोग अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं। इस दौरान घायल बनभूलपुरा निवासी फहीम को सुशीला तिवारी अस्पताल लाने पर मृत घोषित कर दिया गया। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए डीएम वंदना ने रात में ही कर्फ्यू लगाते हुए उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दे दिए हैं। वहीं, शुक्रवार को बाजार एवं सभी स्कूलों को बंद रखने के भी निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि बनभूलपुरा वही इलाका है जहां पिछले साल रेलवे की भूमि पर बसी 50 हजार की आबादी वाली बस्ती को खाली कराने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। पुलिस-प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली थी। इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और वर्तमान में विचाराधीन है।

मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बनभूलपुरा के मलिक का बगीचा में पिछले दिनों नगर निगम और प्रशासन की टीम अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान यहां अवैध मदरसा और नमाज स्थल भी मिला। गुरुवार दोपहर पुलिस, प्रशासन व नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर अतिक्रमण तोड़ने पहुंची थी। प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के अलावा पुलिस व निगम कर्मचारी मिलाकर करीब 700 लोगों की फोर्स थी, लेकिन जैसे ही बुलडोजर और टीम आगे बढ़े। चारों तरफ से पथराव शुरू हो गया। देखते ही देखते मुस्लिम समुदाय के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सड़क से लेकर घरों की छतों से पत्थर बरसने लगे। एसडीएम कालाढूंगी रेखा कोहली, एसपी हरबंस सिंह, एसओ प्रमोद पाठक समेत पुलिस, निगमकर्मी संग पत्रकारों को पत्थर लगे। छह बजे तक बवाल पूरे क्षेत्र में फैल चुका था। भारी संख्या में उपद्रवी बनभूलपुरा थाने पहुंच गए। जहां उन्होंने थाने के बाहर खड़े पुलिस व मीडियाकर्मियों के एक दर्जन से अधिक वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा अलग-अलग इलाकों में 50 से अधिक वाहन जलाए गए हैं। इसमें पीएसी व पुलिस की दो बस, सड़कों पर खड़े चौपहिया व दोपहिया वाहन शामिल हैं। दर्जनों वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है।

उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में गुरुवार को सरकारी भूमि पर बने नमाज स्थल को हटाए जाने के विरोध में उपद्रवियों ने पथराव किया और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। जागरण

नभूलपुरा मामले में हाई कोर्ट का राहत देने से इन्कार

हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में बनभूलपुरा क्षेत्र के मलिक का बगीचा और अच्छन खान के बगीचे में अतिक्रमण ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता साफिया मलिक व अन्य को किसी तरह की राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 14 फरवरी नियत कर दी है।

यह मामला इतना संवेदनशील था कि सरकार की ओर से महाधिवक्ता व अन्य सरकारी अधिवक्ता पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह भूमि बिना कमिश्नर की अनुमति के कई बार हस्तांतरित की गई है, जबकि यासीन मलिक को यह भूमि कृषि उपयोग के लिए दी गई थी। शर्त थी कि इसमें बिल्डिंग नहीं बनाई जाएगी। यह भूमि ट्रांसफर नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी बिक्री कर दी गई, जो नियम विरुद्ध है। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके पास 1937 की लीज है, जो मलिक परिवार से मिली है। सरकार इसमें कब्जा नहीं ले सकती। नगर निगम की ओर से जारी नोटिस में मदरसे को अवैध बताते हुए ध्वस्त करने को कहा गया है।

विकास और विरासत साथ-साथ आगे बढ़ेंगे : मोदी

- कहा, विविधता में एकता के भारत के मंत्र में विभाजन की गुंजाइश नहीं
- श्रील प्रभुपाद के सम्मान में स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि विविधता में एकता का भारत का मंत्र इतना सरल व व्यापक है कि इसमें विभाजन की गुंजाइश नहीं है। जैसे-जैसे देश आगे बढ़ेगा, विकास व विरासत साथ-साथ आगे बढ़ते रहेंगे। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, अब देश में अयोध्या और मथुरा-वृंदावन के कायाकल्प के साथ वंदे भारत ट्रेन भी चलेगी।

पीएम ने आध्यात्मिक गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, उनकी 150वीं जयंती उस समय मनाई जा रही है, जब महज कुछ दिन पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का सदियों पुराना सपना पूरा हुआ है। इतना बड़ा महायज्ञ संतों के आशीर्वाद से ही पूरा हुआ। आपके चेहरे पर दिख रहा उत्साह रामलला विराजमान की खुशी का भी संकेत देता है। उन्होंने कहा,15वीं शताब्दी के संत चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम के प्रतीक थे। उन्होंने आध्यात्मिकता व साधना को आम लोगों तक पहुंचाया। पीएम ने श्रील प्रभुपाद के सम्मान में स्मारक डाक टिकट व सिक्का भी जारी किया। ज्ञात हो, प्रभुपाद गौड़ीय मिशन के संस्थापक थे। गौड़ीय मिशन ने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं व दुनिया भर में वैष्णव धर्म की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे यह 'हरे कृष्ण' आंदोलन का केंद्र बन गया है।

नई दिल्ली में गुरुवार को प्रगति मैदान के भारत मंडपम में श्रील प्रभुपाद की 150 वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। एएनआइ

न्यूज गैलरी

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आडवाणी से की मुलाकात

नई दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को दिग्गज भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी से भेंट की और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। 2013 के बाद भाजपा से संबंधों में कई बार दरार आने के बावजूद कुमार ने आडवाणी को बहुत सम्मान दिया है। आडवाणी (96) को गत सप्ताह केंद्र सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। (प्रेट्र)

हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेंगे विदेश मंत्री

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस. जयशंकर पर्थ में आयोजित हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने को आस्ट्रेलिया की दो दिवसीय यात्रा करेंगे। आगामी नौ-10 फरवरी को आयोजित सम्मेलन के सातवें संस्करण के उद्घाटन सत्र को विदेश मंत्री एस. जयशंकर संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्रियों, 16 देशों व छह बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पहुंचेंगे। (प्रेट्र)

कृषि मंत्री ने लांच किया सारथी पोर्टल-हेल्पलाइन

नई दिल्ली: कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीआइ) समेत अन्य बीमा उत्पादों की व्यापक जानकारी के लिए सारथी पोर्टल लांच किया। पीएमएफबीआइ से संबंधी शिकायतों के निदान के लिए मंत्री ने कृषि रक्षक पोर्टल व शिकायत दर्ज कराने को हेल्पलाइन नंबर 14447 की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम डिजिटल तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। इस दौरान कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, शोभा करंदलाजे आदि भी मौजूद रहे। (प्रेट्र)

तुलजा भवानी मंदिर ट्रस्ट का अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा

छत्रपति संभाजीनगर: महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में स्थित तुलजा भवानी मंदिर ट्रस्ट का लेखाधिखारी सिद्धेश्वर शिंदे (39) छह लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। एक ठेकेदार की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार को कार्रवाई की। शिंदे ने ट्रस्ट द्वारा संचालित सैनिक स्कूल के विकास कार्यों के बिल को पास करने के लिए ठेकेदार से घूस मांगी थी। पुलिस ने शिंदे के घर से 270 ग्राम सोना व 6.08 लाख की नकदी बरामद की है। (प्रेट्र)

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा

जागरण संवाददाता, वाराणसी

- न्यास परिषद की 105वीं बैठक में सदस्यों ने सर्वसम्मति से दी सहमति
- चार दशक बाद लागू होगी पुजारी सेवा नियमावली

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में चार दशक बाद पुजारी सेवा नियमावली लागू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मंदिर न्यास परिषद की गुरुवार को आयोजित 105वीं बैठक में इस पर चर्चा की गई। समस्त बिंदुओं पर विचार-विमर्श के बाद परिषद ने सर्वसम्मति से सहमति प्रदान कर दी। प्रदेश सरकार ने 1983 में मंदिर का अधिग्रहण किया था। इसके बाद प्रस्ताव तो कई बार पारित हुए, लेकिन सेवा नियमावली अब बन पाई है। इसमें पुजारियों की नियुक्ति प्रक्रिया, वेतनमान, सेवानिवृत्ति समेत समस्त बिंदुओं को शामिल किया गया है। मंदिर में लगभग 50 पुजारी होंगे जिसमें प्रधान, कनिष्ठ व सहायक पुजारी आदि श्रेणियां होंगी।

मंदिर न्यास परिषद की बैठक में तय किया गया कि कक्षा छह से 12 तक के सभी बच्चों को निश्शुल्क पुस्तक-ड्रेस दी जाएगी। विद्यालयों को वाद्ययंत्र भी दिया जाएगा। एक-दो माह में ही इसे क्रियान्वित कर लिया जाएगा। इसके अलावा विश्वनाथ मंदिर में पहली बार संस्कृत की अंतर विद्यालयी समेत विभिन्न स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया जाएगा। इस दौरान न्यास सदस्य संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बिहारीलाल शर्मा के आग्रह पर संविवि को भवन मरम्मत और रखरखाव के लिए एक करोड़ रुपये तक का बजट न्यास परिषद की ओर से देने की सहमति दी गई। प्रतिदिन बाबा का भोग-प्रसाद शहर के स्टेशन, बस अड्डे और घाटों पर रहने वालों को वितरित किया जाएगा। मंदिर अन्नक्षेत्र में भोग-प्रसाद तैयार करा कर पैक कराया जाएगा और मंदिर के वाहन से दोपहर में बांटा जाएगा। तिरुपति बालाजी और महाकाल मंदिर की तर्ज पर श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में भी प्रसाद की अलग रेसिपी तैयार करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

ईडी ने मनरेगा फर्जीवाड़ा में बंगाल सरकार के कई अफसरों को किया तलब

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 100 दिन रोजगार देने की योजना को लागू करने में अनियमितताओं को लेकर ईडी ने गुरुवार को पूछताछ के लिए राज्य सरकार के कई अधिकारियों को नोटिस जारी किया। तलब किए गए अफसरों में दो संचयन पान व सुभ्रांशु मंडल पश्चिम बंगाल सिविल सेवा (डब्ल्यूबीसीएस) के अधिकारी हैं।

ईडी को पता चला है कि 25 लाख फर्जी जाब कार्ड बनाकर करोड़ों रुपये का हेरफेर किया गया है। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई है। इसी कड़ी में संचयन को 12 फरवरी तथा सुभ्रांशु मंडल को 15 फरवरी को ईडी के साल्टलेक दफ्तर में बुलाया गया है। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने शुरुआती जांच के बाद दो प्रकार की अनियमितताओं की पहचान की है। पहली योजना के तहत फर्जी रोजगार कार्ड को लेकर है। दूसरी, फर्जी जाति प्रमाण-पत्र को लेकर है, जिसका उपयोग फर्जी रोजगार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में किया गया था।

उत्तराखंड में आनलाइन परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, देहरादून

- सेक्शन आफिसर व असिस्टेंट सेक्शन आफिसर की परीक्षा में अभ्यर्थियों को कराई जा रही थी नकल
- सर्वर रूम से रिमोट एक्सेस लेकर परीक्षा के सिस्टम को हैक कर पेपर साल्व करा रहा था गिरोह

उत्तराखंड में काउंसिल आफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआइआर) की ओर से आयोजित सेक्शन आफिसर व असिस्टेंट सेक्शन आफिसर की आनलाइन भर्ती परीक्षा में नकल कराने का मामला सामने आया है। नकल माफिया गिरोह के सदस्यों ने सर्वर रूम से रिमोट एक्सेस लेकर सिस्टम को हैक कर लिया। इसके बाद अभ्यर्थियों को पेपर साल्व कराया। देहरादून के सहस्त्रधारा रोड और डोईवाला के दो परीक्षा केंद्रों पर पुलिस ने छापा मारा और कुछ अभ्यर्थियों के साथ केंद्र संचालकों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में गिरोह द्वारा दिल्ली व अन्य प्रांतों में भी आयोजित हो रही इस परीक्षा में नकल कराने की जानकारी मिली है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी सीएसआइआर द्वारा आयोजित परीक्षा में नकल माफिया और परीक्षा केंद्र संचालक मिलीभगत कर नकल करा रहे हैं। इस पर पुलिस की दो टीमों ने सहस्त्रधारा रोड स्थित आइटी पार्क क्षेत्र में पशुपति लैब और डोईवाला के प्रेम नगर में दून घाटी इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल एजुकेशन सेंटर पर दबिश दी। पुलिस टीम को परीक्षा केंद्रों पर मुख्य लैब के सर्वर रूम से अलग कमरे में चोरी से जोड़ी गई लीज लाइनें मिलीं। यह लीज लाइन नकल माफिया ने केंद्र संचालकों से मिलीभगत कर परीक्षा से पूर्व ही अभ्यर्थियों को नकल कराने के लिए जोड़ी थी।

लीज लाइनों के माध्यम से आनलाइन परीक्षा का एक्सेस प्राप्त किया जाता था व परीक्षा के प्रश्नों को साल्व कर उनके उत्तर अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए जाते थे।

पूछताछ के लिए हिरासत में कई संदिग्ध : एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने दोनों सेंटरों से कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। प्राथमिक पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि गिरोह की ओर से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को दून के परीक्षा केंद्र भरवाए हैं। सहस्त्रधारा रोड स्थित आइटी पार्क में बनाए परीक्षा केंद्र में अंकित व डोईवाला स्थित परीक्षा केंद्र में मोहित व दीपक कुमार अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर उन्हें प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करा रहे थे।

महिला अभ्यर्थी ने की नकल कराने की पुष्टि : पुलिस को दिए बयानों में एक महिला अभ्यर्थी ने बताया कि उसका परीक्षा सेंटर सहस्त्रधारा रोड स्थित आइटी पार्क की पशुपति लैब था। महिला ने नकल कराने की पुष्टि की है। बताया कि सेंटर की ओर से उसे उत्तर उपलब्ध कराए गए हैं।

पूर्वोत्तर बहुमूल्य प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर : मुर्मु

- पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विविधता को मिलेगा मंच :राष्ट्रपति
- विविधता का अमृत महोत्सव का प्रथम संस्करण 11 फरवरी तक चलेगा

नई दिल्ली, प्रेट्र: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को कहा, पूर्वोत्तर बहुमूल्य प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है। यहां के लोग भी अत्यंत प्रतिभाशाली हैं जो नृत्य, संगीत, परिधान, हस्तनिर्मित कलाकृतियों व स्वादिष्ट व्यंजनों की कलाओं से परिपूर्ण हैं।

राष्ट्रपति भवन में 'विविधता का अमृत महोत्सव' का उद्घाटन करते हुए मुर्मु ने उक्त बात कही। उन्होंने कहा, पूर्वोत्तर में भारतीय संस्कृति के कई सुंदर व विविध रूपों को देखा जा सकता है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि 'विविधता का अमृत महोत्सव' का प्रथम संस्करण पूर्वोत्तर के समारोहों के साथ शुरू हो रहा है। इसमें असम, अरुणाचल, नगालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम के कार्यक्रम चलेंगे। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी बयान में मुर्मु के हवाले से बताया गया है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता ही उसकी ताकत है। यह हमारी साफ्टपावर है। समारोह में इस विविधता को दर्शाना व समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अनुभवों को साझा करना और उसमें निहित एकता को परिलक्षित करना अपने आप में मिसाल है। यह समारोह जनता के लिए आठ से 11 फरवरी तक चलेगा। इसका समय सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक का होगा। इस कार्यक्रम के लिए राष्ट्रपति भवन में प्रवेश गेट नंबर 35 से मिलेगा। इसकी आनलाइन बुकिंग visit.rashtrapatibhavan.gov.in. से होगी।

नई दिल्ली में गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में 'विविधता का अमृत महोत्सव' का उद्घाटन करने के बाद हस्तनिर्मित कलाकृतियां देखतीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु। एएनआइ

बंगाल में फरार तृकां नेता की गिरफ्तारी के लिए सड़क पर उतरीं महिलाएं

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में सैकड़ों महिलाएं गुरुवार सुबह सड़कों पर उतर आईं और फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग की। शेख इस साल पांच जनवरी को ईडी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों पर हमले का मास्टरमाइंड भी है। इस हमले में ईडी के तीन अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। ईडी की टीम तृणमूल नेता के घर छापामारी करने गई थी।

संदेशखाली की महिलाएं शेख और उसके सहयोगियों द्वारा अपमान व यातना का शिकार थीं। इस संबंध में शेख के कुछ सहयोगियों के नाम उन्होंने बताए, जिनमें अमीर गाजी, सिबप्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार शामिल हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने दावा किया कि जब ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमला हुआ तो ये सभी सबसे आगे थे। महिलाओं ने शिकायत की कि क्षेत्र में जमीन हड़पने के अलावा, सत्तारूढ़ दल के भगोड़े नेता के सहयोगियों ने सूर्यास्त के बाद महिलाओं के लिए अपने घरों से बाहर निकलना लगभग असंभव बना दिया है।

सोपोर में बड़े षड्यंत्र के लिए आतंकियों ने घर में छिपा रखी थी आईईडी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- सुरक्षाबलों ने आतंकी ठिकाने से हथियार बरामद कर मकान मालिक को किया गिरफ्तार
- दो कमरों के बीच बने ठिकाने को लश्कर-ए-इस्लाम का कमांडर करता था इस्तेमाल

उत्तरी कश्मीर में बारामुला जिले के सोपोर में आतंकियों ने बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए एक मकान के भीतर ठिकाना बना रखा था, जहां आइईडी, एक पिस्तौल और अन्य सामान छिपा रखा था। सुरक्षाबलों ने गुरुवार को इन हथियारों को बरामद कर मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया। यह आतंकी ठिकाना लश्कर-ए-इस्लाम के मारे जा चुके कमांडर कयूम नजार का था।

पुलिस ने सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर सोपोर के क्रैंकशिवन में एक आतंकी ठिकाना होने की सूचना पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान एक मकान मालिक घबराया हुआ नजर आया। एक कमरे में बनी अलमारी कुछ असामान्य सी दिखी। सुरक्षाबलों ने अलमारी को हटाया तो उन्हें वहां छोटा दरवाजा दिखा जो दो कमरों की दीवारों के बीच बने छोटे से कमरे का था। इसी कमरे में हथियार बरामद हुए हैं। सुरक्षाबलों ने उसी समय मकान मालिक रशीद नजार को गिरफ्तार कर लिया।

अधिकारी ने बताया कि रशीद नजार लश्कर-ए-इस्लाम के आतंकी कयूम नजार का भाई है। रशीद के मकान में बना ठिकाना कयूम द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। कयूम नजार पहले कभी लश्कर-ए-तैयबा का कुख्यात आतंकी था जो वर्ष 2015 में लश्कर-ए-इस्लाम का चीफ कमांडर बना था।

कयूम और उसके साथियों ने वर्ष 2015 में कश्मीर में मोबाइल फोन टावर ध्वस्त करने के अलावा विभिन्न मोबाइल कंपनियों के कर्मचारियों को भी निशाना बनाया था। सुरक्षाबलों का दबाव बढ़ने पर वह पाकिस्तान भाग गया था। सितंबर, 2017 में पाकिस्तान से लौटते हुए उत्तरी कश्मीर के लच्छीपोरा, उड़ी में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था।

जागरण विशेष यशस्वी प्रधान

महिला प्रधान के नेतृत्व व कुशल प्रबंधन से प्रेरणास्रोत बनी ग्राम पंचायत

सरिता देवी ने बदली देहरादून की बड़कोट पंचायत की छवि, कामकाज समझने आ चुके हैं कई राज्यों के पंचायत प्रतिनिधि

महेंद्र चौहान • देहरादून

जज्बा हो तो अल्प शिक्षा भी आड़े नहीं आती। उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित बड़कोट ग्राम पंचायत की प्रधान सरिता देवी इसका प्रमाण हैं। सिर्फ 10वीं कक्षा पास सरिता की नेतृत्व क्षमता और कुशल प्रबंधन से यह ग्राम पंचायत स्वच्छ ग्रामीण परिवेश का तमगा पाने के साथ आदर्श पंचायत के रूप में भी ख्याति अर्जित कर रही है। उनके इस प्रयास को पंचायती राज विभाग वर्ष 2022-23 में राज्य स्तर और वर्ष 2023-24 में जिला स्तर पर पुरस्कृत कर चुका है। ग्रामोत्थान में इस योगदान के लिए केंद्र सरकार ने भी इसी वर्ष गणतंत्र दिवस पर सरिता को नई दिल्ली आमंत्रित किया। उनकी पंचायत के कामकाज को समझने के लिए जम्मू-कश्मीर समेत अन्य राज्यों के दर्जनों पंचायत प्रतिनिधि के भ्रमण पर आ चुके हैं।

देहरादून की बड़कोट ग्राम पंचायत की आबादी करीब 9,000 है। 33 वर्षीय सरिता देवी वर्ष 2019 में प्रधान बनीं। तब पंचायत घर खस्ताहाल था। गांव में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। पेयजल की भी किल्लत रहती थी। न ही सड़कें दुरुस्त थीं। प्रधान बनने पर सरिता ने सबसे पहले स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाए। इसके लिए घर-घर कूड़ा उठान के साथ सूखे और गीले कूड़े को पृथक करने की व्यवस्था की गई। ग्रामीणों को भी जागरूक किया। गीले कूड़े से पंचायत में जैविक खाद बनती है, जबकि सूखे कूड़े को निस्तारण के लिए ऋषिकेश भेजा जाता है। पंचायत में सामुदायिक शौचालय भी है। वर्मी कंपोस्ट के 50 केंद्र और बायोगैस के 22 लाभार्थी भी हैं।

हाईटेक पंचायत घर और सीसीटीवी कैमरों से लैस: सुरक्षा के लिए प्रमुख स्थानों पर 13 सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। यहां माडल आंगनबाड़ी केंद्र के साथ हाईटेक पंचायत घर भी है। जहां गार्डन के साथ सीएसएसी सेंटर की सुविधा है। पंचायत घर में दो किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया गया है, जिससे बिजली के साथ धन भी बच रहा है।

निजी खर्च से किया पंचायत को जगमग: चकाचक सड़कों के साथ रात में रोशनी की भी व्यवस्था है। सीमित बजट होने के चलते प्रधान ने खुद लगभग 10 लाख रुपये खर्च करके 500 एलईडी लाइट लगवाईं। पंचायत निधि से भी 180 एलईडी लाइट लगाई गई हैं।

पंचायत घर के बाहर का दृश्य। इनसेट में ग्राम पंचायत बड़कोट में सुरक्षा के मद्देनजर लगे सीसीटीवी कैमरे • जागरण

सामुदायिक शौचालय की स्वच्छता में अहम भूमिका

आमदनी का भी ख्याल

प्रधान सरिता को पंचायत की आमदनी का भी ख्याल है। उन्होंने पंचायत घर के समीप पांच दुकानें बनवाईं, जिनसे प्रतिवर्ष डेढ़ लाख रुपये की आय होती है। पंचायत में भवन निर्माण शुल्क भी लागू है। इसके अलावा पंचायत घर और पंचायत की भूमि को विवाह आदि कार्यक्रमों के लिए किराये पर देने से भी आमदनी हो रही है।

> पंचायत को हर स्तर पर उत्कृष्ट बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसमें ग्रामीणों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि पंचायत को स्वच्छता के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
>
> **सरिता देवी,** ग्राम प्रधान, बड़कोट

> बड़कोट ग्राम पंचायत में स्वच्छता के साथ अन्य क्षेत्र में भी बेहतर कार्य हुआ है। यह पंचायत सड़क, बिजली, पानी व अन्य सुविधाओं से सुसज्जित है। अन्य पंचायतों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए।
>
> **उर्मिला बिष्ट,** खंड विकास अधिकारी, डोईवाला

विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

****

गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के आठ गुर्गे गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जालंधर : पंजाब में जालंधर जिले में करमा फैशन शोरूम के मालिक को कारतूस के साथ धमकी भरा पत्र भेजकर रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने गुरुवार को जेल में बंद गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई व कनाडा में बैठे अपराधी गोल्डी बराड़ के गिरोह के आठ गुर्गों संजय बावा, दीपक, गजिंदर राजपुर उर्फ गज्जू, राधे, अभिषेक गिल, पप्पू, मनोज व दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के पास से तीन देसी पिस्तौल, 10 कारतूस व चार मैग्जीन मिली हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त संदीप शर्मा ने बताया कि पकड़े गए अपराधी इंग्लैंड में बैठे गोल्डी के करीबी सूरज के कहने पर जालंधर में रंगदारी वसूलने वाले थे। इस मामले में सूरज को भी नामजद किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लुक आउट सर्कुलर जारी किया जाएगा।

For More Newspapers And Magazines Join Paid Group Whatsapp To 8969469464

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 9 फरवरी, 2024

दैनिक जागरण

आसान कार्य भी आरंभ में कठिन प्रतीत होता है

श्वेत और स्याह पत्र

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संप्रग शासन के समय के आर्थिक कुप्रबंधन को प्रकट करने वाले श्वेत पत्र में यह जो कहा गया कि तत्कालीन सरकार के तौर-तरीकों से कमजोर अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी, उससे असहमत होना कठिन है। यह स्पष्ट ही है कि कांग्रेस को यह श्वेत पत्र रास नहीं आया और इसीलिए उसने मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर आनन-फानन अपना स्याह पत्र पेश किया और यह गिनाया कि कैसे यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। कांग्रेस यह सब करके इस तथ्य को नहीं नकार सकती कि मनमोहन सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में किस तरह नीतिगत पंगुता का शिकार बन गई थी। यह नीतिगत पंगुता इस हद तक थी कि खुद तत्कालीन आर्थिक सलाहकार ने यह कहा था कि अब इस पंगुता को चुनाव बाद ही दूर किया जा सकता है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि संप्रग शासन के समय किस प्रकार घपले-घोटालों की झड़ी लग गई थी। इनमें बैंक घोटाले भी शामिल थे। मोदी सरकार के समय जो तमाम बैंक घोटाले सामने आए और जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा, उनकी नींव मनमोहन सरकार के समय ही पड़ी थी। इन घपलों-घोटालों को लेकर मनमोहन सिंह ने कहा था कि गठबंधन सरकार की कुछ मजबूरियां होती हैं। यह संप्रग शासन के आर्थिक कुप्रबंधन के साथ भ्रष्टाचार पर लगाम न लग पाने का ही दुष्परिणाम रहा कि 2014 के आम चुनावों में कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट गई थी। यदि सब कुछ सही था तो फिर कांग्रेस की इतनी दुर्गति क्यों हुई?

श्वेत पत्र के जवाब में कांग्रेस की ओर से लाए गए स्याह पत्र की मानें तो मोदी सरकार के दस वर्षों का कार्यकाल अन्याय का काल रहा है। कांग्रेस ने इस स्याह पत्र के जरिये आर्थिक के साथ राजनीतिक और सामाजिक मोर्चे पर भी मोदी सरकार की कथित असफलताओं की सूची पेश की है। निःसंदेह ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार की कमियों और कमजोरियों का उल्लेख नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बाद भी इसे तो अनदेखा नहीं ही कर सकते कि आज देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। जब प्रमुख देशों की अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती का शिकार हैं, तब विश्व बैंक से लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तक यह मान रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के बुनियादी आधार मजबूत हैं और वह साढ़े छह-सात प्रतिशत की विकास दर हासिल करती रहेगी। यदि कांग्रेस को मोदी सरकार के आंकड़ों पर यकीन नहीं तो क्या उसे वैश्विक संस्थाओं के आंकड़ों और आकलन पर भी भरोसा नहीं? क्या वह इसे नकार सकती है कि मोदी सरकार राजकोषीय घाटे पर लगाम लगाने के साथ विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में सफल रही है? इसी तरह क्या वह इस बात को ओझल कर सकती है कि बीते दस वर्षों में आधारभूत ढांचे का द्रुत गति से विकास हुआ है? यह तो सबको दिख रहा है।

सड़कों पर आतंक

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम स्थित सृष्टि अपार्टमेंट में साइकिलिंग कर रहे सात वर्षीय बच्चे पर आवारा कुत्ते के हमले की घटना सिहराने वाली है। साथ ही नगर निगम प्रशासन के लिए इस बात की चेतावनी भी कि इन पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो नगरीय जनजीवन को और भी विषम स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। सड़कों पर झुंड बनाकर घूमते आवारा कुत्ते महानगरों की बड़ी समस्या बन चुके हैं और हर जगह लोगों को उनके अचानक हमलों का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद में तो कुत्ते के काटने की वजह से ही एक बच्चे ने पिता की गोद में दम तोड़ दिया था। बरेली, बदायूं, बागपत सहित कई जनपदों में भी खूंखार कुत्तों के हमले में बच्चों की मौत हुई। महानगरों की आवासीय कालोनियां भी सुरक्षित नहीं हैं। सड़क के कुत्ते कालोनियों में घुसकर लोगों पर हमला बोल देते हैं। लखनऊ के जिस अपार्टमेंट की चर्चा हो रही है, वहां ही आधा दर्जन लोग कुत्तों के हमले का शिकार हो चुके हैं। आतंक का हाल यह है कि कई अपार्टमेंट में तो लोगों ने सुबह टहलना ही छोड़ दिया है और बच्चे खेलने के लिए बाहर नहीं निकल रहे। कभी रात में बदमाशों से जितना डर नहीं लगता था, अब उससे अधिक आवारा कुत्तों से लोगों को लग रहा है। जनजीवन को सुरक्षित रखने के लिए आवारा कुत्तों की समस्या पर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन नगर निगम असहाय नजर आता है। जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो नगर निगम कुत्तों को पकड़ने का अभियान जरूर शुरू करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही बंद कर दिया जाता है। इन पर नियंत्रण का एक ही चारा है कि उनकी नसबंदी की जाए, लेकिन यह कार्य भी सिर्फ आंकड़ेबाजी तक ही सीमित है। सरकार ने कई निकायों में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाए जरूर हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं। वस्तुतः सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसके समाधान की योजना बनानी चाहिए।

रंग लाएगा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान

सुरेंद्र किशोर

चूंकि जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी अभियान पर विराम लगते नहीं देखना चाहती, इसलिए यदि मोदी सरकार और बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आए तो हैरानी नहीं

अवधेश राजपूत

आजादी के कुछ समय बाद चर्चित जीप घोटाले के साथ ही कांग्रेस सरकार ने देश में भ्रष्टाचार का जो पौधा रोपा था, उसकी जड़ें समय के साथ और गहरी होती गईं। जीप घोटाला साबित हो जाने के बावजूद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी हस्ती का नाम सामने आ रहा था। विपक्षी दलों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज की तो तत्कालीन गृहमंत्री ने संसद में विपक्ष को चुनौती दी कि अगले चुनाव में इसे मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ लीजिएगा और इस केस को अब बंद कर दिया गया है। कांग्रेस के इसी रवैये के चलते देश में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। सार्वजनिक धन की लूटपाट चलती रही और लोग गरीब बने रहे। आज स्थिति यह है कि चार मौजूदा मुख्यमंत्रियों, दो उपमुख्यमंत्रियों और 14 पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में विभिन्न अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं या जांच एजेंसियां उनके खिलाफ सक्रिय हैं। इस मामले में अन्य तमाम नेताओं के खिलाफ मामलों का अंबार लगा हुआ है। इससे पहले एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नेताओं के खिलाफ मामले कभी नहीं चले थे। आज हम कैसे लोकतंत्र में जी रहे हैं?

यह स्थिति रातोंरात निर्मित नहीं हुई। भ्रष्टाचार की गंभीरता को समझते हुए 1963 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डी. संजीवैया को यह कहना पड़ा था कि '1947 में जो कांग्रेसी भिखारी थे, वे आज करोड़पति बन बैठे। झोपड़ियों का स्थान शाही महलों ने और कैदखानों का स्थान कारखानों ने ले लिया है।' फिर 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो यहां तक स्वीकार कर लिया कि केंद्र सरकार दिल्ली से जो एक रुपया यानी सौ पैसे भेजती है, उनमें से लोगों तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे मनमोहन सिंह ने 1998 में यह दुखड़ा रोया था कि इस देश की पूरी व्यवस्था सड़ चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि गठबंधन वाली सरकार चलाते रहने के लिए कुछ समझौते करने पड़ते हैं। उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन वह मौन धारण किए रहे। हालांकि नरेन्द्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद यह रवैया बदला, जिन्होंने पहले ही एलान कर दिया था कि 'न खाऊंगा और न खाने दूंगा।' हाल में उन्होंने संसद में कहा, 'जिन्होंने देश को लूटा है, उन्हें लौटाना पड़ेगा।'

भ्रष्ट नेताओं पर मजबूत हो रहे शिकंजे से तिलमिलाए कांग्रेस तथा अन्य दल यह आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार बदले की भावना से हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अगर ऐसा है भी तो फिर इन नेताओं को अदालतों से क्यों नहीं राहत मिल रही? चूंकि जनता भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई को देखकर खुश है, इसलिए उसने मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाकर भेजा और उनके तीसरे कार्यकाल को लेकर भी कोई संदेह नहीं दिख रहा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी है कि हमें ऐसा प्रशासनिक तंत्र विकसित करना है, जिसमें भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी ने जांच एजेंसियों को भी खुली छूट दी हुई है कि भ्रष्टाचारी किसी भी कीमत पर न बचने पाएं। भ्रष्टाचार असल में कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। यह देश को तबाह कर रहा है। मोदी ने यह भी कहा कि 'जब काम की बात करो तो लोग कहते हैं कि इसमें मेरा क्या? जब उनका हित नहीं सधता तो कहते हैं कि मुझे क्या? इस मेरा क्या और मुझे क्या ने देश को बर्बाद कर दिया है।' वह 2014 से ही ऐसी बातें कहते आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के प्रति मोदी के कड़े रवैये के परिणाम भी सामने हैं। उनकी दस साल की सरकार के दौरान भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आया। शायद देश ने पहली बार ऐसा दौर देखा है। भ्रष्टाचार के समूल नाश की उम्मीद बढ़ी है। मोदी सरकार में कर चोरी और सरकारी खजाने से रिसाव भी रुका है। कर राजस्व तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। जनकल्याण से जुड़ी कई अभूतपूर्व योजनाएं लागू की गई हैं। सैन्य बलों का सशक्तीकरण किया जा रहा है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान केंद्रित हुआ है। ये उत्साहजनक संकेत हैं।

इससे पहले देश ने वह दौर भी देखा, जब कांग्रेस सरकारों ने भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े मामलों को रफा-दफा करने के हरसंभव प्रयास किए। बोफोर्स और हवाला कांड तो मिसाल ही बन गए। उन मामलों को इतना कमजोर कर दिया गया कि फरवरी 2004 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बोफोर्स मामला बंद कर दिया। सीबीआइ ने उसके खिलाफ अपील तक नहीं की, जबकि उसका ठोस आधार बनता था। तब केंद्र में कांग्रेस सरकार ही थी। पिछली सदी के अंतिम दशक में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जेएस वर्मा को यह कहना पड़ा कि सीबीआइ ने हवाला कांड की जांच तक नहीं की। यदि न्यायपालिका के शीर्ष पर सरकार को लेकर ऐसे विचार प्रकट किए गए हों तो स्थिति का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

भ्रष्टाचार के आरोपितों ने मोदी के सत्ता में आने से पहले 'बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय' वाली सरकारें ही देखी थीं। 2014 में सत्ता में आने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से कहा था कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। लोगों ने 2019 के चुनाव में उन्हें और बड़ा बहुमत दे दिया। ऐसा लग रहा है कि देश की आम जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रहे मोदी सरकार के इस अभियान पर विराम लगते नहीं देखना चाहती। इसलिए यदि मोदी पिछली बार से और बड़े बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आएं तो इस पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। यह बात प्रधानमंत्री मोदी के आत्मविश्वास में भी झलक रही है, जिन्होंने संसद से ही शंखनाद किया कि इस बार भाजपा अकेले 370 से अधिक सीटें लाने जा रही है। मोदी का दावा बेमानी भी नहीं लगता, क्योंकि देश के सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के बारे में तो उसके सहयोगी दलों को ही संदेह लग रहा है कि क्या वह 40 सीटें भी जीत पाएगी। विपक्षी खेमे में खलबली और भाजपाई खेमे में सहजता का भाव आम चुनाव की इबारत को स्पष्ट तौर पर दर्शा रहा है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

जिंदगी बदलता जल जीवन मिशन

गजेंद्र सिंह शेखावत

जल जीवन मिशन स्वास्थ्य जोखिमों को घटाने के साथ ही लोगों के जीवन स्तर में सुधार भी ला रहा है

अतीत की बात बनती पानी की कमी। फाइल

भारत आज जल क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश और व्यापक लक्ष्यों के साथ कार्य करने वाला दुनिया का शीर्ष देश है। इस लिहाज से सबसे अहम है जल जीवन मिशन (जेजेएम) की सफलता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा भी है कि जल जीवन मिशन का विजन लोगों तक पानी पहुंचाने का तो है ही, साथ ही यह विकेंद्रीकरण का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। यह ग्राम-संचालित और नारी शक्ति-संचालित है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। जेजेएम आज भारत की विकास नीति और दृष्टि की सफलता की जमीनी गवाही दे रहा है। 14 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों तक पहुंच रहा शुद्ध जल यह बताता है कि हम सिर्फ सरपट विकास की ओर नहीं भाग रहे, बल्कि आम लोगों के जीवन में बुनियादी बदलाव के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इससे उत्तराखंड के क्यारकुली भट्टा गांव से पलायन रुक गया है। झारखंड के आदिवासी गांव कुसुमडीह में मानव-पशु संघर्ष में कमी आई है तो महाराष्ट्र के चांदपुर गांव की गलियों में शहनाई की आवाजें फिर से गूंजने लगी हैं। इन तीन गांवों में ही नहीं, बल्कि ऐसे हजारों गांवों में जल जीवन मिशन से आया परिवर्तन आज साफ दिखता है। यह मिशन न केवल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी वरदान साबित हो रहा है, बल्कि महिला सशक्तीकरण और ग्रामीणों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव भी ला रहा है।

जल जीवन मिशन ने 73.98 प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली है। यह बड़ी बात है कि 14 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों को नल से जल का कनेक्शन दिया जा चुका है। अगस्त 2019 में ऐसे घरों की संख्या महज 3.23 करोड़ थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2019 में लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की थी। इस मिशन के तहत ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार की दिशा और दशा निर्धारित की गई, जो आजादी के 75 साल बाद भी नल से जल सरीखी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित थी। देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन शुद्ध जल आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लक्ष्य के साथ जल जीवन मिशन की यात्रा शुरू हुई थी। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि देश के किसी भी नागरिक को जल आपूर्ति से वंचित न रहना पड़े। भारत की विशालता और भौगोलिक विविधता के लिहाज से यह एक बड़ी चुनौती थी। सरकार ने समुदायों, भागीदारों और गैर सरकारी संगठनों को एक साथ लाकर अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना तैयार की। एक ही व्यवस्था सभी क्षेत्रों में लागू नहीं की जा सकती थी। उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में पानी जमने की समस्या थी तो रेगिस्तानी और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों की कमी थी। कहीं ग्रामीण बस्तियां दूर-दूर थीं तो कुछ जगहों पर प्रदूषण की बड़ी समस्या थी। इसलिए 'कोई भी पीछे न छूटे' की थीम के साथ जल जीवन मिशन ने सभी तरह की चुनौतियों से निपटते हुए अपनी राह बनाई। पहाड़ी और ठंडे क्षेत्रों में इंसुलेटेड पाइप का उपयोग किया गया। जिन बस्तियों में पानी की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतें थीं, वहां के लिए मल्टी-विलेज योजना बनाई गई। साथ ही पीने और खाना पकाने के लिए सामुदायिक जल शोधन संयंत्र जैसे अल्पकालिक उपाय भी किए गए। ये उपाय उपयोगी सिद्ध हुए।

जल जीवन मिशन का प्रभाव केवल जल उपलब्धता तक सीमित नहीं है। इसमें ग्रामीण समुदायों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता भी शामिल है। यह जहां स्वास्थ्य जोखिमों को कम कर रहा है, वहीं लोगों के जीवन स्तर में सुधार भी ला रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता डा. माइकल क्रेमर ने कहा है कि सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने से नवजात मृत्यु दर में 30 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि हर घर जल की आपूर्ति सुनिश्चित होने से डायरिया से होने वाली चार लाख मौतों को कम किया जा सकता है। जेजेएम से 8.37 लाख करोड़ रुपये तक की आर्थिक बचत का आकलन भी किया गया है। जेजेएम से हर दिन पानी की व्यवस्था करने में लगने वाले समय में छह करोड़ घंटे से भी अधिक की बचत संभव है। इससे महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि आम तौर पर महिलाएं ही पानी की व्यवस्था करती हैं।

जेजेएम के तहत ग्रामीण इलाकों में 'नल जल मित्र' पहल भी शुरू की गई है, ताकि ग्रामीण आबादी को पंप संचालन और जल प्रबंधन से संबंधित कार्यों में कुशल बनाया जाए। इसके तहत अब तक 5.14 लाख से अधिक ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां/पानी समितियां गठित हो चुकी हैं। 5.12 लाख विलेज एक्शन प्लान तैयार कर लिए गए हैं। फील्ड टेस्टिंग किट का उपयोग कर पानी के नमूनों की जांच करने के लिए 23.68 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। अपने शुरुआती चरण में इससे औसतन 59.93 लाख लोगों को प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष और 2.22 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला। कार्यान्वयन और रख-रखाव चरण के दौरान इस मिशन से अतिरिक्त 11.18 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर प्रतिवर्ष रोजगार मिला। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलने से समाज आत्मनिर्भर हुआ और ग्रामीण विकास को नए पंख लगे। देश में पानी की स्वच्छता जांचने के लिए आज 2,118 लैब काम कर रही हैं। मामूली दरों पर पानी के नमूनों की जांच की जा रही है, ताकि हर परिवार को स्वच्छ जल मुहैया कराया जा सके। सरकार का लक्ष्य एक ऐसे भारत का निर्माण है, जहां सभी के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध हो, पानी की कमी अतीत की बात हो जाए और किसी ग्रामीण परिवार को जीवन के इस अमृत के लिए मशक्कत न करनी पड़े।

(लेखक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

खुद को बदलें

चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में आंकना और सामर्थ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जीवन जीना ही उन्नति एवं सार्थकता का मार्ग है। विश्व में ऐसा कोई कार्य नहीं है, जिसे मनुष्य न कर सके। बस मन-मस्तिष्क में कार्य के प्रति लगन होनी चाहिए। यही वह चुनौतीपूर्ण क्षण है, जो आपको जीवन में कुछ अनूठा एवं सार्थक करने का परिवेश देता है। आप ब्रह्मांड में इच्छा का बीज बोएंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपको आपकी वह वस्तु दिलाने के लिए जुट जाएगा। आप आसमान को देखकर यह कह सकते हैं, 'यह कितना नीरस है' या यह कह सकते हैं-'यह कितना बड़ा है।' यह बस मस्तिष्क को अनुकूलित करने की बात है। जैसा कि रूमी ने कहा, 'अपने आपको परिपक्व बनाएं और परिवर्तन के बुरे नतीजों के बारे में आशंकित न हों। उजाला बनें।' यानी संकट के समय खुद रोशनी बनें और दूसरों को भी प्रकाशित करें।

महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें वह परिवर्तन खुद में करना चाहिए जिसे हम संसार में देखना चाहते हैं। जरूरत है हम दर्पण जैसा जीवन जीना सीखें। उन सभी खिड़कियों को बंद कर दें जिनसे आने वाली गंदी हवा मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती। जीवन की समझ होना बेहद जरूरी है। उसके साथ चरित्र और माध्यम की समझ भी उतनी ही जरूरी है।

कुछ महान करने के चक्कर में हम कुछ नहीं कर पाते। हम दूसरों के किए हुए में कमियां निकालने में लगे रहते हैं और दूसरे सब बातों से बेपरवाह एक के बाद एक सफलता अपने नाम करते जाते हैं। हम पूर्णता की चाह में अटके रहते हैं और दूसरे आधे-अधूरे काम करते हुए बढ़ते जाते हैं। ओशो कहते हैं, 'जीवन महान चीजों से नहीं, छोटी-छोटी चीजों से बनता है। इसलिए अपूर्णता की निंदा न करें। खुद को बदलें।'

ललित गर्ग

बाजार के हवाले वैवाहिक आयोजन

डा. महेश परिमल

अब शादियां मैरिज प्लान के अंतर्गत होने लगी हैं। वैवाहिक आयोजन पूरी तरह से एक बिजनेस का हिस्सा हो गए हैं

फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का अधिकतर हिस्सा शादी पर केंद्रित है। इस फिल्म में शादी की सारी रस्में घर पर मनाते दिखाई गई हैं। सचमुच पहले शादियां घरों में ही होती थीं। जो कई दिनों का आयोजन होता था। अब शादी के पवित्र बंधन की बात कहीं दब गई है। अब यह पूरी तरह से एक बिजनेस का हिस्सा हो गया है। इन दिनों मध्यम वर्ग परिवार में भी शादी का खर्च अब लाखों में आने लगा है। यह वर्ग भी अपनी संतानों की शादी में किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। भले ही कर्ज लेना पड़े। ऐसी बात नहीं है कि सस्ती शादियां हो ही नहीं रही हैं। सामूहिक विवाह में शादियां सस्ते में होने तो लगी हैं, पर उसमें शामिल लोगों में वह उत्साह दिखाई नहीं देता। यही हाल मंदिरों एवं सेवाभावी संस्थाओं द्वारा आयोजित विवाह समारोहों का है।

वास्तव में अब शादियां मैरिज प्लान के अंतर्गत होने लगी हैं। लोग विभिन्न तरह के प्रबंधन से बचने लगे हैं। इसलिए बाजार में प्रबंधन कंपनियां सामने आने लगी हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल आदेश करें, काम हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक यही है कि आपकी जेब कहां तक इसकी इजाजत देती है। जब तक आपकी जेब में पैसा है, तब तक आपके सारे काम तुरंत होते जाएंगे। पहले शादी के एक दिन मंगल गीतों का कार्यक्रम हुआ करता था, जिसमें परिवार के लोग ही शामिल होते थे। अब ऐसा नहीं होता, इसके लिए भी मैरिज प्लान करने वाली एजेंसियां तैयार हैं। वे ही इस मंगल गीतों के कार्यक्रम के लिए पेशेवर संगीतकारों एवं उसमें डांस करने वालों का चयन करते हैं। यह कार्यक्रम भी पूरी तरह से प्रोफेशनल हो गया है। विभिन्न तरह के लोगों के शामिल होने से उनकी पसंद के भोजन की अलग से व्यवस्था होने लगी है। एक से एक व्यंजनों के माध्यम से लोगों को लुभाने की कोशिशें भी होने लगी हैं।

आलीशान शादी के बजट में मेनू सर्विस और कैटरिंग सर्विस पर 30 प्रतिशत, गिफ्ट पर 19 प्रतिशत, डेकोरेशन पर 14 प्रतिशत, इवेंट प्लानिंग पर 12 प्रतिशत, हनीमून पर आठ प्रतिशत, फोटोग्राफी पर तीन प्रतिशत खर्च होता है। देश में हर साल शादी के लिए खरीदे जाने वाले जेवरात पर 60 हजार करोड़ रुपये खर्च होते हैं। चार हजार करोड़ रुपये के होटल रूम बुक किए जाते हैं। 10 हजार करोड़ रुपये कपड़ों पर खर्च होते हैं। इसमें प्री-वेडिंग का खर्च शामिल नहीं किया गया है। यह भी एक खर्चीला कार्यक्रम है, जिसमें वर-वधू शादी के पहले विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर विभिन्न मुद्राओं में अपनी तस्वीर खींचवाते हैं। जाहिर है लोग बेतहाशा खर्च करने में पीछे नहीं रहना चाहते। ऐसे में आम आदमी की दशा क्या होती होगी? इसे आसानी से समझा जा सकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

विकृत मानसिकता से इतिहास लेखन

'विकृत इतिहास लेखन के दुष्परिणाम' शीर्षक से लिखे आलेख में हरेंद्र प्रताप ने कड़वी सच्चाइयों को उजागर किया है। इतिहास का अर्थ है जो हुआ उसका वर्णन, किंतु भारत के संदर्भ में कुछ प्रतिभाओं ने अपनी विचारधारा के वशीभूत भारत का विकृत इतिहास प्रस्तुत किया और उन्हें इतिहास लेखन के पुरोधाओं में शामिल किया गया। न जाने कितने लोगों ने ऐसे विकृत इतिहास को पुष्ट करते हुए पीएचडी तक की डिग्रियां हासिल कीं और कितनी ही पीढ़ियों को गलत इतिहास पढ़ाया। खैर, जो हुआ उसे तो पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। अब हर भारतीय को अपने प्रजातंत्र की राष्ट्रीय पुस्तक संविधान को आत्मसात करते हुए अपने हर कार्य का निर्वहन करना चाहिए। ठीक ही कहा है कि ईश्वर मनुष्य को सत्ता और शक्ति स्वयं के उत्थान और समाज के कल्याण के लिए प्रदान करते हैं। जो लोग ऐसा कर पाते हैं वे ही इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं, न कि स्वार्थी लोग। इतिहास गवाह है कि जिस भी समाज ने अपने सही इतिहासबोध का सहारा लेकर कार्य किए वे दुनिया को राह दिखा पाए। गलती यदि हो जाती है तो उसे स्वीकार कर, उससे सबक लेकर आगे बढ़ा जाता है। हमारी युवाशक्ति के पास आज ज्ञान के अनेक द्वार खुले हैं। वे घिसी-पिटी परिपाटी को न अपनाकर सही जानकारी के आधार पर आगे बढ़ें और देशहित को सर्वोपरि मानें। समस्या चाहे कितनी भी विकट हो, किंतु मनःस्थिति यदि विकृत न हो तो आपसी संवाद से हर समस्या का समाधान पाया जा सकता है। सही इतिहासबोध इस कार्य में बहुत सहायक होता है। आज जो मंदिर-मस्जिद के झगड़े हैं इनसे पार पाने के लिए जरूरी है कि इतिहास की सही तस्वीर को सामने रख सभी पक्ष संवाद को तरजीह दें। आपसी निपटारे से समस्याओं के समाधान सामाजिक सौमनस्य के लिए न्यायालयों के निपटारे से अधिक कारगर सिद्ध हुए हैं, इतिहास इसका साक्षी है।

yograj62@gmail.com

दोषियों के खिलाफ हो कार्रवाई

मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हादसा हुआ बहुत ही दिल दहलाने वाला है। देश में पटाखा फैक्ट्री में ऐसा हादसा होना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। अब फिर सरकार, प्रशासन और अन्य भ्रष्ट अधिकारियों की लापरवाही कुछ लोगों की जान पर भारी पड़ गई। जिस देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, जहां सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार के दलदल में हो, वहां भविष्य में भी ऐसे हादसों पर शायद ही लगाम लगे, क्योंकि यहां पैसे के लिए अवैध और असुरक्षित निर्माण भी खूब होते हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद फिर से सरकार, प्रशासन और अन्य कुंभकर्णी नींद से जगे हैं और इसकी जांच के आदेश के और कुछ मुआवजे का मरहम लगाकर अगले किसी ऐसे दिल दहलाने वाले हादसे के इंतजार में लंबी तान के सो जाएंगे, लेकिन ऐसे हादसे क्यों होते हैं? इनके लिए कौन-सी लापरवाहियां जिम्मेदार हैं? आखिर क्यों नहीं ऐसे हादसों से सबक लेते हुए अपने यहां आग, भूकंप या अन्य हादसों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम करते हैं?

raju09023693142@gmail.com

आगे आए न्यायपालिका

यह सच है कि मुगल शासकों ने अपनी झूठी शान के लिए देश के मंदिरों को ध्वस्त किया। औरंगजेब से लेकर अंग्रेजों तक और अंग्रेजों से लेकर मौजूदा समय में भी धर्म और जाति के बीच विभाजन की लकीर खींच कर सत्ता हासिल करना चाहते हैं कुछ लोग। इतिहास गवाह है कि मुगल शासकों ने बहुत से मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाईं। प्राचीन समय में लेखनी राजाओं के दबाव में आकर ही चलती होगी। इसी का नतीजा है कि मुगलों का महिमामंडन किया गया। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण और ज्ञानवापी के लिए वैसा ही फैसला लेना चाहिए, जैसा भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या के लिए लिया। देश का सर्वोच्च न्यायालय इस पर जो भी फैसला लेगा, उसका सभी लोगों को स्वीकारना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

मेलबाक्स

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

2.33 लाख लोगों के सुझाव आए थे उत्तराखंड में सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता के संबंध में विधेयक तैयार किए जाने से पूर्व मांगे गए सुझावों के क्रम में, सभी वर्गों की ओर से।

ज्ञानेंद्र रावत
वरिष्ठ पत्रकार

समान नागरिक संहिता

देश नवनिर्माण की आसान बनेगी राह

उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित कर दिया है। निश्चित रूप से यह संहिता दूसरे राज्यों के लिए भी पथ प्रदर्शक का काम करेगी। साथ ही इससे देश से रूढ़िवादी मानसिकता के खात्मे और नए भारत के निर्माण की राह आसान हो सकती है। इससे महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया को भी मजबूती मिलेगी। ऐसे अद्भुत प्रयास के लिए उत्तराखंड का योगदान इसलिए भी प्रशंसनीय है, क्योंकि लंबे समय से चर्चा में रहे इस मामले पर उसने पहल की है

एक विधिवत समिति का गठन करते हुए उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार किया है। प्रतीकात्मक

उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक न केवल विधानसभा में पारित कर नया इतिहास रचा है। नया इतिहास इसलिए कि कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उल्लेखनीय है कि गोवा में पुर्तगाली शासन के दौर से ही यूसीसी लागू है। वहां पुर्तगालियों के शासन के समय सिविल कोड लागू था, वह भी व्यक्तिगत नागरिक मामलों के लिए। गोवा के पुर्तगालियों के चंगुल से आजाद होने के समय एक आदेश द्वारा पुराने जारी कानून को यथावत रखने का प्रविधान किया गया। यही वजह है कि गोवा में अभी भी समान नागरिक संहिता चल रही है।

उल्लेखनीय है कि बीते शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा इस विधेयक के प्रारूप को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया था। इस विधेयक की विशेषता यह रही कि इसमें बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं को आपराधिक कृत्य बनाने तथा लिव-इन में रह रहे जोड़ों के बच्चों को भी सभी अधिकार दिए जाने का प्रविधान है, जिनमें कुछ मुद्दों पर विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा धार्मिक आजादी के हनन की संज्ञा दी गई, जबकि इस विधेयक जिसे सत्तापक्ष ने सभी वर्गों को साथ लेने वाला विधेयक बताया है, जिसमें सभी वर्गों की लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष रखने, शादी के छह माह के भीतर अनिवार्य तौर पर पंजीकरण करवाने, जिस आधार पर पति तलाक ले सकता है, उसी आधार पर पत्नी द्वारा भी तलाक की मांग किए जाने, पति या पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी यानी बहुविवाह पर सख्ती से पाबंदी, लड़के व लड़कियों को समान अधिकार, लिव-इन में रहने के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता और विवाहित पुरुष या महिला के लिव-इन में रहने पर पाबंदी, सभी धर्मों के व्यक्तियों के लिए अपनी संपदा की वसीयत करने व बच्चों को उस दंपत्ति का जैविक बच्चे का अधिकार दिया गया है।

कई देशों में है प्रविधान : विश्व में बहुतेरे ऐसे देश हैं, जहां समान नागरिक संहिता है। यही नहीं, बहुतेरे देशों में बिना किसी जाति-धर्म में भेदभाव किए समान कानून लागू हैं। यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि वर्ष 2022 में सऊदी अरब में महिला अधिकारों, तलाक, विवाह की न्यूनतम उम्र को लेकर अपनी संहिता बनाई गई। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया, बांग्लादेश आदि देशों में इस तरह के प्रविधान हैं, लेकिन वहां इन कानूनों को लेकर किसी भी तरह की विसंगति नहीं है। तात्पर्य यह कि वहां किसी को भी किसी प्रकार की खास शिकायत नहीं है। ऐसे में विचारणीय यह है कि फिर हमारे यहां ही इसका इतना विरोध क्यों? इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि कुछ कट्टरपंथी और निहित स्वार्थी मानसिकता वाले लोग और राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते वोटों की राजनीति के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। उन लोगों के अनुसार हमारा देश विविध संस्कृतियों, भाषाओं, प्राकृतिक वैविध्य और विभिन्न धर्मों के अनुयायियों का देश है। उन लोगों के अनुसार यहां विविधता में ही एकता के दर्शन होते हैं, क्योंकि विविधता ही इसकी पहचान है। समान नागरिक संहिता से सब कुछ एकरस हो जाएगा और देश अपनी विविधता तथा मूल प्रकृति खो देगा। इसे किसी भी किस्म पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह देश के विरोधी दलों की एकमुश्त राय है। फिर देश का मुस्लिम तबका भी यह मानता है कि यह उनके मजहबी विचारों के विरुद्ध है, लिहाजा यह उन पर सुनियोजित हमला है।

यहां इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आजादी के बाद से कई ऐसे मौके आए हैं, खासकर 1973 के बाद से जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुतेरे मामलों पर ऐसी टिप्पणी की है कि समान नागरिक संहिता इस देश के लिए आवश्यक है। इसे जितनी जल्दी हो लाया जाना चाहिए। पर्सनल सिविल ला को ही लें, उसमें महिलाओं और पुरुषों में असमानता जगजाहिर है। पर्सनल सिविल ला में महिला अधिकारों का हनन कोई छिपी हुई बात नहीं है। जब सभी को समान अधिकार की बात की जाती है, उस दशा में महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों? पर्सनल सिविल ला तो महिलाओं के साथ भेदभाव की जीती जागती मिसाल है। इसे कायम रखकर समान अधिकार की बात बेमानी है। इसे धार्मिक बाना पहनाकर महिलाओं के साथ भेदभाव की इजाजत नहीं दी जा सकती।

उल्लेखनीय है कि हमारे यहां व्यक्तिगत मामलों को छोड़कर सभी कानून संविधान सम्मत हैं। हमारे यहां आजादी मिलते समय संविधान में उस समय व्यक्तिगत मामलों को इस आशय से छोड़ा गया था कि अभी-अभी देश का बंटवारा हुआ है। इसलिए उस समय यह माना गया कि समान नागरिक संहिता लाने का उचित समय नहीं है। इसको उचित समय पर चर्चा करके लाया जाए। यही वह वजह रही कि उस समय इस मसले को नीति निर्देशक तत्वों में रख दिया गया और केंद्र एवं राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया कि वह उचित समय आने पर इस मुद्दे पर कानून बनाएं।

इसमें दो राय नहीं कि यह जो समान नागरिक संहिता विधेयक तैयार किया गया, उसके लिए एक विधिवत कमेटी गठित की गई, उसने पूरे उत्तराखंड में लगभग 20 माह में 72 से ज्यादा बैठकें कर और 40 से ज्यादा जनसंवाद कर रायशुमारी की, लोगों से आनलाइन सुझाव मांगे, सभी वर्गों-धर्मों-पंथों के लोगों के 2.33 लाख के लगभग सुझाव आए और उसके बाद आम सहमति के उपरांत इस विधेयक को राज्य विधानसभा में पेश किया। यह भी सच है कि उत्तराखंड में पारित इस विधेयक में सभी वर्गों, धर्मों के लिए समृद्धि व समानता दी गई है। यह किसी भी जाति, पंथ, धर्म के निजी कानूनों के ऊपर है। अब एक राष्ट्र, एक निशान और एक विधान समय की मांग है। जनसंख्या वृद्धि देश की ज्वलंत समस्या है। यह संहिता देश के दूसरे प्रदेशों के लिए पथ प्रदर्शक का काम कर सकती है। जनमानस में जनसंख्या वृद्धि समेत अन्य समस्याओं को लेकर भी जागरूकता लाने के दायित्व का भी बखूबी निर्वहन करेगी। अन्य राज्यों के लिए भी इसमें बहुत कुछ सीख है।

उत्तराखंड ने रचा स्वर्णिम इतिहास

प्रमोद भार्गव

उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक राज्य विधानसभा में पारित करके देश में समानता का कानून बनाने के संदर्भ में इतिहास रचने का काम किया है। राज्यपाल से अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। गुजरात और असम में भी इसी प्रकार का कानून लाने की तैयारी की जा रही है। वस्तुतः एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की समिति ने इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। चूंकि देसाई न्यायालयीन प्रक्रिया से अवगत रही हैं, इसलिए उन्हें ज्ञात रहा है कि कानून में असमानताओं के चलते लोगों को किस तरह से परेशान होना पड़ता है। अतएव अब उत्तराखंड में उन कानूनों को समाप्त कर दिया है, जो स्त्री-पुरुष में भेद के साथ संतान और संपत्ति में भी भेद के पर्याय रहे है। साफ है, व्यक्तिगत नागरिक अधिकार संबंधी मामलों से जुड़े ज्यादातर कानूनों में एकरूपता लाने का स्वागतयोग्य प्रयास किए गए हैं। अब प्रत्येक वर्ग-धर्म-पंथ के दंपति को विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण नहीं होने पर सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। कोई भी पति, पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित है। वैवाहिक दंपति में यदि कोई एक व्यक्ति बिना किसी दूसरे पक्ष की सहमति के मत परिवर्तन करता है तो दूसरे पक्ष को उससे तलाक लेने व गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार रहेगा। पति-पत्नी के संबंध विच्छेद या घरेलू झगड़े के समय पांच वर्ष तक का बच्चा माता के पास रहेगा।

इस विधेयक में लिव-इन के रिश्तों में रहने वाले युगलों को पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में गैर-पंजीकृत युगलों पर सोशल पुलिसिंग का खतरा बढ़ सकता है? वर्तमान में आजीविका के लिए युवक एवं युवतियों को अकेले रहना पड़ रहा है, जो जीवन में कठिनाई बढ़ाता है। परिणामस्वरूप संपर्क में आने के बाद कई जोड़े साथ रहने को मजबूर हो जाते हैं। यह एक व्यावहारिक मानसिकता है। हालांकि यह ठोस सच्चाई है कि लिन-इन रिश्तों के प्रचलन से महिलाओं पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं। साथ ही विवाह संस्था की सात जन्मों वाले गठबंधन और पवित्रता के मूल्य एक हद तक घटे भी हैं। ऐसे में पंजीकरण की बाध्यता करने से ऐसे युगल राहत में रहेंगे, जिन्हें परिजनों की साथ रहने की स्वीकृति नहीं मिलती है। लिहाजा पंजीकरण के चलते युगल को संतान होती है तो उसे लालन-पालन के साथ विरासत संबंधी कानूनी अधिकार भी मिल जाएंगे। अतएव अविवाहित मातृत्व से पैदा होने वाली संतान का भविष्य माता-पिता का नाम मिल जाने के कारण संरक्षित होगा।

संविधान राज्य को स्वतंत्र रूप से समान नागरिक कानून बनाने का अधिकार देता है। अतएव संविधान में दर्ज नीति-निर्देशक सिद्धांत यही अपेक्षा रखता है कि समान नागरिकता समूचे देश में लागू हों। इससे देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक ही तरह का कानून वजूद में आ जाए, जो सभी धर्मों, संप्रदायों और जातियों पर लागू हो। ऐसे में इन विरोधाभासी कानूनों के तहत न्यायपालिका को सबसे ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ता है। अदालत में जब पारिवारिक विवाद आते हैं तो अदालत को देखना पड़ता है कि पक्षकारों का धर्म कौनसा है? फिर उनके धार्मिक कानून के आधार पर विवाद का निराकरण करती है। इससे व्यक्ति का मानवीय पहलू भी प्रभावित होता है। (प्रमोद भार्गव)

खरी-खरी

असली मलाई तो यहां है...

अलंकार रस्तोगी

एक बार एक बिल्ली किसी जमानत जब्त हो चुके नेता की तरह उदास बैठी थी। उस देवदास ब्रांड बिल्ली को देखकर उससे हमेशा से भयभीत रहने वाला चूहा भी मौज लेने के मूड में आ चुका था। वह बिल्ली से पर्याप्त और सुरक्षित 'फिजिकल डिस्टेंसिंग' बनाते हुए बोला, 'क्या हुआ बिल्ली मौसी? क्या कोरोना की वैक्सीन लगवा कर आई हो जो बुखार आ गया है?'

वह निरीह चूहा जो कभी बिल्ली की खुशबू तक से दूर भागता था, आज उस पर धड़ल्ले से कमेंट कर रहा था। लेकिन उसे यह अच्छा लगा कि चलो किसी ने उसकी सुध तो ली। इसलिए वह अपनी भड़ास निकालते हुए बोली, 'बुखार तो नहीं आया है, लेकिन जब से मुझे यह पता चला है कि दूध को 'डिटर्जेंट' और 'यूरिया' मिलाकर बनाया जा रहा है, मलाई के नाम पर जहर बेचा जा रहा है, तब से मुझे अपनी सेहत की बहुत चिंता हो रही है।'

चूहे की पूरी बिरादरी पर ग्रहण बनकर 'टेंशन' देने वाली बिल्ली को पहली बार स्वयं टेंशन में देखकर उस चूहे को असीम आनंद की अनुभूति हुई। लेकिन उसे विपक्ष को मिटाने में नहीं, बल्कि स्वस्थ 'चूहातंत्र' में बिल्ली रूपी सशक्त विपक्ष में यकीन था, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए 'टाम एंड जेरी' वाला आनंद बना रहे। इसके लिए बिल्ली की उचित चिंता पर अपनी समान चिंता जाहिर करते हुए बोला, 'तुम्हारी बात सही है। अपनी जान हथेली पर रखकर तुम अपनी नींद खराब कर किसी तरह जुगाड़ से दूध की सत्ता पर कब्जा जमा पाती हो। और बदले में क्या मिलता है, वही जानलेवा यूरिया वाला दूध और उसकी कातिल मलाई।'

चूहे ने अब उस बिल्ली की व्याकुलता देखते हुए समाधान बताया, 'ऐसा करो बिल्ली आंटी, तुम अब दूध की चोरी किसी आम आदमी के यहां करना छोड़कर केवल भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट ठेकदार, भ्रष्ट डाक्टर, भ्रष्ट अधिकारी या सरल भाषा में बोला जाए तो हर भ्रष्ट विशेषण युक्त लोगों के घर ही किया करो, क्योंकि ऐसा मैंने कई लोगों से सुना है कि असली मलाई अब इन्हीं लोगों के घर आती है।'

पोस्ट

बीते कुछ दिनों से जयन्त चौधरी के राजग में शामिल होने की खबर चल रही है। पार्टी या चौधरी साहब की तरफ से किसी ने अभी तक कोई खंडन नहीं किया है। इतनी लंबी चुप्पी तो नीतीश कुमार के रास्ते की तरफ अग्रसर दिखती है।

आदेश रावल@AadeshRawal

उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने महाराष्ट्र के बहुमत को धता बता दिया था। अब दोनों ही अपनी पार्टी और चुनाव चिह्न से हाथ धो बैठे हैं। कर्मों का फल यहीं भुगतना पड़ता है।

समीत ठक्कर@thakkar_sameet

विपक्षी दल राजनीतिक फायदे के लिए उत्तर-दक्षिण विभाजन का खेल खेल रहे हैं। यह हास्यास्पद है कि सबसे कर्जदार राज्य केरल की सरकार अपनी वित्तीय अनुशासनहीनता छिपाने के लिए जंतर-मंतर पर धरना दे रही है।

मिलिंद देवड़ा@milinddeora

मैं अगले टेस्ट में केएल राहुल और मोहम्मद सिराज की वापसी की उम्मीद कर रहा हूं। साथ ही इसकी भी कि राजकोट में अच्छी पिच मिलेगी। मुझे लगता है कि टीम प्रबंधन के समक्ष यही दुविधा होगी कि क्या दूसरा तेज गेंदबाज खिलाया जाए या वाशिंगटन सुंदर के रूप में ऐसा स्पिन गेंदबाज, जो बल्लेबाजी करने में भी सक्षम है।

हर्षा भोगले@bhogleharsha

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने बलबूते 370 सीटें हासिल कर सकती है?

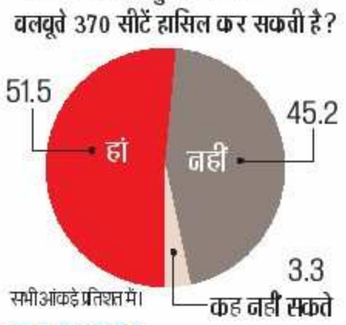

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या एससी-एसटी आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

योगी बाबा कह दिये हमें चाहिए तीन,
वरना देखोगे मिया बान्नबे का सीन!
बान्नबे का सीन अयोध्या ढांचे वाला,
क्यों धधकाना चाह रहे हो वो ही ज्वाला।
मथुरा-काशी छोड़ प्रेम से दे दो ताबा,
उंगली तीन दिखाय कह दिये योगी बाबा!!

– ओमप्रकाश तिवारी

झारखंड डायरी

प्रदीप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, झारखंड

लीक पर चलेंगे या नई लकीर खींचेंगे 'टाइगर'

झारखंड में हाल ही में अप्रत्याशित तरीके से हुए राजनीतिक बदलाव ने पूरे देश का ध्यान खींचा। हेमंत सोरेन के विरुद्ध जब ईडी का शिकंजा कस रहा था तो यह लगभग तय था कि वे अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन की ताजपोशी करेंगे। त्यागपत्र देने के एक दिन पहले विधायकों के साथ बैठक के दौरान कल्पना सोरेन की मौजूदगी से इसे बल मिला। इससे पहले सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के एक विधायक डा. सरफराज अहमद द्वारा सीट रिक्त करना भी इसी तैयारी का हिस्सा था। कवायद इस स्तर पर की गई थी कि रिक्त हुई सीट से कल्पना सोरेन चुनाव लड़कर विधानसभा में जाने की कोशिश करेंगी, लेकिन इसमें जोखिम भी था। निर्वाचन आयोग की अनुमति इसके लिए आवश्यक थी।

वहीं दूसरी ओर कल्पना सोरेन को आगे करने को लेकर सोरेन परिवार में भी सहमति नहीं थी। ऐसे में विधायकों ने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें विधायक दल के नेता की जगह खाली रखी गई थी। अगले दिन ईडी जब हेमंत सोरेन के आवास पर पूछताछ के लिए पहुंची तो घटनाक्रम तेजी से घूमा। परिणाम यह हुआ कि चम्पाई सोरेन का नाम सामने आया, जिन्हें सोरेन परिवार का विश्वस्त माना जाता है। चम्पाई ने राजनीति का ककहरा झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन से सीखा है। वे राज्य के सबसे बड़े क्षेत्रीय दल के प्रमुख रणनीतिकारों में भी हैं। उनकी ताजपोशी से झामुमो पर एक पारिवारिक पार्टी का लगाया जाने वाला आरोप भी कमजोर हुआ है। चम्पाई सोरेन ने तमाम अटकलों को पीछे छोड़ते हुए विश्वास मत भी हासिल कर लिया है। जल्द ही वे मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर लेंगे। उनके कामकाज पर पिछली सरकार की छाया स्वाभाविक है। विपक्ष का आरोप है कि वे रबर स्टांप की तरह इस्तेमाल होंगे। इससे इतर चम्पाई सोरेन सरकार के शुरुआती फैसले यह संदेश दे रहे हैं कि उनका लक्ष्य आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के साथ-साथ उन योजनाओं को आगे बढ़ाना है, जिन पर हेमंत सोरेन सरकार का फोकस रहा है। वे यह स्वीकार करने से भी पीछे नहीं हटते कि उनकी सरकार हेमंत पार्ट-दो है। इससे विपक्षी दलों को निशाना साधने का मौका मिल रहा है।

विधानसभा में अपनी बात रखते हुए चम्पाई सोरेन। फाइल

वैसे चम्पाई के संक्षिप्त कार्यकाल की उनकी गतिविधियों से समझा जा सकता है कि वे किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। राजभवन में शपथ लेने के साथ ही उन्होंने दुमका के लिए उड़ान भरा। उप राजधानी दुमका संताल आदिवासी बहुल है और यह झामुमो का पारंपरिक गढ़ है। यहां हर वर्ष दो फरवरी को समर्थकों का बड़ा जुटान पार्टी स्थापना दिवस समारोह के मौके पर होता है। हेमंत की अनुपस्थिति में पार्टी समर्थकों में जोश-जज्बा बनाए रखने की यह शुरूआत थी। उसी दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में पाकुड़ के रास्ते प्रवेश कर रही थी। चम्पाई राहुल से मिलने यात्रा में पहुंच गए। उन्होंने यह संदेश दिया कि कांग्रेस के साथ झामुमो की दोस्ती जारी रहेगी। विभिन्न क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस को जहां लगातार झटका लग रहा था, वहीं झामुमो के इस कदम से राहुल गांधी को भी तसल्ली हुई होगी। चम्पाई सोरेन ने यह स्पष्ट कर दिया कि झामुमो आने वाले चुनावों में कांग्रेस के साथ तालमेल कर ही आगे बढ़ेगा। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को तलब किया और विधि-व्यवस्था समेत राजस्व प्राप्ति के मोर्चे पर डटने के निर्देश दिए। गांवों में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए चलाए गए आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार के तीसरे चरण के क्रियान्वयन का निर्देश दिया।

वस्तुतः चम्पाई सोरेन का फोकस उन्हीं आधार क्षेत्रों पर है, जिसके इर्द-गिर्द योजनाएं तैयार करने में हेमंत सोरेन लगे रहे। उनके जिम्मे सरकार के साथ-साथ संगठन का भी दारोमदार होगा, क्योंकि बदली राजनीतिक परिस्थिति में उन पर दबाव अधिक होगा। हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन दुमका से विधायक हैं। वे झामुमो की युवा शाखा का नेतृत्व करते हैं। उनकी भाभी सीता सोरेन भी विधायक हैं। कल्पना सोरेन का नाम जब सामने आया तो उन्होंने आपत्ति जताई थी। जब चम्पाई सोरेन का नाम सामने आया तो उनके तेवर नरम हुए, लेकिन सोरेन परिवार का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाव और अपेक्षा उनके सम्मुख रहेगा। लीक पर चलते हुए वे उन योजनाओं पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपनी अलग लकीर खींचने का अवसर भी उनके पास है। वे जिस पृष्ठभूमि से यहां तक आए हैं, वह उपहार में नहीं मिलता। चम्पाई सोरेन ने लंबा समय मजदूरों और विस्थापितों के आंदोलन के नेतृत्व में गुजारा है। एकबारगी उन्हें देखकर ही उनकी सरलता का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन उनकी फायरब्रांड छवि की वजह से ही वे अपने समर्थकों में 'झारखंड टाइगर' कहे जाते हैं। देखना यह होगा कि 'टाइगर' बनी-बनाई लीक पर चलते हैं या नई लकीर खींचने में कामयाब होते हैं।

मंथन

तुलसी साहित्य में विज्ञान तत्व

तुलसीदास की कृतियों में वैज्ञानिक तत्वों का भी विवरण है। उनके साहित्य का अध्ययन इस दृष्टिकोण से भी किया जाना चाहिए कि वैज्ञानिक सिद्धांतों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है

डा. परमेश्वर झा
पूर्व डीन, बी. एन. मंडल विवि, बिहार

धर्म एवं विज्ञान में कोई मौलिक विरोध नहीं है। दोनों का उद्देश्य एक ही है- सत्य का साक्षात्कार करना, अंतर केवल उन दोनों की प्रक्रियाओं में है। मानव कल्याण के लिए दोनों आवश्यक हैं, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। मानवता की शरीर यात्रा के लिए धर्म नेत्रों का तथा विज्ञान चरणों का कार्य करता है। भारतीय संस्कृति का प्राण है दोनों का समन्वय। प्राचीन उपलब्ध ग्रंथों में आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ वैज्ञानिक तत्व भी बीज रूप में पाए जाते हैं।

गोस्वामी तुलसीदास इन तथ्यों से परिचित थे और इसलिए उनकी रचनाओं में विभिन्न वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश है। वे महान भक्त कवि थे। श्रीरामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, बरवै रामायण, रामाज्ञा प्रश्न आदि छोटी-बड़ी 37 पुस्तकों की उन्होंने रचना की। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना 'श्रीरामचरितमानस' है जो विश्व साहित्य की शाश्वत निधि है तथा भारतीय संस्कृति का जीवंत स्मारक। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध सिद्धांतों से वे व्यापक रूप से परिचित थे। उन्होंने इसमें धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक आदि तथ्यों के साथ-साथ वैज्ञानिक तत्वों का भी अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में विवरण प्रस्तुत किया है। आज जब समूचा ब्रह्मांड श्रीराम के जन्मस्थान पर उनके पुनर्स्थापित होने पर भावविभोर है, हमें तुलसी की रचनाओं में वर्णित वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में भी जानना चाहिए।

वस्तुतः आधुनिक विज्ञान की उपलब्धियों में हवाई जहाज का निर्माण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 'पुष्पक विमान' प्राचीन भारत की देन है जिसकी चर्चा विभिन्न प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में उपलब्ध है। तुलसीदास ने भी इसकी चर्चा श्रीरामचरितमानस में की है। यहां उसके उत्तरकांड के दोहा चार में तत्संबंधी उल्लेख है : आवत देखि लोग सब, कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरउ, उतरेउ भूमि विमान। आज के विज्ञानी युग में राकेट का निर्माण और उसका प्रयोग किसी भी राष्ट्र के लिए प्रतिष्ठा एवं गौरव का द्योतक है। अस्त्र-शस्त्र को निर्दिष्ट स्थान पर गिराकर या अन्य अभीष्ट को पूरा करके राकेट पुनः पृथ्वी पर लौट आता है। श्रीराम के अमोघ बाण में भी ऐसी विशेषता थी कि निर्दिष्ट कार्य को पूरा करके उनके तरकश में लौट आता था। इतना ही नहीं, आगे जाकर वह बाण कई बाणों में परिवर्तित हो जाता और पुनः उसी रूप में वापस आ जाता। पहले इस तरह का वर्णन कपोल कल्पित समझा जाता था, परंतु राकेट के आविष्कार ने इस तरह के वर्णन को सत्य साबित कर दिया है कि प्राचीन भारत में बहुत पूर्व ही इसका आविष्कार हो गया था।

स्थापत्य कला : श्रीरामचरितमानस में वर्णित अयोध्या के राजप्रासाद, जनकपुर की गगनचुंबी अट्टालिकाएं, लंका के सुसज्जित-सुगठित सोने का किला आदि से प्राचीन भारत में प्रचलित उन्नत स्थापत्य कला का दिग्दर्शन होता है। नल-नील जैसे कुशल इंजीनियरों की देख-रेख में महासमुद्र पर अतिशीघ्र महापुल का निर्माण किया गया जिस पर चढ़कर सेना सहित श्रीराम ने समुद्र को पार किया तथा लंका पर चढ़ाई की : बांधि सेतुअति सुदृढ़ बलावा, देखि कृपानिधि के मन भावा। चली सेन सहित कछु बरनि न जाई, गर्जहि मरकट भट समुदाई।। वस्तुतः गति संबंधी न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया की विपरीत एवं बराबर प्रतिक्रिया होती है। इसी नियम के अनुकूल हनुमानजी एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर चलते हुए आगे बढ़ते जाते। जिस तेज गति एवं दबाव के साथ किसी पर्वत पर वे कूदते, ठीक उसी गति से पर्वत भी उन्हें ऊपर की ओर उछाल देता जिससे यह प्रमाणित होता है कि न्यूटन से हजारों वर्ष पूर्व भारत में इस नियम की जानकारी थी। मेघनाद के बाण से जब लक्ष्मणजी मूर्छित हो गए, तो सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी का प्रयोग कर उन्हें स्वस्थ कर दिया।

दोहावली एवं कवितावली में भी फलित ज्योतिष संबंधी अनेक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। यथा कौन सी तिथि कब हानिकारक होती है, किस नक्षत्र में कौन सा कार्य करना चाहिए, किन वस्तुओं का दर्शन शुभ और किन वस्तुओं का दर्शन अशुभ, राशियों, जन्म कुंडली, समय की विभिन्न इकाइयों का विचार आदि। इसके साथ ही इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि उन्हें अंकों, गणित की मौलिक क्रियाओं, भौतिक, रसायन और वैद्यक शास्त्र का भी विशिष्ट ज्ञान था। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनके साहित्य का अध्ययन इस दृष्टिकोण से भी किया जाए कि अध्यात्म की तरह वैज्ञानिक सिद्धांतों में भी उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है।

रामायण काल में भी कुशल इंजीनियरिंग से निर्मित अनेक निर्माण कार्यों के विवरण उपलब्ध हैं। फाइल

****

2025 से श्रीलंका को एलएनजी की आपूर्ति करेगा भारत

बेतूल : देश की सबसे बड़ी लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी 2025 से श्रीलंका को आपूर्ति शुरू कर देगी। कंपनी के सीईओ अक्षय कुमार सिंह ने बताया कि शुरुआत में जहाजों के जरिये कंटेनर से एलएनजी की आपूर्ति की जाएगी। बाद में आयात टर्मिनल बनाया जाएगा। अक्षय ने बताया कि श्रीलंका को हर रोज 850 टन एलएनजी की आपूर्ति की जाएगी। एक कंटेनर में 17 टन एलएनजी भेजी जाएगी। (प्रेट्र)

इस समय ओपन नेटवर्क फार डिजिटल कामर्स पर करीब तीन लाख मर्चेंट पंजीकृत है। आने वाले वर्षों में इनमें कई गुना वृद्धि होने की उम्मीद है।
– थंपी कोशी, सीईओ, ओएनडीसी

सेंसेक्स	71,428.43 ▼ 723.57	निफ्टी	21,717.95 ▼ 212.55	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 63,300 ▼ ₹70	चांदी प्रति किलोग्राम	₹74,600 बदलाव नहीं	डालर	₹82.96 बदलाव नहीं	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 79.07

एक नजर में

थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं भंडारण सीमा घटाई

नई दिल्ली : केंद्र ने गुरुवार को थोक विक्रेताओं, बड़े चेन रिटेलर और प्रोसेसर्स के लिए गेहूं भंडारण की सीमा घटा दी। थोक विक्रेता अब एक हजार टन के बजाए 500 टन गेहूं का भंडारण कर सकेंगे। इसी तरह, बड़े चेन रिटेलर अब प्रत्येक स्टोर में पांच टन और सभी डिपो में कुल भंडारण 500 टन कर सकेंगे। प्रोसेसर अपनी मासिक क्षमता का 60 प्रतिशत गेहूं भंडारण कर सकेंगे। (प्रेट्र)

एयरबस ए220 के दरवाजे बनाएगी भारतीय कंपनी

नई दिल्ली : विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने भारतीय कंपनी डायनामैटिक टेक्नोलाजीज को एक आर्डर देने की घोषणा की। इसके तहत डायनामैटिक टेक्नोलाजीज एयरबस के नई पीढ़ी के कम आकार वाले विमान ए220 के लिए अत्याधुनिक दरवाजे बनाएगी। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा यह किसी भारतीय एयरोस्पेस मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी के लिए सबसे बड़े निर्यात अनुबंधों में से एक है। (प्रेट्र)

निर्यातकों के प्रति संवेदनशील रहें बैंक और बीमा कंपनियां

नई दिल्ली : वित्तीय सेवाओं के सचिव विवेक जोशी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों से कहा है कि वे लाल सागर संकट के चलते समस्याओं का सामना कर रहे निर्यातकों का मामलों को संवेदनशीलता के साथ निपटाएं। उन्होंने कहा कि लाल सागर संकट से जहाज लंबा रास्ता अपना रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप व्यापार से जुड़े वित्त की मांग बढ़ रही है और बीमा लागत में वृद्धि हो रही है। (प्रेट्र)

माइक्रोसाफ्ट ने बढ़ाया महिला डेवलपर प्रशिक्षण कार्यक्रम

बेंगलुरु : माइक्रोसाफ्ट के चेयरमैन सत्या नडेला ने गुरुवार को कंपनी के 'कोड विदआउट बैरियर्स' कार्यक्रम के विस्तार की घोषणा की। इसका उद्देश्य 2024 के दौरान 75 हजार महिला डेवलपर्स को प्रशिक्षित करना है। डेवलपर्स और टेक दिग्गजों को संबोधित करते हुए नडेला ने कहा कि भारत में डेवलपर्स और विकास की गति अविश्वसनीय है। (प्रेट्र)

महंगाई में कमी लाने के उपायों का दिख रहा असर : दास

आरबीआइ ने वित्त वर्ष 2024-25 में महंगाई दर 4.5 प्रतिशत और विकास दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान जताया

- आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता एक बड़ी चुनौती
- एमपीसी के पांच सदस्य ब्याज कम करने की प्रक्रिया सोच समझकर लागू करने के पक्ष में
- पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ गति पकड़ रहा निवेश, निजी निवेश में भी आ रही है तेजी

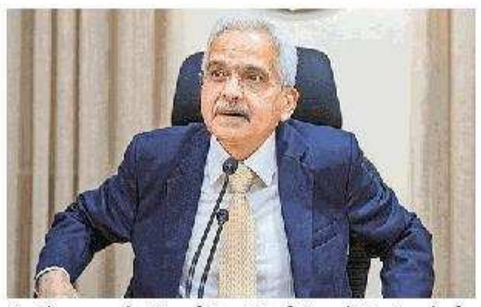

मुंबई में गुरुवार को मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ● प्रेट्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अभी तक महंगाई थामने के जो कदम उठाए गए हैं, उनका असर दिख रहा है। महंगाई कम हो रही है। 2024 में यह और कम होगी। दास ने बताया कि एमपीसी के छह में से पांच सदस्य इस बात पर सहमत है कि ब्याज दरों को कम करने की प्रक्रिया सोच समझ कर लागू होनी चाहिए, ताकि विकास की रफ्तार भी बनी रहे और महंगाई भी काबू में रहे। आरबीआइ गवर्नर ने अगले वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान खुदरा महंगाई 4.5 प्रतिशत और आर्थिक विकास दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।

आरबीआइ की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट से साफ है कि कुछ महीने पहले अर्थव्यवस्था में सुस्ती आने की जो संभावना दिख रही थी, वह अब तकरीबन खत्म हो गई है। यही वजह है कि एक वर्ष पहले केंद्रीय बैंक ने 2024-25 में आर्थिक विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने की बात कही थी, लेकिन अब उसका मानना है कि विकास दर सात प्रतिशत रहेगी। सरकार ने हाल ही में जो आंकड़े पेश किए हैं, उसके मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक विकास दर 7.3 प्रतिशत रहेगी। पहले इसके भी 6.5 प्रतिशत रहने की बात कही गई थी। अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों के बारे में आरबीआइ गवर्नर का कहना है कि वैश्विक हालात और वैश्विक वित्तीय बाजार में अनिश्चितता एक बड़ी चुनौती के तौर पर आ सकती है। वैश्विक तनाव होने से उत्पादों व सेवाओं की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है जिसका असर भारत की इकोनमी पर भी पड़ना संभव है।

दास ने कहा कि एमपीसी खाद्य पदार्थों की महंगाई पर नजर रखेगी ताकि अभी तक के प्राप्त लाभ बेकार न जाएं। आरबीआइ गवर्नर ने कहा कि ग्रामीण मांग में लगातार सुधार हो रहा है और शहरी मांग भी मजबूत बनी हुई है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ निवेश गति पकड़ रहा है। निजी निवेश में भी तेजी आ रही है। उन्होंने कहा कि चालू रबी सीजन में बोआई में सुधार हुआ है। मैन्यूफैक्चरिंग में लाभप्रदता और सेवा क्षेत्र में लचीलेपन से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिलेगा। एमपीसी की अगली बैठक 3-5 अप्रैल 2024 के दौरान होगी।

ई-रुपये में आफलाइन लेनदेन जल्द

मुंबई, प्रेट्र : आरबीआइ ने कहा है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) के पायलट प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही ई-रुपये का खुदरा आफलाइन लेनदेन शुरू किया जाएगा। इसके बाद डिजिटल रुपये यानी ई-रुपये उपयोगकर्ता ऐसे स्थानों पर भी लेनदेन कर सकेंगे, जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी सीमित है। आरबीआइ ने दिसंबर 2022 में सीबीडीसी का पायलट प्रोजेक्ट लांच किया था और दिसंबर 2023 में इसके एक दिन में 10 लाख लेनदेन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

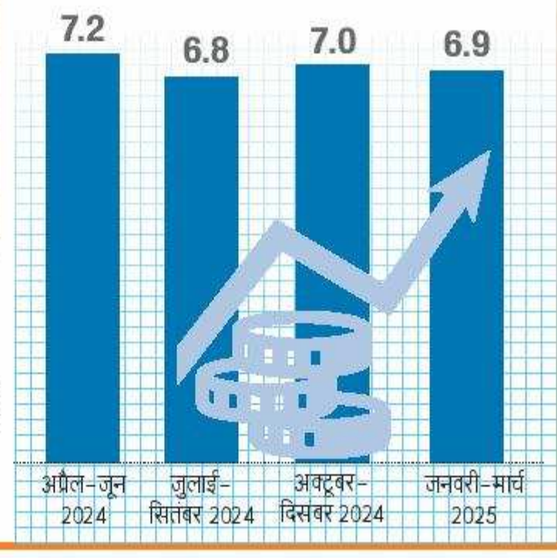

डिजिटल पेमेंट सत्यापन के लिए लाएंगे नया फ्रेमवर्क

मुंबई, आइएएनएस : आरबीआइ ने गुरुवार को बताया कि डिजिटल पेमेंट लेनदेन के सत्यापन के नया फ्रेमवर्क लाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा आधार आधारित पेमेंट प्रणाली में सुरक्षा के लिहाज से नए नियम जोड़े जाएंगे। बीते कुछ वर्षों से आरबीआइ डिजिटल पेमेंट्स में सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। खासतौर पर बार-बार प्रमाणीकरण के लिए अतिरिक्त कारक (एएफए) पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि, आरबीआइ ने एएफए की विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी है।

खुदरा और एमएसएमई कर्ज लेने वालों को प्रमुख तथ्य बताएं बैंक

मुंबई, प्रेट्र : आरबीआइ ने कर्ज देने वाले सभी संस्थानों से कहा है कि वे अब खुदरा और एमएसएमई कर्ज लेने वालों को सभी समावेशी ब्याज लागत सहित ऋण समझौते की शर्तों के बारे में मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) प्रदान करें।

अभी यह नियम वाणिज्यिक बैंकों की ओर से दिए जाने वाले व्यक्तिगत कर्ज, आरबीआइ की ओर से विनियमित संस्थाओं की ओर से दिए जाने वाले डिजिटल लोन और माइक्रोफाइनेंस लोन पर लागू हैं। आरबीआइ गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने ग्राहकों पर लगाए गए ऋण और अन्य शुल्कों के मूल्य निर्धारण में विनियमित संस्थाओं की ओर से अधिक पारदर्शिता और प्रकटीकरण को बढ़ावा देने के लिए हाल के दिनों में कई उपायों की घोषणा की है।

उन्होंने बताया कि आरबीआइ ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) बाजार में सोने की कीमत जोखिम की हेजिंग की अनुमति भी दी है। आरबीआइ ने इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म (ईटीपी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा की भी घोषणा की है।

ब्याज में कटौती की स्पष्टता न मिलने से लुढ़के शेयर बाजार

मुंबई, प्रेट्र : आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के फैसलों के बाद ब्याज दरों में कटौती के समय को लेकर स्पष्टता नहीं मिलने और बैंकिंग व आटो क्षेत्र के शेयरों में भारी बिकवाली के चलते घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुए। सकारात्मक शुरुआत करने वाला बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स अंत में 723.57 अंक की गिरावट के साथ 71,428.43 के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई का निफ्टी 212.55 अंक गिरकर 21,717.95 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स में ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, आटो, रियल्टी और कमोडिटी क्षेत्र के शेयर दबाव में दिखे। वहीं, ऊर्जा और आइटी क्षेत्र के शेयरों में बढ़त दिखी। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर का कहना है कि बाजार में शेयरों का बड़ा हिस्सा गिरावट के साथ बंद हुआ है।

सात लाख करोड़ के करीब एलआइसी का पूंजीकरण

एलआइसी का अक्टूबर-दिसंबर 2023 के दौरान शुद्ध लाभ 49 प्रतिशत बढ़कर 9,444 करोड़ रुपये रहा है। इसकी बदौलत बीएसई में कंपनी के शेयर 5.86 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,106.25 रुपये प्रति इकाई पर बंद हुए। इससे कंपनी का पूंजीकरण 38,740.62 करोड़ बढ़कर 6.99 लाख करोड़ रुपये हो गया है। अब एलआइसी पूंजीकरण के लिहाज से पांचवीं मूल्यवान कंपनी बन गई है।

पेटीएम एप पर कोई कार्रवाई नहीं : आरबीआइ

- डिप्टी गवर्नर ने कहा, अन्य बैंकों के साथ जुड़ सकता है पेमेंट प्लेटफार्म
- पेटीएम ने भी दिया भरोसा, एप के संचालन में नहीं आएगी कोई बाधा

डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ● प्रेट्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पेटीएम एप के जरिये डिजिटल लेनदेन करने वाले ग्राहकों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। आरबीआइ ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई की है न कि पेटीएम एप पर। इस कार्रवाई का पेटीएम के पेमेंट एप पर कोई असर नहीं होगा। आरबीआइ ने यह भी कहा है कि अगर कोई अन्य बैंक पेटीएम के साथ जुड़ना चाहता है तो यह उसका व्यावसायिक फैसला होगा। जो बैंक चाहे वह पेटीएम संग काम कर सकता है।

एमपीसी बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में आरबीआइ के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने बताया कि पेटीएम एप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आरबीआइ के इस रुख ने पेटीएम के लिए अन्य बैंकों के साथ भागीदारी करने का रास्ता भी खोल दिया है। आरबीआइ के इस स्पष्टीकरण के बाद पेटीएम ने अपने ग्राहकों और व्यापारिक भागीदारों को आश्वस्त किया है कि पेटीएम एप पूरी तरह से चालू रहेगा। बीते सप्ताह ही आरबीआइ की तरफ से पेटीएम पेमेंट्स बैंक और डिजिटल वालेट पर नए ग्राहक लेने पर रोक लगा दी गई थी। आइएएनएस के अनुसार, पेटीएम ने स्पष्ट किया है कि न तो उसके और न ही उसकी किसी एसोसिएट कंपनी के खिलाफ कोई नियामकीय जांच हो रही है। वहीं, पेटीएम पेमेंट बैंक की स्वतंत्र निदेशक मंजू अग्रवाल ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है।

एफएक्यू अगले सप्ताह

मुंबई, प्रेट्र : आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि समय-समय पर नियामकीय दिशानिर्देशों के बावजूद पेटीएम द्वारा लगातार गैर-अनुपालन के कारण यह कार्रवाई हुई है। साथ ही स्पष्ट किया कि कोई प्रणालीगत चिंता नहीं है। दास ने कहा कि पेटीएम के खिलाफ यह कार्रवाई ग्राहक हित में की गई है। दास ने कहा कि लोगों के सवालों के समाधान के लिए अगले सप्ताह एफएक्यू (अक्सर पूछे जाने वाले) जारी किया जाएगा।

जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 21,780 करोड़ का निवेश

- बीते दो वर्षों के दौरान इस श्रेणी में यह सबसे ज्यादा निवेश
- एसआइपी में 18,838 करोड़ रुपये का अब तक सबसे ज्यादा निवेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : म्यूचुअल फंड में लोग जमकर निवेश कर रही है। यही कारण है कि जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश लगभग दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। एसोसिएशन आफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआइ) की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, इक्विटी म्यूचुअल फंडों में पिछले महीने 21,780 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

डाटा के अनुसार, इससे पहले मार्च 2022 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 28,463 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। दिसंबर में इस श्रेणी में लगभग 17,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। वैल्यू फंड को छोड़कर, सभी श्रेणियों में इक्विटी सेगमेंट में निवेश बढ़ा है। पिछले महीने लार्ज-कैप श्रेणी में 1,287 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जो 13 महीने से अधिक समय में उच्चतम है। कुल मिलाकर, म्यूचुअल फंड में जनवरी में 1.23 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया।

इसी तरह मासिक सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआइपी) में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचते हुए 18,838 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। यह दिसंबर 2023 के 17,610 करोड़ रुपये के मुकाबले ज्यादा है। जनवरी में एसआइपी खातों की संख्या बढ़कर 7.92 करोड़ हो गई है। पिछले महीने 51.84 लाख नए एसआइपी पंजीकृत हुए हैं।

For More Newspapers And Magazines Join Paid Group 8969469464 राष्ट्रीय फलक For More Newspapers And Magazines Join Paid Group 8969469464

किसान आंदोलन की आहट भांप केंद्र सरकार ने संभाली कमान

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसान नेताओं संग की बैठक
- भाकियू सिद्धूपुर की ओर से 13 को दिल्ली कूच का किया गया है एलान
- पंजाब के सीएम मान भी बैठक में हुए शामिल

किसान आंदोलन की फिर से आहट को भांपते हुए केंद्र सरकार ने कमान संभाल ली है ताकि इस बार 2020 की तरह बात हाथ से निकल न जाए। भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर की ओर से 13 फरवरी को दिल्ली कूच की घोषणा से ठीक पांच दिन पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ बैठक की। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उपस्थित थे।

इस बार किसान संगठन एकजुट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि भाकियू उगराहां व राजेवाल जैसे संगठनों ने दिल्ली कूच से खुद को दूर रखा है। भाकियू राजेवाल ने 16 फरवरी को सहयोगी संगठनों से भारत बंद की अपील की है। दावा है कि इसमें विभिन्न बैंकों के कर्मचारी संगठन भी उन्हें समर्थन देंगे।

ज्ञात हो, तीन कृषि सुधार कानूनों को लेकर आंदोलन की शुरुआत पंजाब के किसानों ने की थी। तब केंद्र इसकी गंभीरता को समझ नहीं सकी थी। एक साल बाद केंद्र को इन तीनों कानूनों को रद करना पड़ा था। यही नहीं, किसानों को फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी जैसे कानून लाने का आश्वासन देना पड़ा। इस विषय पर केंद्रीय कमेटी बनाने और इसमें किसानों को भी शामिल करने का आश्वासन दिया गया था। केंद्र द्वारा अब तक ऐसा नहीं किए जाने के विरोध में किसानों के एक संगठन ने संघर्ष की घोषणा कर दी है। लोस चुनाव के नजदीक इस प्रकार से किसानों के जमा होने का जोखिम केंद्र सरकार नहीं उठाना चाहती, इसलिए किसानों को दिल्ली की ओर नहीं बढ़ने के लिए मनाने के लिए गोयल ने महात्मा गांधी प्रशासनिक संस्थान में किसान संगठनों संग बैठक की, जो खबर लिखे जाने तक यह बैठक खत्म नहीं हुई थी।

दिल्ली में जबरन घुसे तो गिरफ्तार होंगे किसान

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

न्यूनतम खरीद मूल्य (एमएसपी) पर गारंटी कानून, किसानों और मजदूरों को 58 वर्ष की उम्र के बाद 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों के 13 फरवरी के दिल्ली कूच के एलान ने फिर पुलिस की सिरदर्दी बढ़ा दी है। वर्ष 2021 की पिछली घटनाओं से गहरा सबक लेते हुए विभाग ने इस बार किसानों को दिल्ली की सीमा में ही नहीं घुसने देने का निर्णय किया है। पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के पुलिस प्रमुखों से बात कर दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए व्यापक रणनीति बनाई है। साथ ही तैयारी की गई है कि किसान किसी भी रास्ते से दिल्ली में घुसे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

विशेष आयुक्त कानून एवं व्यवस्था रवींद्र सिंह यादव का कहना है कि किसानों के किसी संगठन ने राज्य में प्रवेश के लिए अनुमति नहीं मांगी है। अगर मांगी तो भी उन्हें किसी सूरत में अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के पुलिस प्रमुखों से इस संबंध में विस्तृत चर्चा की है। उनसे अपील की गई है कि वे अपने-अपने राज्यों की सीमाओं में ही किसानों को रोककर हिरासत में ले लें। कानून हाथ में लेने वाले किसानों के साथ सख्ती से निपटने की कोशिश करें।

अगर पड़ोसी राज्यों की पुलिस किसानों को रोक पाने में नाकाम रहेगी तो दिल्ली पुलिस उन्हें अपनी सीमाओं पर रोक देगी। किसान दिल्ली में कहीं से भी न घुस पाएं इसके लिए व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। कंक्रीट ब्लाक, लोहे की बैरिकेड, कंटेनरों पत्थरों से लदे ट्रकों आदि से सड़कों को बंद कर दिए जाएगा। सिंघू, टीकरी, लामपुर व औचंदी आदि सभी छोटे बड़े रास्तों पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस व अर्धसैनिक बलों की तैनाती करने का निर्णय किया गया है। इन सीमाओं पर अभी से दिल्ली पुलिस व अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है।

पांच वर्षों में रेलवे ने दी तीन लाख नौकरियां

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- रेलवे संबंधी संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में दी जानकारी
- रोजगार देने की प्रक्रिया को अत्यधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित किया

राधामोहन सिंह फाइल

भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती रेल नेटवर्क प्रणाली है। सेवा के साथ-साथ यह नौकरी एवं रोजगार का माध्यम भी है। पिछले पांच वर्षों के दौरान रेलवे में दो लाख 94 हजार से ज्यादा पदों पर सीधी नियुक्तियां की गईं। रेलवे संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि नौकरियां और रोजगार देने की प्रक्रिया को पहले से अत्यधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित किया गया है।

समिति के अध्यक्ष राधामोहन सिंह ने बताया कि अमेरिका, चीन व रूस के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसमें प्रतिदिन दो करोड़ से ज्यादा लोग यात्रा करते हैं। केंद्र सरकार रेल यात्रा को सहज व सुलभ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी मकसद से यात्रियों से टिकट का सिर्फ 53 प्रतिशत ही लिया जाता है। बाकी की राशि अनुदान से पूरी की जाती है। रेलवे ने समय और सुरक्षा पर विशेष फोकस किया है। एक ही ट्रैक पर पैसेंजर एवं मालगाड़ियों के परिचालन से बेवजह ट्रेनें लेट होती हैं। इसके लिए दो डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर का निर्माण किया गया। अन्य चार कारिडोर की तैयारी है। सुरक्षा के लिए कवच को 1465 रूट किमी व 139 लोकोमोटिव पर तैनात किया गया है।

पिछले दस वर्षों के दौरान रेलवे की उपलब्धियां बताते हुए राधामोहन ने कहा कि वर्ष 2022-23 में स्विट्जरलैंड रेलवे के बराबर 5,243 किमी ट्रैक बनाए गए, जबकि नौ वर्षों में जर्मन रेलवे के बराबर 25 हजार 434 किमी ट्रैक बने।

बजट की राशि में भी 30 गुना वृद्धि हुई। 2004-05 में रेलवे का बजट 8,000 करोड़ और 2013-14 में यह 29,055 करोड़ था, किंतु वर्ष 2023-24 में दो लाख 40 हजार करोड़ हो गया। राधामोहन ने कहा कि नौ वर्षों में नई रेल लाइन बिछाने में लगभग 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रतिदिन 14 किमी ट्रैक बिछाया गया। आगे यह लक्ष्य 16 किमी प्रतिदिन करने का है। सिंगल लाइन को डबल किया गया। साथ ही रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं पर पांच गुना राशि बढ़ा दी गई है। ससमय ट्रेन संचालन के साथ-साथ सड़क यात्रा को भी सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। इसके तहत लेवल क्रासिंग (एलसी) को खत्म करने को प्राथमिकता दी जा रही है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने रेलवे की दशा सुधारने की दिशा में बड़े कदम उठाएं हैं। इस संबंध में कई बड़ी परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

कहां-कितनी बारिश, तीन माह पूर्व ही होगी सटीक जानकारी

संग्राम सिंह, वाराणसी

- पुणे व नोएडा में 900 करोड़ रुपये से स्थापित होंगे दो सुपर कंप्यूटर
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय योजना को इसी साल धरातल पर उतारेगा

पुणे स्थित भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आइआइटीएम) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डा. सूर्य चंद्र राव ने बताया कि सब ठीक रहा तो जल्द हम सटीक तौर पर यह जान पाएंगे कि आने वाले तीन महीने में कहां-कितनी बारिश होने वाली है। हवा का रुख, कोल्ड या हीट वेव की स्थिति आदि मौसम संबंधी तमाम जानकारी भी मिल सकेगी। इसका सीधा फायदा किसानों को होगा। वे उसी हिसाब से फसल का चुनाव कर सकेंगे।

डा. सूर्य चंद्र राव गुरुवार को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में जलवायु परिवर्तन और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र विषयक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्रमशः पुणे के आइआइटीएम व नोएडा के राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में छह साल पहले 'प्रत्यूष' और 'मिहिर' नामक सुपर कंप्यूटर स्थापित किए थे। अब उनके उन्नत संस्करण को लांच करने की तैयारी है। करीब 900 करोड़ रुपये की इस योजना पर सहमति बन गई है। नए सुपर कंप्यूटर की क्षमता 18 पेटाफ्लाप होगी। यह 36 वर्ग किमी परिधि के मौसम की सटीक जानकारी देने में सक्षम होगा। दोनों सुपर कंप्यूटर की सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएं। इसके लिए फ्रांस की कंपनी एटीओएस को आर्डर जारी हो गया है।

विमान में रेल मंत्री को नैपकिन पर दिया प्रस्ताव, हवाई अड्डे पर उतरते ही आया बुलावा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- कोलकाता के उद्यमी ने दिल्ली-कोलकाता की उड़ान के दौरान दिया अपशिष्ट की रेल ढुलाई का प्रस्ताव

अक्षय सतनालीवाला।

कोलकाता के उद्यमी अक्षय सतनालीवाला ने हवाई यात्रा के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पेपर नैपकिन पर लिखकर एक प्रस्ताव दिया, जिसे लेकर रेलवे प्रशासन हरकत में आ गया। बताया जाता है कि सतनालीवाला जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उसके छह-सात मिनट के अंदर ही रेलवे अधिकारियों का फोन आ गया। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि पूर्व रेलवे (ईआर) के महाप्रबंधक मिलिंद के देउस्कर ने क्षेत्रीय मुख्यालय में सतनालीवाला से मुलाकात की और उनकी कंपनी की तरफ से माल ढुलाई के बारे में दिए गए सुझावों पर चर्चा की।

दरअसल, सतनालीवाला बंगाल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कंपनी का संचालन करते हैं। वह कंपनी के निदेशक हैं। उन्होंने दो फरवरी को दिल्ली-कोलकाता की उड़ान के दौरान रेलमंत्री को पेपर नैपकिन पर अपशिष्ट की रेल ढुलाई के बारे में प्रस्ताव दिया था। उस समय उनके पास नैपकिन के अलावा कोई दूसरा कागज नहीं था। नैपकिन पर लिखा था-सर, आप अनुमति दें तो मैं यह प्रस्ताव रखना चाहूंगा कि सीमेंट संयंत्रों को एएफआर (वैकल्पिक ईंधन व कच्चे माल) की आपूर्ति श्रृंखला में रेलवे किस तरह अभिन्न अंग बन सकता है और पीएम के स्वच्छ भारत अभियान में भी योगदान दे सकता है। सतनालीवाला को उस समय आश्चर्य हुआ, जब एयरपोर्ट पर उतरते ही पूर्वी रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय से उनके पास फोन आ गया। उन्हें प्रस्ताव पर चर्चा के लिए छह फरवरी को कार्यालय बुलाया गया था।

रेलवे प्रवक्ता कौशिक मित्रा ने कहा, सतनालीवाला ने छत्तीसगढ़ के रायपुर एवं ओडिशा के राजगांगपुर और अन्य इलाकों में विभिन्न उद्योगों में ठोस कचरे के योजनाबद्ध प्रवाह के बारे में बताया। वह ठोस अपशिष्ट को विभिन्न इलाकों में मौजूद इकाइयों तक पहुंचाने के सस्ते साधन के रूप में रेलवे का प्रयोग करना चाहते हैं। इस पर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने उनके समक्ष अपशिष्ट ले जाने के लिए लचीली शर्तें पेश कीं।

****

मुंबई में बुलेट ट्रेन परियोजना पर तेजी से हो रहा है काम

मिडडे, मुंबई

- वांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स और शिलफाटा के बीच बन रही सुरंग
- पांच शाफ्ट बनाने को लेकर पर चल रहा है काम

अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। इसके तहत बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स और शिलफाटा के बीच 21 किमी लंबी सुरंग बनाई जा रही है। इस सुरंग का सात किलोमीटर हिस्सा समुद्र के अंदर बनना है।

नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड का कहना है कि पांच स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। शाफ्ट 1 बांद्रा में मुंबई हाई स्पीड रेलवे स्टेशन पर 36 मीटर की गहराई पर बन रहा है। यहां सेकेंट पाइलिंग का काम 100 प्रतिशत पूरा हो चुका है और खोदाई का काम चल रहा है। विक्रोली में शाफ्ट-2 की गहराई भी 36 मीटर है, जिसमें पाइलिंग का काम पूरा हो चुका है। इन शाफ्टों का उपयोग सुरंग बोरिंग मशीनों को विपरीत दिशाओं में नीचे करने के लिए किया जाएगा। शाफ्ट 3 सावली (घांसोली के पास) में 39 मीटर गहरे शाफ्ट-3 की खोदाई का काम जारी है। शिल्फाटा में साइट पर पोर्टल का काम शुरू हो चुका है। पांचवां अतिरिक्त मध्यवर्ती सुरंग है जिससे सुरंग तक अतिरिक्त पहुंच की सुविधा मिलेगी। सुरंग को तीन टीबीएम द्वारा खोदा जाएगा। यह ट्यूब सुरंग होगी। 37 स्थानों पर 39 उपकरण कक्ष भी बनाए जाएंगे। यह सुरंग लगभग 25 से 57 मीटर गहरी होगी। सबसे अधिक गहराई शिलफाटा के पास पारसिक पहाड़ी से 114 मीटर नीचे होगा।

19 भारतीय मछुआरों को अवैध रूप से श्रीलंका की जल सीमा में मछली पकड़ने के आरोप में वहां की नौसेना ने गिरफ्तार किया है। दो भारतीय नौकाएं भी जब्त की गई हैं। उल्लेखनीय है कि श्रीलंकाई नौसेना ने इस महीने दूसरी बार भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है।

न्यूज गैलरी

आइसलैंड में एक बार फिर ज्वालामुखी फटा

ग्रिंडाविक : दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में दिसंबर के बाद से गुरुवार को तीसरी बार एक ज्वालामुखी फटा। इससे आकाश में धुएं का गुबार छा गया। इसके चलते और द्वीप राष्ट्र के सबसे बड़े आकर्षण ब्लू लैगून स्पा को खाली कराना पड़ा। आइसलैंड के मौसस विज्ञान कार्यालय ने बताया कि विस्फोट अंतरराष्ट्रीय समयानुसार तकरीबन छह बजे माउंट सुंधनुकर के उत्तरपूर्व में तीन किमी दरार आने से हुआ। ग्रिंडाविक से तकरीबन चार किमी दूर स्थित इस तटीय शहर को गत 18 दिसंबर को हुई घटना के समय भी खाली कराना पड़ा था। (एपी)

हेलीकाप्टर दुर्घटना में पांच अमेरिकी नौसैनिकों की मौत

सैन डिएगो : सैन डिएगो के बाहर पहाड़ी क्षेत्र में तूफानी मौसम में फंस जाने से हुई हेलीकाप्टर दुर्घटना में पांच अमेरिकी नौसैनिकों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि सीएच-53ई सुपर स्टालिअन हेलीकाप्टर मंगलवार रात लापता हो गया। उस समय हेलीकाप्टर लास वेगास के उत्तर पश्चिम में क्रीच वायुसैनिक अड्डे से प्रशिक्षण के बाद सैन डिएगो में मरीन कोर एयर स्टेशन मिरामर लौट रहा था। दिवंगत नौसैनिकों के नाम अभी नहीं बताए गए हैं। एक बयान में बताया गया है कि पांचों के शव की तलाश जारी है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। (एपी)

अमेरिका में असम प्रवासियों ने हिमंत को दूरदर्शी सीएम बताया

वाशिंगटन : वैश्विक असमी उद्यमिता फोरम की प्रमुख अंजना बोरदोलोई ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा एक प्रगतिशील और दूरदर्शी नेता हैं जिनकी अगुआई में राज्य सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में अतुलनीय प्रगति कर रहा है। वैश्विक असमी उद्यमिता फोरम विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले असम के उद्यमियों को जोड़ने वाला मंच है। ज्यादातर असमिया उद्यमी अमेरिका में रहते हैं, लेकिन वे कनाडा, सिंगापुर, बहरीन, पश्चिम एशिया के सभी देशों और आस्ट्रेलिया में भी हैं। (प्रेट्र)

सिंगापुर की कंपनी के भारतवंशी निदेशक को जेल

सिंगापुर : जर्मनी के वायरकार्ड एजी से दिसंबर 2014 से सितंबर 2015 के बीच 5.4 करोड़ यूरो से ज्यादा राशि प्राप्त करने वाली सिंगापुर की कंपनी के निदेशक 60 वर्षीय भारतवंशी थिलागरत्नम राजरत्नम को कर्तव्य में लापरवाही के लिए बुधवार को चार सप्ताह जेल की सजा सुनाई गई। भुगतान करने का काम करने वाली कंपनी वायरकार्ड एजी ने जून 2020 में दिवालिया घोषित करने के लिए अर्जी दाखिल कराई थी। कंपनी ने स्वीकार किया था कि उसके खातों से 1.9 अरब यूरो नकद गायब हैं। उस समय कंपनी के पूर्व मुख्य कार्यकारी मार्कस ब्राउन और अन्य कई शीर्ष अधिकारियों को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। (प्रेट्र)

बर्लिन में लाल राजहंस की 75 वर्ष की उम्र में मौत

बर्लिन : बर्लिन चिड़ियाघर में लाल राजहंस की 75 वर्ष की उम्र में मौत हो गई। इसराज हंस को चिड़ियाघर में 1955 में तत्कालीन कम्युनिस्ट शासित पूर्वी जर्मनी के भाग वाले बर्लिन के टीयरपार्क चिड़ियाघर से लाया गया था। इस पक्षी के मूल निवास की जानकारी स्पष्ट नहीं है। पक्षी के पैर पर लगे रिंग पर काहिरा 23 जून, 1948 अंकित है। हाल ही में यह राजहंस थोड़ा लंगड़ा कर चलने लगा था। यह पक्षी जंगल के राजहंस के लगभग 30 वर्ष के औसत जीवन काल से कहीं अधिक समय तक जीवित रहा। (एपी)

महिलाओं के कोटा का मामला निर्वाचन आयोग को भेजा

इस्लामाबाद : इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आम चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं के लिए पांच प्रतिशत सामान्य सीट कोटा उल्लंघन करने का मामला निर्वाचन आयोग को लौटा दिया है। जस्टिस उमर फारूक ने बुधवार को कहा कि गुरुवार को होने वाला मतदान नहीं रोका जा सकता, लेकिन न्यायाधीश ने पाकिस्तान निर्वाचन आयोग को चुनाव के बाद कानून के अनुसार, शिकायत पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। औरत फाउंडेशन ने निर्वाचन आयोग के विरुद्ध चुनाव अधिनियम 2017 की धारा 206 का अनुपालन नहीं कराने के लिए याचिका दाखिल कराई है। धारा 206 में कहा गया है कि सभी पार्टियां नेशनल असेंबली की सामान्य सीटों में से पांच प्रतिशत और प्रांतीय असेंबली में से चार प्रतिशत सीटों पर महिला प्रत्याशी उतारेंगी। (प्रेट्र)

लोगान हवाई अड्डे पर एक विमान दूसरे से टकराया

बोस्टन: बोस्टन के लोगान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को दो जेटब्ल्यू विमानों के एक दूसरे से टकराने से उड़ानें बाधित हो गईं। बताया गया कि एक विमान की विंगटिप दूसरे विमान के टेल से रगड़ खा गई। मैसाचुसेट्स पोर्ट अथारिटी के जेनिफ मेहिगन ने बताया है कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई और दोनों की उड़ानें निरस्त कर दी गईं। यात्रियों को दूसरे विमान से भेजा गया। (एपी)

पाक में आज सामने आएगी नई सरकार की तस्वीर

मतगणना शुरू ▶ नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल (एन) के आगे रहने का अनुमान

खैबर पख्तूनख्वा प्रांत चुनाव ड्यूटी के दौरान हमले में पांच पुलिसकर्मियों की मौत

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान में हिंसा के बीच आम चुनाव के लिए गुरुवार शाम मतदान पूरा हो गया और मतगणना शुरू हो गई, शुक्रवार दोपहर तक ज्यादातर परिणाम आने की उम्मीद है। चुनाव ड्यूटी के दौरान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खां जिले में सुरक्षाकर्मियों के वाहन पर हमले में पांच पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। बाशबूद पंजगुर में हुए विस्फोट में दो बच्चों के मरने की सूचना है, अन्य घटनाओं में भी दो लोग मारे गए हैं। वैसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया था। चुनाव सर्वे में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) को आगे माना जा रहा है। नवाज को सेना का समर्थन भी माना जा रहा है।

पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने कहा है कि मतदान के प्रति लोगों के उत्साह से राष्ट्र निर्माण की उनकी इच्छा का संकेत मिल गया है। मतदान के बाद मतगणना स्थलों पर ही उम्मीदवारों के एजेंटों के समक्ष मतपेटियों की सील तोड़कर मतगणना शुरू कर दी गई। मतगणना संचालित कराने वाले पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग आफीसर के जरिये चुनाव प्रबंधन व्यवस्था को सूचित करेंगे और परिणाम की घोषणा करेंगे।

चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराने के लिए मतगणना स्थलों के आसपास करीब साढ़े छह लाख सुरक्षाकर्मियों को नियुक्त किया गया है। चुनाव में पीएमएल (एन) के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने की उम्मीद जताई जा रही है जबकि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) को मुकाबले में माना जा रहा है।

चुनाव चिह्न क्रिकेट बैट के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग द्वारा रोक लगाने के कारण पीटीआइ के उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। पाकिस्तान की नई सरकार के लिए आर्थिक तंगी और आतंकवाद से निपटना बड़ी चुनौती होगी। बुधवार को ही बलूचिस्तान में हुए दो विस्फोटों में 30 लोगों की जान गई है। चीन ने भी स्थिति पर चिंता जताई है।

पाकिस्तान में आम चुनाव के दौरान गुरुवार को हैदराबाद शहर में स्थित पोलिंग स्टेशन पर मतदान करती महिला। एपी

पाकिस्तान में आम चुनाव के दौरान गुरुवार को लाहौर में पोलिंग स्टेशन पर मतदान के लिए पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के प्रमुख नवाज शरीफ और उनकी पुत्री मरयम नवाज। एपी

प्रमुख लोगों ने किया मतदान का आह्वान

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान में गुरुवार को कई सेलेब्रेटी, एक्टर और क्रिकेटर ने वोट डालने के बाद स्याही लगा अपना अंगूठा मीडिया को दिखाया और लोगों से वोट डालने का आह्वान किया। फिल्म एक्टर और प्रोड्यूसर हुमायूं सईद ने एक्स पर पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए वोट डालने का आह्वान किया। एक्ट्रेस सबा कमर ने भी पाकिस्तानियों को मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान करने का अनुरोध किया। इसी प्रकार से भारत में शाह रुख खान के साथ फिल्म रईस में काम करने वाली माहिरा खान ने भी लोगों से मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। पाकिस्तानी क्रिकेट के बड़े नाम वसीम अकरम ने अपने आनलाइन संदेश में आठ फरवरी को पाकिस्तान के लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिन बताया और लोगों से वोट डालने को कहा। पाकिस्तान की टी 20 क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की थी।

रियाद डिफेंस शो में दिखी भारतीय सशस्त्रबलों में नारी शक्ति की झलक

नई दिल्ली, प्रेट्र : रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मियों में तीन महिला सैन्य अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ, कर्नल पोनुंग डोमिंग और लेफ्टिनेंट कमांडर अन्नू प्रकाश भी शामिल रहीं। पांच दिवसीय मेगा इवेंट चार फरवरी को शुरू हुआ था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इनकी भागीदारी रक्षा परिदृश्य में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रमाण है। तीनों ने विश्व डिफेंस शो के विभिन्न सेमिनारों में खासकर रक्षा थीम पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व किया।

स्क्वाड्रन लीडर भावना ने बाधाओं को तोड़ने और आसमान में उड़ान भरने की अपनी प्रेरक यात्रा साझा की। वह 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट हैं। कर्नल पोनुंग डोमिंग उत्तरी क्षेत्र में 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित बोर्डर टास्क फोर्स की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। एक इंजीनियरिंग अधिकारी होने के नाते वह कई चुनौतीपूर्ण कार्यों में सबसे आगे रही हैं। वहीं, भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर अन्नू प्रकाश ने समुद्री सुरक्षा और संचालन में अपनी विशेषज्ञता को सामने रखा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनकी भागीदारी ने विशाल तटरेखा की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है।

स्वीडन का दावा, ईरानी हमले की साजिश को नाकाम किया

स्टाकहोम, एपी : स्वीडिश सुरक्षा पुलिस के एक वरिष्ठ सदस्य ने गुरुवार को कहा कि ईरान ने देश पर हमले की साजिश रची है, जिसे नाकाम कर दिया गया है। उनका बयान स्थानीय मीडिया में आई उस खबर के बाद सामने आया है कि कई साल पहले तीन स्वीडिश यहूदियों को मारने की साजिश के लिए दो ईरानियों को निर्वासित किया गया था।

स्वीडन की घरेलू सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख डैनियल स्टेनलिंग ने गुरुवार को कहा, ईरान स्वीडन में किसी के खिलाफ हमला करने के उद्देश्य से तैयारी कर रहा है, जिसे विफल कर दिया गया है। स्वीडिश ब्राडकास्टर एसआर के अनुसार, दो निर्वासित ईरानियों ने अफगानी होने का दावा करते हुए 2015 में स्कैंडिनेवियाई देश में शरण मांगी और अंततः उन्हें स्वीडन में आश्रय मिला। रिपोर्ट में उनकी पहचान महदी रमजानी और फरेशतेह सनाइफारिद के रूप में की गई और कहा गया कि उनके ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड से संबंध हैं।

पश्चिम एशिया की यात्रा के बाद खाली हाथ लौटे ब्लिंकन

तेल अवीव, एपी: अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा में युद्धविराम और पश्चिम एशिया में व्याप्त तनाव को दूर करने के लिए चार देशों की यात्रा के बाद गुरुवार को पश्चिम एशिया छोड़ दिया। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिम एशिया की उनकी यह पांचवीं यात्रा थी। हमास के ताजा समझौता प्रस्तावों को इजरायल की पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहकर सिरे से खारिज कर दिया कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक कि इजरायल पूरी तरह से विजयी नहीं हो जाता। इस तरह अमेरिकी विदेश मंत्री की यात्रा से कुछ खास हासिल होता नहीं दिखा। लेकिन ब्लिंकन ने कहा कि इजरायल के इन्कार के बीच उसी समय हमें समझौते की गुंजाइश भी दिखाई दी।

इजरायल और उसके मुख्य अंतरराष्ट्रीय सहयोगी अमेरिका के बीच संबंध महीनों से तनावपूर्ण हैं। बुधवार को हमास ने इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले गाजा में 135 दिनों के युद्धविराम की योजना का मसौदा दिया था। लेकिन नेतन्याहू द्वारा उस योजना को सार्वजनिक रूप से खारिज करना, जिसके बारे में अमेरिका का कहना है कि इसमें योग्यता है, यह कम से कम आगे की बातचीत के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में मतभेद को उजागर करता है। फिर भी ब्लिंकन और अन्य अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि वे आशावादी बने हुए हैं। फलस्तीनी नागरिकों के लिए मानवीय स्थितियों में सुधार, हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करना और युद्ध को फैलने से रोकना जैसे उनके मुख्य लक्ष्यों पर प्रगति हो सकती है।

कहा, हमास के प्रस्तावों को इजरायल के खारिज करने के बाद भी गुंजाइश

नेतन्याहू ने कहा, युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक पूर्ण विजय न हो जाए

इजरायली सेना के आपरेशन में वेस्ट बैंक के नूर शम्स स्थित शरणार्थी शिविर के पास नष्ट हुए भवनों के मलबे में सामान तलाशते फलस्तीनी बच्चे। एपी

इजरायल ने दक्षिणी गाजा के रफाह में की भीषण गोलाबारी

गाजा में युद्धविराम की कोशिशों के बीच इजरायल ने गुरुवार को दक्षिणी गाजा में रफाह पर भीषण गोलाबारी की। यहां पर गाजा की आधा आबादी शरण लिए हुए है। स्थानीय निवासियों ने कहा, बुधवार रात और गुरुवार को गोलाबारी में 13 लोगों की जान गई है। टैंकों ने पूर्वी रफाह के कुछ इलाकों में भी गोले बरसाए। इस तरह, गाजा में इजरायली हमले में अब तक 27,840 फलस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली गोलाबारी को देखते हुए मानवीय सहायता में जुटी एजेंसियों ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा, रफाह में गोलाबारी से स्थिति और खराब होगी। यहां पहले से ही राहत कार्यों की स्थिति अच्छी नहीं है। इस बीच, हमास के सह-संस्थापक शेख हसन के बेटे मोसाब हसन यूसुफ ने कहा कि हमास लोगों की परवाह नहीं करता।

अमेरिका ने हाउती विद्रोहियों के तीन मिसाइलों को मार गिराया

अमेरिका ने बुधवार को कहा कि उसने लाल सागर में आत्मरक्षा के लिए तीन हाउती विद्रोहियों के क्रूज मिसाइल को मार गिराया। ये क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के जहाजों और व्यापारी जहाजों के लिए तत्काल खतरा थे। अमेरिकी कमांड ने कहा कि उसने स्थानीय समय के अनुसार बुधवार रात नौ बजे हाउती की दो पोत रोधी क्रूज मिसाइलों को नष्ट कर दिया, वे लाल सागर में जहाजों पर हमले की तैयारी में थी। इसके बाद रात साढ़े ग्यारह बजे एक और क्रूज मिसाइल को मार गिराया।

पीएम मोदी के लिए समर्थन जुटाने के लिए विदेश से भी चलेगा अभियान

वाशिंगटन, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को तीसरा टर्म दिलाने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी अभियान चलाए जाने की तैयारी है। इसके लिए अमेरिका के ओवरसीज फ्रेंड्स आफ बीजेपी ने कई योजनाएं बनाई हैं। इसमें देशभर में 25 लाख लोगों को फोन कर प्रधानमंत्री को एक बार फिर से जिताने के वोट देने की अपील की जाएगी। साथ ही 3000 भारतवंशियों का प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा जाएगा। यह देशभर में कई स्थानों पर भाजपा और उनके उम्मीदवारों के समर्थन में कैंपेन चलाएंगे।

काल करने और विभिन्न राज्यों और भाषाओं के अनुसार रणनीति विकसित करने में मदद करने के लिए पूरे अमेरिका में दो दर्जन से अधिक टीमें भी बनाई गई हैं। संस्था की ओर से कहा गया है कि इसके लिए दिसंबर से तैयारियां जारी हैं। अब इसने और गति पकड़ ली है। ओएफबीजेपी यूएसए के अध्यक्ष अदापा प्रसाद ने बताया कि फरवरी में हम पूरे अमेरिका में एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हम न केवल ओवरसीज फ्रेंड्स आफ बीजेपी के समर्थकों और स्वयंसेवकों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आम समुदाय, समुदाय के नेताओं और उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं।

हम अपने सभी एनआरआइ भाइयों और भारतीय प्रवासियों से आग्रह करेंगे कि वे अपने दोस्तों और परिवारों को भाजपा के लिए वोट करने के लिए कहें। वे उन्हें बताएंगे कि उन्हें भाजपा को वोट क्यों देना चाहिए और वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की सभी उपलब्धियां गिनाएंगे।

देशभर में 25 लाख लोगों को फोन कर वोट देने की अपील की जाएगी

अमेरिका, आस्ट्रेलिया व जापान का दक्षिण चीन सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास

ताइपे, एपी : चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका, आस्ट्रेलिया व जापान के युद्धपोतों ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त युद्धाभ्यास किया। चीन लगभग पूरे रणनीतिक जलमार्ग पर संप्रभुता का दावा करता है। अमेरिका की सातवीं फ्लीट की ओर से कहा गया कि गाइडेड मिसाइड डिस्ट्राबयर यूएसएस जान फिन और युद्धक जहाज यूएसएस ग्रेब्रियल गिफोर्ड्स ने जापान और आस्ट्रेलिया की नौसैनिक जहाजों के साथ बुधवार और गुरुवार को युद्धाभ्यास में भाग लिया। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या यह अभ्यास बीजिंग द्वारा दावा किए गए द्वीपों और तटों के करीब हुए थे। जान फिन के कमांडिंग आफिसर कमांडर अर्विन टेलर ने कहा, अभ्यास सहयोगियों के बीच संबंधों को मजबूत करता है। हम पारदर्शिता, कानून के शासन, नेविगेशन की स्वतंत्रता और उन सभी सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं जो हिंद-प्रशांत में सुरक्षा व समृद्धि को रेखांकित करते हैं। आस्ट्रेलियाई कमोडोर जोनाथन ले बोले, यह साथ काम करने की क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारतीय छात्रों की मौत में कोई साजिश नहीं : विदेश मंत्रालय

न्यूयार्क, एएनआइ : पड्र्यू विश्वविद्यालय में मृत पाए गए भारतीय छात्र समीर कामथ की मौत को अमेरिकी अधिकारियों ने आत्महत्या बताया है। अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि छात्र ने खुद को गोली मार ली थी। अमेरिका में भारतीय छात्र की इस वर्ष यह पांचवीं मौत है। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि इन घटनाओं में न तो कोई साजिश सामने आई है और न ही इनका परस्पर संबंध है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पांच भारतीय छात्र मारे गए हैं, जिनमें प्रवासी छात्र भी शामिल हैं। इनमें से दो भारतीय नागरिक हैं और बाकी तीन भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं।

जार्जिया के लिथोनिया में एक स्टोर के अंदर एक शख्स द्वारा विवेक सैनी की हथौड़े से बेरहमी से हत्या मामले का जिक्र करते हुए जायसवाल ने कहा अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिनसिनाटी विश्वविद्यालय के एक अन्य मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हालांकि, मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने कहा कि जो अन्य तीन मौतें हुई हैं, वे भारतीय मूल के लोगों की हैं, जो अमेरिकी नागरिक हैं। हम भारतीय नागरिकों के मामले में स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं।

वहीं, हाल ही में शिकागो में हैदराबाद निवासी माजिर अली पर हमले को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय वाणिज्य दूतावास परिवार और अली के संपर्क में है। हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे चिकित्सा सहायता कैसे पहुंचाई जाए। छात्र अली पर चार लुटेरों ने हमला किया था।

अमेरिका में पांच भारतीय छात्रों की इस वर्ष हो चुकी है मौत

अमेरिका में प्रतिदिन एक भारतीय की मौत देख रहे हैं : गैर लाभकारी संगठन

अमेरिका में भारतीय छात्रों की लगातार हो रही मौतों पर चिंताओं के बीच समुदाय के एक प्रमुख नेता ने कहा, उनका संगठन प्रतिदिन कम से कम एक ऐसे दुखद मामले से निपट रहा है। गैर लाभकारी संगठन टीम एडा के संस्थापक मोहन नन्नापनेनी ने कहा, भारतीय अप्रवासियों के बीच जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। नन्नापनेनी ने कहा, हम हर दिन एक मौत देख रहे हैं। ज्यादातर युवा छात्र या एच-1बी वीजा पर आए कर्मचारी हैं, जो हाल ही में अमेरिका आए हैं। मेरा सुझाव है कि छात्रों को खुद को जोखिम में नहीं डालना चाहिए या अवैध, जोखिम भरी नौकरियां नहीं अपनानी चाहिए।

रूसी सैन्य कार्रवाई का विरोध करने पर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोका

मास्को, एपी: रूस के मुख्य चुनाव प्राधिकरण ने गुरुवार को यूक्रेन में मास्को की सैन्य कार्रवाई का विरोध करने वाले राजनेता को आगामी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। मास्को के पास एक कस्बे के स्थानीय विधायक बोरिस नादेजदीन को कानून के अनुसार, उम्मीदवारी के समर्थन में कम से कम 100,000 हस्ताक्षर इकट्ठा करने की जरूरत थी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने नादेजदीन के अभियान द्वारा प्रस्तुत 9,000 से अधिक हस्ताक्षरों को अमान्य घोषित कर दिया। 60 वर्षीय नादेजदीन ने खुले तौर पर यूक्रेन में संघर्ष को रोकने और पश्चिम के साथ बात शुरू करने का आह्वान किया है। नादेजदीन ने चुनाव अधिकारियों से निर्णय स्थगित करने और उन्हें अधिक समय देने को कहा, पर इससे इन्कार कर दिया गया। उन्होंने कहा, वह अयोग्यता को अदालत में चुनौती दूंगा। यहां मैं नहीं खड़ा हूं। वह सभी रूसी नागरिक मेरे पीछे हैं जिन्होंने मेरे लिए हस्ताक्षर किए थे।

अमेरिका पर कम भरोसे के चलते रूस के निकट गया भारत : निक्की

वाशिंगटन, एपी: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी के लिए भारतवंशी निक्की हेली पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने डटकर खड़ी हैं। आयोवा, न्यू हैंपशायर की पराजय के बाद नेवादा में भी शर्मनाक हार के बाद उन्होंने अपना ध्यान अब कैलिफोर्निया प्राइमरी के लिए केंद्रित कर दिया है। उन्होंने अमेरिकी नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा, भारत अमेरिका का साझेदार बनना चाहता है पर वह इस पर विश्वास नहीं करता, इसलिए अपनी जरूरतों के लिए वह रूस से निकटता बनाए हुए है।

डेमोक्रेटिक पार्टी में प्रत्याशी बनने के लिए जो बाइडन के सामने कोई खास चुनौती नहीं है, पर रिपब्लकन पार्टी में घमासान है। नेवादा में हार के बावजूद हेली ने लास एंजिलिस में इंडोर रैली में कहा, वह दौड़ से हटने वाली नहीं हैं। वह कहीं नहीं जा रहीं। हेली ने एक सवाल के जवाब में कहा, मेरी पीएम नरेन्द्र मोदी से बात हुई है। भारत अमेरिका का साझेदार बनना चाहता है न कि रूस का। वहीं, ट्रंप ने समर्थकों से कहा, नेवादा चुनाव को नजरअंदाज कर दीजिए, जनता ने हेली को शर्मनाक हार का मजा चखा दिया है।

दूसरी ओर, डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी की दौड़ से लेखिका व अध्यात्मिक गुरु मैरिएन विलियमसन हट गई हैं। उन्होंने कहा, समय आ गया है कि मैं प्रत्याशी बनने के लिए बाइडन को चुनौती दूं या दौड़ से बाहर हो जाऊं। मैंने अभियान रोकने का निश्चय किया है।

****

कहा, रिपब्लिकन उम्मीदवारी के लिए ट्रंप के सामने डटकर खड़ी हूं

डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी से हटीं लेखिका मैरिएन विलियमसन

भारतवंशी भाविनी व क्रिस्टल कौल लड़ रहीं संसदीय चुनाव

इंडिया आन व्हील्स नाम से फूड ट्रक संचालित करने में अपनी मां की मदद करने वाली भारतवंशी भाविनी पटेल प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ रही हैं। गुजराती मूल की 30 वर्षीया भाविनी पेन्सिलवेनिया के 12वें क्रांगेसनल डिस्ट्रक्ट से डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी के लिए दावा पेश कर रही हैं। भाविनी ने अपने अभियान के दौरान 3,10,000 डालर चंदा जुटाया हैं। एक और भारतवंशी क्रिस्टल कौल वर्जीनिया के 10वें कांग्रेसनल जिले से डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी के लिए चुनौती पेश कर रही हैं। यह चुनाव लड़ने वाली वह पहली कश्मीरी महिला हैं। उन्होंने अभियान के दौरान 5,67,000 डालर चंदा जुटाए हैं। वह एक पूर्व अमेरिकी सेना अधिकारी और विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ हैं।

सड़कों पर घमासान जारी, यूक्रेन ने रूसी हेलीकाप्टर मार गिराया

कीव, एपी : यूक्रेनी सेना ने गुरुवार को पूर्वी यूक्रेन के अवदीवका सिटी के पास एक रूसी हमलावर हेलीकाप्टर को मार गिराने का दावा किया। अवदीवका में सैनिक सड़कों पर युद्ध कर रहे हैं। रूसी सेना ने कीव की रक्षा कर रहे सैनिकों को घेरने के अपने चार महीने के अभियान को और तेज कर दिया है।

दक्षिण पूर्वी अग्रिम मोर्चे पर लड़ रही यूक्रेन की इकाइयों के कमांडर अलेग्जेंडर टर्नावस्की के अनुसार, यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी वायुसेना के सबसे खतरनाक में से एक केए-52 एलीगैटर हमलावर हेलीकाप्टर को पोर्टेबल विमान रोधी मिसाइल से मार गिराया। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने बताया कि उसके सैनिकों ने पिछले 24 घंटे के दौरान अवदीवका के ऊपर दुश्मन के 40 हमले विफल किए।

सर्दियों के दौरान लगभग 1500 किलोमीटर संपर्क रेखा में थोड़ा बदलाव आया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को एक्स पर अपने आकलन में कहा है कि यूक्रेन युद्ध के दो वर्ष पूरा होने के करीब रूसी सेना का ध्यान अवदीवका पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेनी सेना भारी बमबारी के बीच अपने मुख्य आपूर्ति मार्ग को खुला रखने में जुटी है, इसलिए सड़कों पर घमासान हो रहा है।

अवदीवका के लिए लड़ाई दोनों पक्षों के लिए गंभीर हो गई है। इसकी तुलना बखमुत के लिए नौ महीने तक चली यूक्रेन युद्ध की सबसे लंबी और सबसे खूनी लड़ाई से की जा सकती है।

पिछले वर्ष मई में बमबारी से तबाह और वीरान शहर पर कब्जे के साथ बखमुत के लिए लड़ाई का अंत हो गया। मास्को ने इसे बड़ी जीत माना था। अवदीवका और बखमुत दोनों जिस दोनेत्स्क क्षेत्र में हैं उस पूरे क्षेत्र पर रूस कब्जा करना चाहता है।

अवदीवका पर कब्जा करने के लिए रूस ने तेज किया अभियान

खेल को विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों का भी ध्यान रखने की जरूरत है। वह पिछले 15 साल से अधिक समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर उन्हें परिवार के साथ रहने के लिए खेल से ब्रेक की जरूरत है तो हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।
– नासिर हुसैन, पूर्व कप्तान, इंग्लैंड

टीम चयन पर माथापच्ची

- राजकोट टेस्ट में बुमराह को खिलाने पर विचार
- विराट के खेलने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : विशाखापत्तनम में इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज बराबर होने के बाद तीसरा टेस्ट 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाना है, लेकिन टीम चयन को लेकर माथापच्ची जारी है। दूसरा टेस्ट सोमवार को खत्म हुआ था और चर्चा थी कि बाकी टेस्ट मैचों के लिए मंगलवार को टीम की घोषणा की जा सकती है। बाद में टीम चयन के लिए गुरुवार को चयनकर्ताओं की बैठक होनी थी, लेकिन कुछ प्रमुख सदस्यों की अनुपस्थिति के चलते अब इसे शुक्रवार के लिए टाल दिया गया। चयनकर्ता शुक्रवार टीम चुनने बैठेंगे तो विशेष रूप से जसप्रीत बुमराह व विराट कोहली को लेकर मंथन करेंगे।

दूसरे टेस्ट में नौ विकेट लेकर टीम को शानदार जीत दिलाने वाले बुमराह को लेकर चयनकर्ताओं के बीच इस गेंदबाज के कार्यभार प्रबंधन को लेकर विचार विमर्श होगा। बुमराह ने इस टेस्ट सीरीज में अब तक 58 ओवर डाले हैं। पहले ऐसी खबरें थीं कि टीम प्रबंधन चौथे और अंतिम टेस्ट के लिए बुमराह को तरोताजा रखना चाहता है, जिसके चलते उन्हें राजकोट से आराम दिया जा सकता है। उनकी जगह मोहम्मद सिराज को टीम में जगह मिल सकती है, जिन्हें दूसरे टेस्ट में आराम दिया गया था। लेकिन बुमराह के प्रदर्शन राजकोट की पिच को देखते हुए मुख्य कोच राहुल द्रविड़, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और कप्तान रोहित के बीच विचार-विमर्श के बात लगता है कि इस निर्णय का मूल्यांकन किया जा सकता है। बुमराह ने इस सीरीज में 15 विकेट लिए हैं और 10 से कम के औसत से रन दिए हैं और भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की मुख्य कड़ी हैं। राजकोट में स्पिन के बजाय तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है और वहां बुमराह को टीम के साथ बनाए रखा जाने की संभावना अधिक है। विराट की उपलब्धता को लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। ऐसी अटकलें हैं कि विराट अगले दो या संभवतः पूरी सीरीज से ही बाहर हो सकते हैं। चयनकर्ताओं के पास भी विराट को लेकर कोई सूचना नहीं है कि वह खेलेंगे या नहीं। इससे पहले, विराट को शुरुआती दो टेस्ट मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया था, लेकिन पहला टेस्ट शुरू होने से दो दिन पहले उन्होंने निजी कारणों से नाम वापस ले लिया था। हालांकि विराट के खास दोस्त और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने बताया था कि विराट और अनुष्का दूसरी बार माता-पिता बनने वाले हैं। इसलिए विराट अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। विराट की जगह रजत पाटीदार को टीम में शामिल किया गया था।इस बीच, रवींद्र जडेजा और केएल राहुल की प्रगति के संबंध में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी से आशाजनक जानकारी मिल है। दोनों अलग-अलग कारणों से विशाखापत्तनम में दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाए थे। राहुल की टीम में वापसी तय लग रही है, जबकि जडेजा की संभावित वापसी टीम प्रबंधन द्वारा उनकी हैमस्ट्रिंग चोट के आकलन पर निर्भर करती है।

स्पिनरों की सफलता का श्रेय टीम माहौल और कप्तान को : रेहान अहमद

नई दिल्ली : भारत के दौरे पर इंग्लैंड के स्पिनरों ने शुरुआती दो टेस्ट मैचों में आशा से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है और युवा गेंदबाज रेहान अहमद ने इस सफलता का श्रेय टीम के माहौल और बेन स्टोक्स के नेतृत्व को दिया है। रेहान, टाम हार्टले और शोएब बशीर की स्पिन गेंदबाजों की तिकड़ी दो मैचों में 33 विकेट चटकाए हैं, तो रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव जैसे अनुभवी स्पिनरों ने आपस में 23 विकेट साझा किए हैं। 19 वर्षीय अहमद ने कहा, स्पिनरों का प्रदर्शन दिखाताहै कि टीम का माहौल कितना बढ़िया है। अपने देखा होगा कि हार्टले और बशीर यहां आने के बाद दबाव में नहीं दिखे और इसका श्रेय टीम को जाता है। हमारी टीम में माहौल और नेतृत्व ऐसा है कि आप यह भूल जाते है कि आप किसके विरुद्ध खेल रहे है। आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि आपको क्या करने की आवश्यकता है। रेहान ने दिसंबर 2022 में पाकिस्तान के विरुद्ध पदार्पण किया था।

बुमराह संपूर्ण गेंदबाज, टी-20 विश्व कप में भारत के लिए अहम होंगे : फिलैंडर

जोहानिसबर्ग, प्रेट्र : सभी प्रारूपों में जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन से प्रभावित दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज वर्नेन फिलैंडर ने कहा है कि वह इस साल होने वाले टी-20 विश्व कप में भारत की सफलता की कुंजी रहने के साथ सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज भी साबित होंगे। इंग्लैंड के विरुद्ध विशाखापत्तनम टेस्ट में नौ विकेट लेकर भारत को जीत दिलाने वाले बुमराह आइसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। फिलैंडर ने कहा कि बुमराह इस समय संपूर्ण गेंदबाज हैं। उनके पास जबरदस्त कौशल है और उन्होंने सटीक गेंदबाजी का हुनर सीख लिया है।

रोहित शर्मा ● फाइल फोटो, प्रेट्र

ट्राफी के लिए टकराएंगे भारत-आस्ट्रेलिया

अंडर-19 विश्व कप

दूसरे सेमीफाइनल में आस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान एक विकेट से हराया, स्ट्रेकर ने झटके छह विकेट, रविवार को खेला जाएगा खिताबी मुकाबला

बेनोनी, प्रेट्र : अंडर-19 विश्व कप की ट्राफी छठी बार जीतने के लिए भारतीय टीम का सामना आस्ट्रेलिया से होगा। आस्ट्रेलिया ने गुरुवार को दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को एक विकेट से रोमांचक जीत दर्ज करते हुए फाइनल मुकाबले में जगह बनाई। फाइनल रविवार को खेला जाएगा। भारत और आस्ट्रेलिया के बीच ही पिछले वर्ष 19 नवंबर को वनडे विश्व कप का फाइनल खेला गया था, जिसमें आस्ट्रेलियाई टीम ने जीत दर्ज की थी। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 179 रन का स्कोर खड़ा किया था। छोटे लक्ष्य का पीछा करने के बावजूद आस्ट्रेलियाई टीम की बल्लेबाजी भी लड़खड़ा गई और टीम ने 49.1 ओवर में लक्ष्य प्राप्त करने तक नौ विकेट गंवा दिए थे।

तीसरी बार फाइनल में भिड़ेंगे दोनों : भारतीय टीम ने जहां रिकार्ड नौवीं और पांचवीं बार फाइनल में जगह बनाई है तो वहीं आस्ट्रेलियाई टीम अपना छठा अंडर-19 विश्व कप फाइनल खेलेगी। भारत ने पांच और आस्ट्रेलिया ने तीन बार ये ट्राफी जीती है। वहीं दोनों टीमों के बीच दो फाइनल खेला गया है, जिसमें भारत ने दोनों बार बाजी मारी है। भारतीय टीम ने 2012 और 2018 में आस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीता था। आस्ट्रेलिया ने अपना अंतिम खिताब 2010 में जीता था, जब उसने पाकिस्तान को हराया था।

पाकिस्तानी टीम तेज गेंदबाज स्ट्रेकर (6/24) के आगे संघर्ष करते दिखे। अगर अराफात मिन्हास (52) और अजान अवेस (52) के अर्धशतक नहीं होते तो यह स्कोर और कम होता। अवेस और मिन्हास ने मैदानी शाट व एक या दो रन से से ज्यादातर रन जुटाये। आस्ट्रेलियाई टीम भी पाकिस्तानी गेंदबाजों के आगे जूझती दिखी लेकिन इसके बावजूद 181 रन बनाकर फाइनल में पहुंचने में सफल रही।

जीत के बाद आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज व साथ में निराश पाकिस्तानी खिलाड़ी ● एक्स

टीम बांडिंग से विश्व कप जीतने का भरोसा है : सहारन

बेनोनी, प्रेट्र : लगातार पांचवीं बार अंडर 19 विश्व कप फाइनल में पहुंची भारतीय टीम के कप्तान उदय सहारन ने इसका श्रेय खिलाड़ियों के आपसी तालमेल को देते हुए कहा है कि फाइनल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके उनकी टीम इतिहास में नाम दर्ज कराने के लिए लालयित है। भारत का अंडर-19 विश्व कप में दबदबा इसी बात से साबित होता है कि पिछले नौ में से सात बार टीम फाइनल में पहुंची है।हर बार किसी खिलाड़ी ने जिम्मेदारी लेकर टीम को जीत तक पहुंचाया है। सहारन ने गुरुवार को कहा कि हमारी टीम के अच्छे प्रदर्शन का राज आपसी तालमेल है।हमारी बांडिंग इतनी अच्छी है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत दोस्ताना है। सभी एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और एक दूसरे की मदद को तत्पर रहते हैं। इसी से प्रदर्शन ग्राफ लगातार अच्छा रहा है। गर्व की बात है कि हम लगातार पांचवीं बार फाइनल में पहुंचे हैं।

एक नजर में

महिला हाकी टीम वापसी के लिए लगाएगी जोर

भुवनेश्वर : भारतीय महिला टीम एफआइएच प्रो लीग 2023-24 सत्र में लगातार तीन हार के बाद शुक्रवार को यहां जब अमेरिका के विरुद्ध मैदान में उतरेगी तो उसका लक्ष्य जीत की राह पर लौटने का होगा। पेरिस ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई करने में विफल रहने के बाद से सविता पूनिया की अगुआई वाली टीम के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई है। एफआइएच प्रो लीग के इस सत्र में भारतीय टीम को चीन ने 1-2, नीदरलैंड्स ने 1-3 और फिर बुधवार को आस्ट्रेलिया से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। (प्रेट्र)

अब पटियाला में होगी राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप

नई दिल्ली : अंडर-15 और अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन अब 28 फरवरी से पटियाला में किया जाएगा। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआइ) के संचालन के लिए गठित तदर्थ समिति ने गुरुवार को यह घोषणा की। पहले इस प्रतियोगिता का आयोजन 11 से 17 फरवरी के बीच ग्वालियर में किया जाना था लेकिन कुछ राज्य संघ ने समय कम होने के कारण इसमें भाग लेने में असमर्थता जताई थी। (प्रेट्र)

वुड्स की अगले सप्ताह वापसी

लास एंजिलिस: टाइगर वुड्स अगले हफ्ते रिवेरा में जेनेसिस इनविटेशनल में भागीदारी के साथ मौजूदा सत्र का अगाज करेंगे। वह पिछले साल मास्टर्स टूर्नामेंट के बाद पहली बार प्रतिस्पर्धी मुकाबले में उतरेंगे। वुड्स ने इंटरनेट मीडिया पर लिखा कि वह 15 फरवरी से शुरू होने वाले पीजीए टूर के अगले आयोजन का मेजबान बनने को लेकर उत्साहित है। रिवेरा गोल्फ कोर्स पर वुड्स ने सबसे ज्यादा 12 मुकाबलों में भाग लिया है। (एपी)

एमआइ को हराकर आइएलटी-20 प्लेआफ के करीब पहुंचे जायंट्स

नई दिल्ली, जेएनएन : गत चैंपियन गल्फ जायंट्स ने गुरुवार को आइएलटी-20 में रोमांचक मुकाबले में एमआइ एमिरेट्स को पांच रन से हराकर प्लेआफ में लगभग अपनी जगह पक्की कर ली है। जायंट्स के नौ मैचों में 10 अंक हो गए हैं और अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं एमआइ नौ मैचों में 12 अंक लेकर पहले ही प्लेआफ में जगह पक्की कर चुकी है।

जी फाइव व एंड पिक्चर्स पर प्रसारित मुकाबले में एमआइ ने टास जीतकर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। जायंट्स को कप्तान जेम्स विंस (59) ने तूफानी शुरुआत दिलाई और 4.2 ओवर में ही टीम का स्कोर 44 रन पहुंचा दिया। दूसरे छोर पर खड़े जोर्डन काक्स ने केवल इसमें दो रन का योगदान दिया। काक्स के आउट होने के बाद टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए। टीम 90 रन के भीतर पांच विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन अंत में जेमी स्मिथ ने सिर्फ 26 गेंदों में चार चौके और दो छक्के लगाते हुए 42 रन की पारी खेली और टीम का स्कोर 158 तक पहुंचाया। अपने नियमित कप्तान निकोलस पूरन के बगैर खेल रही एमआइ की सधी शुरुआत हुई, लेकिन 34 रन बनाने वाले कुसल परेरा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। मध्यक्रम लड़खड़ाने के बाद अंत में कप्तान की भूमिका निभा रहे कीरोन पोलार्ड ने 40 रन बनाकर टीम को अंतिम ओवर तक मैच में बनाए रखा, लेकिन जीत नहीं दिला पाए।

आइस पैलेस में लगी नीरज की पट्टिका

लुसाने, प्रेट्र : भारत के ओलिंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउजोक में मशहूर आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया जहां कई और स्टार खिलाड़ियों की पट्टिकाएं लगी हुई हैं।

नीरज की शानदार उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए स्विट्जरलैंड पर्यटन ने कहा कि जंगफ्राउजोक ने स्मारक पट्टिका का अनावरण करने के लिए इस एथलीट का स्वागत किया। जंगफ्राउजोक को 'यूरोप का शिखर' कहा जाता है। नीरज ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अपना एक भाला भी दिया और इसे पट्टिका के साथ ही रखा गया है। इस तरह वह रोजर फेडरर और गोल्फर रोरी मैकलराय जैसे स्टार खिलाड़ियों के साथ शामिल हो गए जिनकी भी आइस पैलेस में ऐसी स्मारक पट्टिकाएं हैं। नीरज ने पट्टिका के अनावरण पर आभार व्यक्त करते हुए कहा, 'इस देश में मुझे जो प्यार और सराहना मिली है, उससे मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैंने सपने में इस शानदार आइस पैलेस में पट्टिका लगाए जाने के बारे में भी नहीं सोचा था, फिर भी मैं यहां हूं। मैं बहुत खुश हूं जैसे मैं यूरोप के शिखर पर खड़ा हूं।' नीरज ने अपने भाला फेंकने के कौशल का प्रदर्शन करके आइस पैलेस में मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नीरज ने स्विट्जरलैंड में ओलिंपिक संग्रहालय को एक भाला उपहार में दिया था।

पट्टिका के साथ भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ● प्रेट्र

क्रिस गेल भारत में फिर विस्फोटक बल्लेबाजी का जलवा बिखेरेंगे

क्रिकेट डायरी

नई दिल्ली, जेएनएन : वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग (आइवीपीएल) के पहले संस्करण में तेलंगाना टाइगर्स की कप्तानी करेंगे।

आइवीपीएल का आयोजन 23 फरवरी से तीन मार्च तक देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा जिसमें क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी अपना जलवा बिखेरेंगे। गेल ने कहा, 'मैं पहले इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग में बड़े नामों के साथ मैदान पर वापस आ रहा हूं। आइवीपीएल के लिए तैयार हो जाइए।' गेल की तेलंगाना टाइगर्स में पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुदीप त्यागी और मनप्रीत गोनी तथा वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज रिकार्डो पोवेल भी होंगे। इस लीग का आयोजन भारतीय वेटरन क्रिकेट बोर्ड (बीवीसीआइ) द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसका प्रबंध 100 स्पोर्ट्स करेगा।

टीम चयन में आइपीएल का प्रदर्शन अहम होगा : मूडी

चेन्नई, प्रेट्र : अनुभवी कोच टाम मूडी ने कहा कि खिलाड़ियों का आइपीएल और आइएलटी-20 जैसी प्रतिस्पर्धी लीग में प्रदर्शन इस बार काफी मायने रखेगा क्योंकि इसका टी-20 विश्व कप से पहले टीम चयन पर असर पड़ेगा। मूडी ने गुरुवार को कहा कि मार्च और मई के बीच खेली जाने वाली आइपीएल के साथ अन्य टी-20 लीग जैसे आइएलटी-20 किसी भी खिलाड़ी के लिए महत्वपूर्ण है।

निकहत और अरुंधति स्ट्रैंड्जा मेमोरियल के सेमीफाइनल में

खेल डायरी

सोफिया, प्रेट्र : दो बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज निकहत जरीन और अरुंधति चौधरी ने गुरुवार को यहां अपने मुकाबले जीतकर 75वें स्ट्रैंड्जा मेमोरियल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

दो बार की स्वर्ण पदक विजेता निकहत (50 किग्रा) ने फ्रांस की लखादिरी वासिला को सर्वसम्मत फैसले में 5-0 से पराजित किया। हालांकि नतीजा जैसा दिख रहा था, उसकी तुलना में मुकाबला काफी चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि दोनों मुक्केबाजों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में निकहत फ्रांस की मुक्केबाज को हराने में सफल रहीं। अब निकहत का सामना शनिवार को सेमीफाइनल में घरेलू प्रबल दावेदार ज्लाटिस्लावा चुकानोवा से होगा। एक अन्य मुकाबले में राष्ट्रीय चैंपियन अरुंधति (66 किग्रा) ने सर्बिया की माटकोविक मिलेना के विरुद्ध दबदबा बनाते हुए 5-0 से जीत हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। साक्षी (57 किग्रा) को क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की मामाजोनोवा खुमोराबोनू से 2-3 से हार मिली।

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभंकर अष्टलक्ष्मी का अनावरण

शुभंकर अष्टलक्ष्मी के साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा (बाएं) और निशिथ प्रमाणिक ● आयोजक

नई दिल्ली, जेएनएन : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभंकर अष्टलक्ष्मी का अनावरण किया। अष्टलक्ष्मी एक तितली है। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक भी मौजूद थे। असम में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 16 स्पर्धाएं होंगी जिसमें एथलेटिक्स, रग्बी, बास्केटबाल, वालीबाल, तैराकी, बैडमिंटन, हाकी, तलवारबाजी, कबड्डी, फुटबाल, टेनिस, मल्लखंब, जूडो, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी और निशानेबाजी शामिल है।

वरुण प्रो लीग से हटे

नई दिल्ली : पाक्सो कानून के तहत दुष्कर्म के आरोपी और अर्जुन पुरस्कार विजेता भारतीय हाकी खिलाड़ी वरुण कुमार ने इसे पैसे ऐंठने का सुनियोजित प्रयास करार देते हुए अपने पर लगाए गए आरोपों के विरुद्ध कानूनी विकल्प तलाशने के लिए भुवनेश्वर में एफआइएच प्रो लीग से नाम वापस ले लिया है। हाकी इंडिया ने इस 28 वर्षीय खिलाड़ी को तत्काल अवकाश दे दिया है क्योंकि इस खिलाड़ी ने कहा था कि इस घटना से उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। वरुण ने हाकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की को लिखे पत्र में दावा किया है कि उनके विरुद्ध दर्ज की गई शिकायत झूठी है और यह राज्य के सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है।

डेविस कप में स्वीडन से भिड़ेगी भारतीय टीम

टेनिस डायरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत डेविस कप विश्व ग्रुप एक के मुकाबले में सितंबर में मेजबान स्वीडन का सामना करेगा। भारतीय डेविस कप टीम ने पिछले सप्ताह इस्लामाबाद में विश्व ग्रुप एक प्लेआफ में पाकिस्तान को 4-0 से करारी शिकस्त दी थी जबकि स्वीडन क्वालीफायर के पहले दौर में ब्राजील से 1-3 से हार गया था। भारत और स्वीडन के बीच डेविस कप में अभी तक पांच मुकाबले हुए हैं। भारतीय टीम हालांकि अभी तक स्वीडन को हराने में नाकाम रही है लेकिन इस बार उसके पास पहली जीत दर्ज करने का अच्छा मौका होगा क्योंकि मेजबान देश की टीम में कोई बड़ा सिंगल्स खिलाड़ी नहीं है। भारत और स्वीडन के बीच पिछला मुकाबला 2005 में हुआ था। दिल्ली में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम 1-3 से हार गई थी।

टामी पाल और शेल्टन क्वार्टर फाइनल में : अमेरिका के दूसरे वरीय टामी पाल और तीसरे वरीय बेन शेल्टन ने अपने मुकाबले जीतकर शेल्टन डलास ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पाल ने टारो डेनियल को 6-3, 6-2 से पराजित किया जबकि पिछले साल यूएस ओपन के सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविक से हारने वाले तीसरे वरीय शेल्टन ने माइकल ममोह पर 6-3, 6-3 से जीत हासिल की। पांचवीं वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी क्रिस्टोफर यूबैंक्स ने आस्ट्रेलिया के जेम्स डकवर्थ पर 7-6, 6-4 से जीत हासिल की।

श्रीवल्ली मुंबई ओपन के दूसरे दौर में हारीं: भारतीय टेनिस खिलाड़ी श्रीवल्ली भादिमिपति मुंबई ओपन के दूसरे दौर के मुकाबले में रूस की 16 वर्षीय अलीना कोर्नीवा से हार गईं।

प्रज्वल देव को बेंगलुरु ओपन के लिए वाइल्ड कार्ड मिला

बेंगलुरु, प्रेट्र : हाल में भारत की डेविस कप टीम में रिजर्व खिलाड़ी चुने गए प्रज्वल देव को गुरुवार को 12 फरवरी से शुरू होने वाले एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन के सिंगल्स मुख्य ड्रा के लिए वाइल्ड कार्ड से प्रवेश दिया गया। देव पिछले साल भी बेंगलुरु ओपन में खेले थे लेकिन पहले दौर में बाहर हो गए थे। वह 2023 में थाइलैंड में हुए आइटीएफ 15 के टूर्नामेंट में उपविजेता रहे और तीन अन्य टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे थे।

राष्ट्रीय फलक

राजस्थान में जेसीबी पर पथराव करने वाली महिलाओं को अग्रिम जमानत

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के झुंझनू में अतिक्रमण हटाने के दौरान जेसीबी पर पथराव करने और सरकारी काम में बाधा डालने वाली दो महिलाओं को अग्रिम जमानत दे दी।

जस्टिस जेबी पार्डीवाला और संदीप मेहता की पीठ ने कहा, हम दोनों अपीलकर्ताओं के महिलाएं होने व समाज के वंचित वर्ग से आने के कारण उनके पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करने को तैयार हैं। इससे पहले अगस्त 2023 में पीठ ने सुनवाई की पहली तारीख में दोनों को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश को रद करते हुए दोनों को एक हफ्ते के भीतर जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होने का आदेश दिया। पीठ ने यह भी कहा, गिरफ्तारी की स्थिति में दोनों को पांच-पांच हजार रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि के दो जमानती देने पर रिहा किया जाएगा। इससे पहले,हाई कोर्ट ने दोनों महिलाओं को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था। मामले में राजस्थान के झुंझनू के खेत्री थाने में दोनों के खिलाफ आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पहले झूठी गवाही, फिर दुष्कर्म के आरोप से मुकरी युवती को जेल

जागरण संवाददाता, बरेली

- बरेली में युवती के पिता की शिकायत पर चार वर्ष से जेल में है युवक
- झूठे बयान देने पर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में लेने का दिया आदेश

जिस मुकदमे में अजय उर्फ राघव चार वर्ष से जेल में बंद है, उसमें गुरुवार को अचंभित करने वाला घटनाक्रम हुआ। कोर्ट पहुंची दुष्कर्म पीड़िता ने मुख्य परीक्षा (गवाही के प्रथम चरण में कोर्ट में दिए जाने वाले बयान) में मुकदमे में दर्ज घटनाक्रम पर हामी भरी। कहा कि अजय ने दुष्कर्म किया था। इसके बाद गवाही शुरू हुई। दूसरे पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की तो युवती के बयान बदल गए। कहने लगी कि कुछ देर पहले (मुख्य परीक्षा में) मैंने जो गवाही-बयान दिए, वो झूठे थे। स्पेशल जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) निर्दोष कुमार ने उससे पूछताछ की। इसके बाद झूठे बयान देने के आरोप में सीजेएम कोर्ट ले जाने के आदेश दिए। वहां परिवाद दर्ज कर युवती को जेल भेज दिया गया।

वर्ष 2019 में युवती के पिता ने अजय के विरुद्ध बहला-फुसलाकर ले जाने की प्राथमिकी पंजीकृत कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई। चार साल से आरोपित जेल में है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इस मामले में अब तक छह गवाहों के बयान हो चुके हैं। गुरुवार को पीड़ित युवती को गवाही के लिए कोर्ट बुलाया गया था। मुख्य परीक्षा के दौरान युवती को मुकदमे में लिखे आरोप पढ़कर सुनाए गए तो हामी भरी। कुछ देर बाद गवाही एवं जिरह के दौरान कहने लगी कि मैंने झूठे बयान दिए थे।

दो कोर्ट में चलेगा प्रकरण : फास्ट ट्रैक कोर्ट में झूठी गवाही का प्रकरण निचली कोर्ट यानी सीजेएम सौरभ कुमार वर्मा के यहां भेजा गया। वहां युवती के विरुद्ध परिवाद दर्ज हुआ। इसके बाद जज ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। झूठी गवाही के प्रकरण की सुनवाई अब इसी कोर्ट में होगी। दुष्कर्म मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही जारी रहेगी। इसके लिए 21 फरवरी तय की गई है।

समीर वानखेड़े की शिकायत पर अदालत ने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी

जासं, नई दिल्ली : भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस) के अधिकारी समीर वानखेड़े की एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली शिकायत पर पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंदर कुमार जांगला ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। साथ ही 27 फरवरी को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

वानखेड़े ने अपनी शिकायत में आइपीएस अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह पर कार्डेलिया ड्रग्स भंडाफोड़ मामले से संबंधित जांच के दौरान उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस कार्रवाई में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। शिकायत में कहा गया है कि ज्ञानेश्वर सिंह ने अनुसूचित जाति के सदस्य वानखेड़े को अपमानित किया और धमकी दी कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि वानखेड़े को नौकरी छोड़ना पड़े। वानखेड़े ने कहा, शिकायत मुंबई पुलिस के पास दर्ज की गई थी, जिसे कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बावजूद अभी तक दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की।

बंगाल की जेलों में कुछ महिला कैदी हुईं गर्भवती

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- न्याय मित्र की ओर से कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में जिक्र
- महिला कैदियों के बैरक में पुरुष कर्मियों के प्रवेश पर पाबंदी का सुझाव

कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए न्याय मित्र ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें दावा किया गया है कि बंगाल की जेलों में कुछ महिला कैदी गर्भवती हुई हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने गुरुवार को इसको आपराधिक खंडपीठ को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। न्याय मित्र ने रिपोर्ट में यह भी कहा कि 196 बच्चे अलग-अलग सुधार गृहों में रह रहे हैं।

जेलों में भीड़भाड़ को लेकर 2018 में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद कोर्ट ने वकील तापस कुमार भंज को न्याय मित्र नियुक्त किया। भंज ने कुछ जेलों का दौरा कर मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

इसमें कहा गया है कि महिला कैदी हिरासत में गर्भवती हुई हैं। बंगाल की विभिन्न जेलों में लगभग 196 बच्चे रह रहे हैं। भंज ने सुधार गृहों के पुरुष कर्मचारियों के महिला कैदियों के बैरक में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। पीठ ने कहा कि रिपोर्ट गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करती है। इसकी एक प्रति राज्य के महाधिवक्ता के कार्यालय में भेज दी गई है। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट में इंगित सभी मामलों पर प्रभावी निर्णय लेने के लिए हम इसे उचित मानते हैं कि इसको आपराधिक रोस्टर निर्धारण वाली खंडपीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए।

गौरतलब है कि हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वर्ष 2018 में राज्य में जेलों में भीड़भाड़ पर स्वतः संज्ञान लिया था। कुछ संबंधित मामले, जो पहले और बाद में दायर किए गए थे, उन्हें भी इस मामले के साथ जोड़ा गया था। अब इस मामले में बाद में सुनवाई होगी।

इसरो 17 फरवरी को लांच करेगा मौसम संबंधी उपग्रह इनसेट-3डीएस

बेंगलुरु, प्रेट्र : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मौसम संबंधी उपग्रह इनसेट-3डीएस को 17 फरवरी को लांच करेगा। इसरो ने गुरुवार को कहा कि इस उपग्रह को जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट लांच व्हीकल (जीएसएलवी) एफ-14 के जरिये 17 फरवरी को शाम 5:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) से प्रक्षेपित किया जाएगा।

यह उपग्रह मौसम का बेहतर पूर्वानुमान और आपदा संबंधी चेतावनी देने में मदद करेगा। इनसेट-3डीएस भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किए जाने वाले तीसरी पीढ़ी के मौसम उपग्रह का मिशन है। जीएसएलवी शक्तिशाली राकेट है, जो भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। इसरो ने कहा कि उपग्रह को मौसम संबंधी अवलोकन करने, मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी के लिए भूमि और महासागर सतहों की निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उपग्रह वर्तमान में संचालित इनसेट-3डी और इनसेट-3डीआर उपग्रहों के साथ-साथ मौसम संबंधी सेवाओं को भी बढ़ाएगा। भारतीय उद्योगों ने उपग्रह के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

दैनिक जागरण
सप्तरंग
मनोरंजन की दुनिया का
शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024

मेरी बात

प्रेम कहानियों में जंचता हूं

कई बार काम के सिलसिले में अपना घर, शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना होता है, पर काम अच्छे से चल जाए, तो कर्मभूमि भी खास हो जाती है। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा कहते हैं कि 18 वर्ष पहले मैं दिल्ली से मुंबई आया था। अब यहां मेरा घर-परिवार सबकुछ है, लेकिन दिल्ली में जो समय बिताया है, उसकी वजह से जो मेरे जीने और सोचने का तरीका है, वह वहां के परिवेश के अनुसार है। वे चीजें बदली नहीं हैं, क्योंकि वह ऐसा समय होता है, जब आपका सोच आकार ले रहा होता है। जब मुंबई आया, तो यहां पर समझदारी बढ़ी। पसंदीदा करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिला। आगामी दिनों में सिद्धार्थ करण जौहर के प्रोडक्शन की फिल्म योद्धा में नजर आएंगे। लगातार एक्शन फिल्में क्या सिद्धार्थ के लिए थकावट भरा नहीं हो जाता? वह कहते हैं कि मैंने हर तरह की भूमिकाएं की हैं। संयोग है कि कुछ समय से मेरे पास एक्शन फिल्में ही आ रही हैं, पर योद्धा के बाद एक प्रेम कहानी में दिखूंगा। मुझे दर्शकों ने प्रेम कहानियों में पसंद किया है। एक विलेन फिल्म में भी प्रेम कहानी थी। अब नई कहानियां ढूंढ़ रहा हूं।

स्मिता श्रीवास्तव

मुलाकात

फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में है एक रोबोट से प्यार की कहानी। सिनेमाघरों में आज प्रदर्शित होने वाली इस फिल्म में कृति सैनन बनी हैं रोबोट और उनके प्यार में डूबे नजर आएंगे शाहिद कपूर। फिल्म की कहानी, तकनीक के जीवन में दखल, डीपफेक सहित विभिन्न पहलुओं पर दोनों से स्मिता श्रीवास्तव की बातचीत के अंश:

कमाई अलग है किस्मत अलग

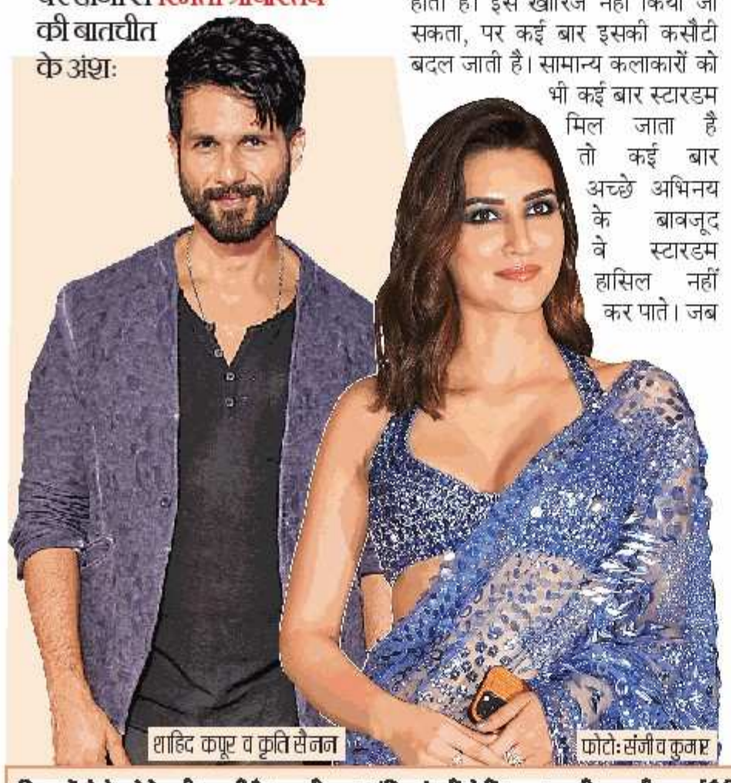

शाहिद कपूर व कृति सैनन — फोटो: संजीव कुमार

अक्सर कलाकार कहते हैं कि वे अच्छे अभिनय में विश्वास करते हैं, स्टारडम में नहीं। आप क्या सोचते हैं?

शाहिद: कलाकारों का स्टारडम तो होता है। इसे खारिज नहीं किया जा सकता, पर कई बार इसकी कसौटी बदल जाती है। सामान्य कलाकारों को भी कई बार स्टारडम मिल जाता है तो कई बार अच्छे अभिनय के बावजूद स्टारडम हासिल नहीं कर पाते। जब मेहनत और भाग्य दोनों का साथ हो तो सितारे चमक उठते हैं।

कृति: स्टारडम दर्शकों का प्यार है। जब आप अच्छा काम करते हैं, तो दर्शकों संग जुड़ाव बनता है। हालांकि इन बातों से इतर भी अच्छी अभिनेत्री के रूप में नाम कमाने का सपना लेकर इस इंडस्ट्री में आई थी।

दर्शकों का प्यार कई बार बाक्स आफिस से भी मापा जाता है...

शाहिद: बाक्स आफिस पर कमाई की रिपोर्टिंग से दर्शक प्रभावित होते हैं। कई बार लोगों को फिल्म का ट्रेलर पसंद नहीं आता तो भी वे कमाई और तारीफों के बारे में सुनकर फिल्म देखने चले जाते हैं, उन्हें बस जो ट्रेंडिंग है, उसका हिस्सा बनना है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग निष्पक्ष प्रतिक्रिया देते थे, सही चीजों की खुलकर पैरवी करते थे पर अब ऐसा नहीं रह गया है। मीडिया की वजह से जिस ओर झुकाव दिखता है, दर्शक उसी सुर में सुर मिलाने लगते हैं।

कृति: हर फिल्म के साथ चीजें अलग तरह से काम करती हैं। उनके बजट, कहानी की प्रासंगिकता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। पहले स्टारडम बहुत अधिक होता था, पर कमाई के ऐसे आंकड़े नहीं थे, इसलिए ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कमाई और स्टारडम दोनों में अंतर्संबंध है।

पहले की फिल्में लोगों के दिमाग में बस जाती थीं, जैसे शोले... उनके संवाद, दृश्य सब कुछ मस्तिष्क में छप जाते थे, पर आज की फिल्मों को देखें तो ऐसा नहीं लगता...

शाहिद: आज भी हो रहा है। अब चीजें अधिक प्रसारित हो रही हैं। लोग फिल्मों के संवाद की कापी करके अपनी रील बना रहे हैं।

कृति: बिल्कुल ऐसा ही है।

तकनीक का जीवन में दखल बहुत बढ़ गया है, पर इसके क्या दुष्प्रभाव देखते हैं?

कृति: तकनीक पर निर्भरता तो बढ़ी है। कोविड काल में तकनीक अपनों से जुड़ने और उन्हें संबल देने का माध्यम बनी तो ये भी देखा गया कि इंटरनेट मीडिया से नकारात्मकता फैलती है। डीपफेक जैसी चीजें सामने आ रही हैं, जिन्हें लेकर सजग होना चाहिए। स्क्रीन टाइम को कम करके मैं संबंधों को समय देने में विश्वास करती हूं।

शाहिद: मानवीय स्वभाव है कि हम किसी भी चीज की सीमा से अधिक करने लगते हैं। फिर वो आदत बन जाता है। पहले हम खुले दिमाग से चीजों को देखते थे। तकनीक का दुरुपयोग, डीपफेक जैसी चीजें सभी के लिए खतरनाक हैं। तकनीक मेरी सुविधा के लिए है, पर मैं इसे आदत नहीं बनाना चाहता, इसलिए प्रयास करता हूं कि मोबाइल में उलझे रहने के बजाय जरूरी चीजों को समय दूं।

फिल्म के ट्रेलर में शादी का दृश्य है। असल जीवन में जब परिवार में शादी की बातें उठती हैं तो उन्हें किस तरह लेती हैं?

कृति: मेरे परिवार में शादी को लेकर ज्यादा बातें नहीं होतीं। दरअसल हम लोगों ने हर काम को लेकर समय-सीमा बांध दी है कि शादी एक आयु में हो जानी चाहिए, पर जीवन इससे मुक्त होना चाहिए। जीवन का कोई भी निर्णय आपको तब लेना चाहिए जब आप उसमें सहज हों।

फिल्म में रोबोट से प्रेम की कहानी है। इसकी भाव-भंगिमाएं नहीं होतीं। इस कहानी में इंसान व रोबोट का पात्र निभाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा?
कृति : ये रोबोट इंसान के काफी करीब है, इसलिए इससे प्यार हो जाता है, तो इसके साथ तो भावनाओं का स्पर्श भी दिखेगा।
शाहिद : फिल्म की थीम में यह सवाल है कि तकनीक इंसानों के निकट आती जा रही है, उनकी जगह लेती जा रही है, तो क्या कभी ऐसा समय आएगा कि रोबोट वास्तव में किसी भी क्षेत्र में इंसान की जगह ले सकेंगे। तकनीक इतनी बढ़ गई है कि अब कुछ भी एकतरफा नहीं है। चीजें एक तारतम्यता में चलती हैं। अल्गोरिदम है, आप इंटरनेट पर एक वीडियो देखते हैं, वैसे ही वीडियो आपके स्क्रीन पर आ जाते हैं। इस फिल्म में हमने ऐसा रोबोट दिखाया है, जो आज मात्र कल्पना है, पर शायद आने वाले 10-15 वर्षों में ऐसा रोबोट बन सके, जो भावनाओं का प्रत्युत्तर दे सके। इन्हीं सवालों के परिप्रेक्ष्य में हमने हल्के-फुल्के अंदाज में रोबोट और इंसान की प्रेम कहानी बुनी है।

वर्ग पहेली-2539

बाएं से दाएं
3. खोज, ढूंढ (3) 4. लाल रंग की एक प्रसिद्ध धातु (2) 6. हार, शिकस्त (4) 7. तमाशा देखने वाला (5) 8. नया व्यवहार किसी से आरंभ करना (2,3) 11. लोहे का ...., बहुत कठिन काम करना (2,3) 14. जिसने तलाक ले लिया हो (5) 15. धृतराष्ट्र का एक पुत्र (4) 17. खून, रुधिर (2) 18. खोह, गुफा, बिल (3)।

ऊपर से नीचे
1. बिलख बिलख कर रोना (3) 2. शासन का अभाव (5) 3. खोजना, ढूंढना (4) 5. गप्प मारना, बहाना करना (2,3) 8. मुख्य, प्रधान, निजी (2) 9. लचकीला, लचकने या झुकने वाला (5) 10. पास की वस्तु गंवाना, गुम होना (2) 12. बादशाह के यहां का दीवान, राजस्व (5) 13. भाग्य, किस्मत (4) 16. नाश, छुटकारा, टपकना (3)।

© Bird Features & Writing Agency

कल का हल

जागरण सुडोकू-2539

कल का हल

9	5	3	2	7	6	1	8	4
1	2	6	8	9	4	3	5	7
7	4	8	3	5	1	2	6	9
6	1	2	4	3	7	5	9	8
3	7	5	6	8	9	4	1	2
8	9	4	1	2	5	7	3	6
5	6	7	9	4	3	8	2	1
2	3	9	7	1	8	6	4	5
4	8	1	5	6	2	9	7	3

आज का भविष्यफल - 09 फरवरी, 2024 शुक्रवार

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। आज का राहुकाल: प्रात: 10 बजकर 30 मिनट से 12:00 बजे तक। आज का दिशाशूल: पश्चिम। आज का पर्व एवं त्योहार: मौनी अमावस्या। विशेष: अमावस्या तिथि क्षय

कल 10 फरवरी 2024 का पंचांग
कल का दिशाशूल: पूर्व
पर्व एवं त्योहार: गुप्त नवरात्रि प्रारंभ
विशेष: पंचक प्रारंभ (प्रात: 10:02 बजे से 14 फरवरी को प्रात: 10:43 बजे तक)।
विक्रम संवत 2080 उत्तरायण, माघ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तत्पश्चात द्वितीया धनिष्ठा नक्षत्र, तत्पश्चात शतभिषा नक्षत्र तत्पश्चात परिघ योग मकर में चंद्रमा तत्पश्चात कुंभ में।

- **मेष:** बहुप्रतिष्ठित कार्य के सम्पन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
- **वृष:** शासनसत्ता का सहयोग मिलेगा। महिला अधिकारी के कृपा पात्र होंगे।
- **मिथुन:** राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।
- **कर्क:** वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। सम्मान में वृद्धि होगी।
- **सिंह:** शासनसत्ता का सहयोग रहेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।
- **कन्या:** रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। रिश्तों में निकटता आएगी।
- **तुला:** संतान या शिक्षा के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा।
- **वृश्चिक:** पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी।
- **धनु:** किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। भागदौड़ रहेगी।
- **मकर:** राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी फिर भी मन अशांत रहेगा।
- **कुंभ:** वाणी पर संयम रखें। व्यक्ति विशेष से तनाव मिल सकता है।
- **मीन:** पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। सम्मान में वृद्धि होगी।

चर्चा में

सफलता का इतिहास दोहराने की तैयारी

जवान और एनिमल के बाद अब वरुण धवन और रणवीर सिंह जैसे सितारे तलाश रहे हैं दक्षिण भारतीय फिल्मकारों के साथ सफलता का वही इतिहास रचने की संभावनाएं...

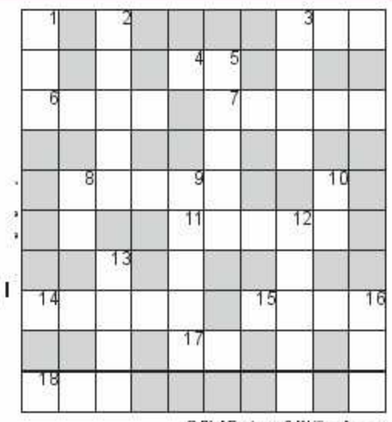

अतीत के अनुभव और सफलता की कहानियां कई बार भविष्य का खाका रचने में अहम भूमिका निभाती हैं। इस वर्ष बड़े सितारों की फिल्मों का प्रदर्शन अभी तक फीका ही रहा। ऐसे में सितारे भी सोचने लगे हैं कि सफलता के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाए। वर्ष 2023 में भारतीय फिल्मों का घरेलू बाक्स आफिस कलेक्शन 12 हजार करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया, जिसमें शीर्ष पर रही दो फिल्मों जवान और एनिमल के निर्देशक दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एटली और संदीप रेड्डी वांगा थे। उनके करिश्मे से प्रभावित बालीवुड सितारे अब दक्षिण भारतीय फिल्मकारों के साथ मिलकर वही सफलता रचना चाहते हैं।

विकल्पों की खोज: वरुण धवन फिल्मकार एटली के साथ अगली एक्शन फिल्म ला रहे हैं। पिछले कुछ समय से फिल्म की चर्चा थी, पर इस माह आधिकारिक घोषणा हो गई है। फिल्म में कीर्ति सुरेश के मुख्य भूमिका में होने पर भी मुहर लग गई है। हालांकि इसका शीर्षक अभी तय नहीं है। ऐसी खबरें हैं कि रणवीर सिंह की भी दक्षिण के कई निर्देशकों से बात चल रही है। एस शंकर की दक्षिण भारतीय हिट फिल्म अन्नियन के हिंदी रीमेक से रणवीर जुड़े थे, पर फिल्म कानूनी अधिकारों में उलझ गई। इसलिए वह नए विकल्पों की खोज में हैं। इस सिलसिले में एटली व जेलर के निर्देशक नीलसन दिलीप कुमार के अलावा गजनी जैसी हिट फिल्म के निर्देशक ए आर मुरुगदास से मुलाकात की खबरें आई हैं।

भरोसे की ठोस वजह: दरअसल नई छवि गढ़ने में दक्षिण भारतीय फिल्मकारों को महारत है। पिछले कुछ दिनों से बाक्स आफिस पर शाह रुख खान की रोमांटिक छवि कमाल नहीं कर पा रही थी। जवान ने एक्शन अवतार में उन्हें स्थापित किया। एनिमल में भी रणबीर कपूर का पात्र उनकी रोमांटिक छवि से बहुत अलग था। फिल्म में उनके चरित्र की तार्किकता पर सवाल उठे, पर युवाओं को फिल्म पसंद आई। इससे पहले सलमान खान को वांटेड से एक्शन स्टार व अक्षय कुमार को हेराफेरी से कामिक भूमिका में लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रियदर्शन को जाता है। वहीं कोविड के बाद अब दर्शक सिनेमाघरों में फिल्में देखने को तैयार हैं तो उन्हें एक्शन और भावुकता से भरा कुछ ऐसा चाहिए जिसका मजा बड़े पर्दे पर हो। ज्यादातर दर्शक युवा होते हैं। हाल में सफल फिल्में देने वाले संदीप रेड्डी वांगा, एटली, लोकेश कंगराज स्वयं उस आयु वर्ग से आते हैं, जिसको ध्यान में रखकर वे फिल्मों का निर्माण करते हैं तो उनकी शैली में वह असर दिखता है।

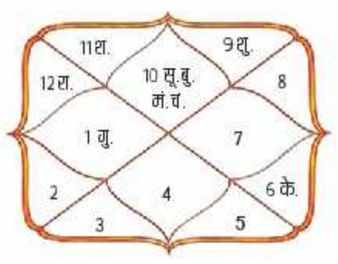

कीर्ति सिंह

बयार के साथ
दीपिका पादुकोण जवान में मेहमान भूमिका निभाने के बाद अब दक्षिण भारतीय निर्देशक नाग अश्विन की साइंस फिक्शन थ्रिलर कल्कि 2898 एडी में अमिताभ बच्चन व प्रभास के साथ दिखेंगी। वहीं कियारा आडवाणी एस शंकर की अखिल भारतीय फिल्म गेम चेंजर में आएंगी।

दक्षिण भारतीय फिल्मकारों संग जोड़ी बनाने के प्रयास में वरुण धवन व रणवीर सिंह

राष्ट्रीय फलक

मुंबई में शिवसेना के पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या

राज्य ब्यूरो, मुंबई : मुंबई के उपनगर दहिसर में शिवसेना (यूबीटी) के पूर्व सभासद अभिषेक घोषालकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले के बाद हमलावर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पैसों के विवाद में अभिषेक पर हमला किया गया। अभिषेक शिवसेना के पूर्व विधायक विनोद घोषालकर के पुत्र थे।

शिवसेना (यूबीटी) के पूर्व सभासद अभिषेक घोषालकर को गुरुवार को मारिस नामक व्यक्ति ने अपने दहिसर स्थित कार्यालय में आयोजित महिलाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। रात करीब साढ़े आठ बजे मारिस ने अभिषेक के साथ फेसबुक लाइव किया और कहा, वह अभिषेक के साथ सामाजिक कार्य करना चाहता है। फेसबुक लाइव में अभिषेक कहते नजर आ रहे हैं कि हम दोनों के बीच मतभेद की खबरें आती रहती हैं पर अब हम लोग मिलकर क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए काम करेंगे। यह कहकर अभिषेक हंसते हुए खड़े होते हैं और तभी मारिस ने अभिषेक पर गोलियां दाग दीं। फेसबुक लाइव के दौरान घटना को बड़ी संख्या में लोगों ने देखा। अभिषेक को गोली मारने के बाद कमरे से बाहर आकर मारिस ने खुद को गोली मार ली। अभिषेक को गंभीर हालत में नजदीकी करुणा अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। गत सप्ताह शनिवार को मुंबई के निकट उल्हासनगर में थाने के अंदर भाजपा विधायक गणपत गायकवाड ने शिवसेना शिंदे गुट के कल्याण शहर अध्यक्ष महेश गायकवाड पर छह गोलियां दाग दी थीं। वर्तमान में महेश अस्पताल में भर्ती हैं।

गोली लगने के बाद शिवसेना (यूबीटी) के पूर्व सभासद अभिषेक घोषालकर (स्क्रीन शाट)। एक्स

शाहजहां के विरोध पर औरंगजेब ने तुड़वाए थे मथुरा-काशी के मंदिर : इरफान हबीब

संतोष शर्मा, अलीगढ़

अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के बाद अब ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर सबकी नजर कोर्ट पर हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रो. इरफान हबीब इसकी जरूरत ही नहीं मानते। उनका कहना है कि पहले गलत हुआ। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा के मंदिर को इसलिए तुड़वाया था, क्योंकि इसे बनवाने वाले वीर सिंह जुदेव बुंदेला के बेटे ने शाहजहां की नीतियों का विरोध किया था। उसने मंदिर की जगह मस्जिद बनवा दी, जो आज मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास है। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को भी तुड़वा दिया, जहां ज्ञानवापी मस्जिद है। यह सब इतिहास में दर्ज है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमरेट्स इरफान हबीब ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा, इतिहास खंगालिए। सब साफ है। औरंगजेब ने मथुरा व काशी में ही हिंदू मंदिरों पर हमले नहीं किए और भी मंदिर तोड़े थे। जहांगीर के अच्छे मित्र रहे वीर सिंह जुदेव बुंदेला ने मथुरा में 1605-28 में मंदिर का निर्माण कराया था। यह काफी ऊंचा था। 1670 के आसपास बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह ने शाहजहां की नीतियों का विरोध कर दिया। औरंगजेब को यह बात अच्छी नहीं लगी। औरंगजेब ने उसके पिता के बनवाए मथुरा के ऐतिहासिक मंदिर को तुड़वा दिया। उस स्थान पर मस्जिद बनवा दी। 1670 के आसपास ही औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाया था। वहां भी मस्जिद बनवा दी। दोनों घटनाएं फारसी इतिहास में दर्ज हैं। इन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। अब जो हो रहा है, वो भी ठीक नहीं है।

प्रो. इरफान हबीब। जागरण

अन्यथा यह तुष्टीकरण की एक खतरनाक प्रवृत्ति बन जाएगी

प्रथम पृष्ठ से आगे

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, आप सबसे पिछड़ों को लाभ देना चाहते हैं, लेकिन सबसे पिछड़ों को लाभ देकर आप यह नहीं कर सकते कि जो सबसे पिछड़े हैं, उनमें से कुछ को ही लाभ दिया जाए और अन्य को छोड़ दिया जाए। अन्यथा यह तुष्टीकरण की एक खतरनाक प्रवृत्ति बन जाएगी। ऐसे तो कुछ राज्य कुछ जातियों को चुनेंगे, अन्य दूसरी जातियों को चुनेंगे। विचार यह है कि आरक्षण में राजनीति न होने दी जाए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि भले ही हम आपकी व्यापक दलील को स्वीकार न करें, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि आप लोग जो दलीलें दे रहे हैं, उनमें कुछ तथ्य है और हमें एक मानदंड निर्धारित करके इसे तैयार करना होगा। उल्लेखनीय है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं लंबित हैं जिनमें एससी-एसटी आरक्षण में उप-वर्गीकरण का मुद्दा उठाया गया है। मुख्य मामला पंजाब का है। पंजाब सरकार 2006 में पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) कानून, 2006 लाई थी। इस कानून में पंजाब में एससी वर्ग को मिलने वाले कुल आरक्षण में से 50 प्रतिशत सीटें और पहली प्राथमिकता वाल्मीकि और मजहबियों (मजहबी सिखों) के लिए तय कर दी गई थीं। हाई कोर्ट ने 2010 में पंजाब के इस कानून को असंवैधानिक ठहरा दिया था, जिसके विरुद्ध पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। सात जज इस मामले को इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि 2004 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में दिए फैसले में कहा था कि राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण का अधिकार नहीं है। अगस्त, 2020 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की एक अन्य पीठ ने माना था कि चिन्नैया के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है और मामला सात जजों की पीठ को संदर्भित कर दिया था।

हरदा विस्फोट : बचाव अभियान पूर्ण होने के बाद भी मिला एक शव

नईदुनिया, हरदा : मध्य प्रदेश में हरदा जिले के बैरागढ़ गांव स्थित पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार को हुए विस्फोट के बाद प्रशासन ने 11 मौतों को आखिरी आंकड़ा बताते हुए बुधवार को ही बचाव अभियान पूर्ण होने की घोषणा कर दी थी, लेकिन यह गलत साबित हुई। फैक्ट्री से कुछ ही दूरी पर गुरुवार सुबह क्षतिग्रस्त मकान से महिला का शव बरामद किया गया है। इसके बाद फिर आसपास के घरों और खेतों में तलाशी अभियान चलाया गया। विस्फोट स्थल पर पोकलेन से खोदाई के दौरान बड़ी मात्रा में पीला विस्फोटक मिलने के बाद अमला सतर्क हो गया। मौके पर टैंकरों से पानी डाला गया। उधर, बड़े हादसे के बाद सक्रिय हुए प्रशासन ने जिले में आठ पटाखा फैक्ट्रियों को सील किया है। वहीं, विस्फोट के बाद से लापता दो पुरुष एवं दो महिला श्रमिकों के स्वजन गुरुवार को भी उनकी तलाश में भटकते रहे। स्वजन का कहना है कि ये लोग फैक्ट्री के अंदर ही थे। इनके मलबे में दबे होने की आशंका है।

दूसरी फैक्ट्री में सूख रहे पटाखों को किया नष्ट: घटनास्थल से दो किमी दूर रहटाखुर्द में आरोपित सोमेश अग्रवाल की दूसरी फैक्ट्री में सूख रहे पटाखों को फायर ब्रिगेड टीम ने पानी से गीला कर नष्ट कर दिया। बता दें कि बैरागढ़ में आरोपित राजेश अग्रवाल व सोमेश अग्रवाल की दो-दो पटाखा फैक्ट्रियां विस्फोट से नष्ट हो चुकी हैं।

कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो, दोषी है तो बचेगा नहीं: सीएम : विधानसभा में गुरुवार को हरदा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में जमकर बहस हुई। कांग्रेस के काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा, मंगलवार सुबह सूचना मिली थी कि हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। तत्काल मंत्री उदय प्रताप सिंह को दो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौके पर भेजा। इस मामले में कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो, दोषी है तो बचेगा नहीं। विपक्ष ने न्यायिक जांच की मांग न माने जाने पर लीपापोती का आरोप लगाते हुए बहिर्गमन कर दिया।

कुटुंब प्रबोधन, धर्म जागरण, ग्राम विकास व नशा मुक्ति पर संघ का जोर

नईदुनिया, उज्जैन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की उज्जैन में आयोजित तीन दिवसीय केंद्रीय टोली बैठक में कुटुंब प्रबोधन, धर्म जागरण, ग्राम विकास और नशा मुक्ति पर जोर दिया गया। गुरुवार को समाप्त हुई बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित अखिल भारतीय स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए।

गुरुवार को बैठक में सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, गोसेवा, धर्म जागरण, ग्राम विकास और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इसमें अगले वर्ष 2025 में संघ स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर किए जाने वाले कार्यों पर भी मंथन हुआ। उल्लेखनीय है कि संघ की टोली बैठक समय-समय पर देश के अलग-अलग प्रांतों में होती है। इसमें अखिल भारतीय स्तर के पदाधिकारी ही शामिल होते हैं। इस बार यह बैठक कई प्रांतों में करने का निर्णय लिया गया था। उसी के तहत बैठक उज्जैन में हुई।

इन विषयों पर विस्तार से हुआ मंथन
सामाजिक समरसता : हर चिह्नित बस्ती में सामान्य वर्ग के परिवार द्वारा पिछड़े वर्ग के पांच परिवारों से मेलजोल बढ़ाने व साथ भोजन आदि करने जैसे गतिविधियों को गति देने पर चर्चा हुई।
कुटुंब प्रबोधन : सामाजिक विकार को दूर करने को कुटुंब प्रबोधन की गतिविधियों को बढ़ाने का निर्णय हुआ। तय हुआ कि एक परिवार हफ्ते में एक दिन भोजन, भ्रमण और भजन साथ में करें। घर में चर्चा के लिए गृह सभा का आयोजन हो।
गोसेवा : गाय से जुड़े उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए परियोजना को गति दी जाएगी।
धर्म जागरण : दबाव या लोभ देकर मतांतरण करने वालों को पुन: धर्म में लाने के लिए परियोजना आगे बढ़ाई जाएगी
ग्राम विकास और नशा मुक्ति : ग्राम विकास व गांवों को नशा मुक्त करने के लिए अभियान स्तर पर कार्य किया जाएगा। एक गांव चिह्नित कर उसे रोल माडल बनाया जाएगा।

बेटी पैदा होने पर एक लाख का बचत बांड देगी राजस्थान सरकार

जागरण संवाददाता, जयपुर

राजस्थान की नई भाजपा सरकार 70 हजार युवाओं को सरकारी विभागों में नौकरियां देगी। राज्य लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर एक लाख रुपये का बचत बांड दिया जाएगा। साथ ही प्रसव राशि पांच हजार से बढ़ाकर छह हजार रुपये दी जाएगी। बुजुर्गों को रोडवेज किराये में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने गुरुवार को विधानसभा में आगामी वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए उक्त घोषणाएं कीं। लोकसभा चुनाव के बाद पूर्ण बजट पेश होगा। उधर, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने अंतरिम बजट को चुनावी बजट बताया और कहा, यह दिल्ली से आया और यहां पढ़ा गया है।

70 हजार नौकरियां व बुजुर्गों को रोडवेज किराये में छूट का भी किया वादा

दीया कुमारी ने किसानों के लिए गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा, इसमें पांच लाख परिवारों को कर्ज दिया जाएगा। महिलाओं व बुजुर्गों की पेंशन एक हजार से बढ़ाकर 1150 रुपये करने की घोषणा की।

केजी से पीजी तक निश्शुल्क शिक्षा : दीया कुमारी ने अल्प आय वर्ग व सीमांत किसानों के बच्चों को केजी से पीजी तक निश्शुल्क शिक्षा का प्रबंध करने की बात कही। उन्होंने कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सौ करोड़ रुपये की लागत से महाराणा प्रताप सर्किट बनाया जाएगा। प्रदेश के 20 मंदिरों के विकास के लिए 315 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट में प्रविधान किया गया है। उन्होंने कहा कि आपातकाल में जेल गए लोगों की लोकतंत्र सेनानी पेंशन बहाल होगी।

पुलिस कंप्यूटर आपरेटर भर्ती में सेंधमारी करने वाले 12 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मेरठ: एसटीएफ ने उप्र पुलिस में कंप्यूटर आपरेटर की आनलाइन भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने वाले गिरोह के सरगना समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद के दुहाई स्थित विधान पब्लिक स्कूल के परीक्षा केंद्र से कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर कर बागपत के बड़ौत में पेपर हल किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से तीन लैपटाप, मोबाइल फोन व अन्य उपकरण बरामद किए हैं।

एएसपी एसटीएफ ब्रजेश सिंह ने बताया कि प्रदेश में 29 जनवरी से आठ फरवरी तक उप्र पुलिस में कंप्यूटर आपरेटर की आनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर बड़ौत से साल्वर गैंग के सरगना रचित चौधरी समेत तीन बदमाशों को पकड़ा गया। इसके बाद गाजियाबाद से नौ लोगों को पकड़ा गया है। वहीं, बुलंदशहर पुलिस ने पुलिस में आपरेटर पद के लिए होने वाली परीक्षा में धांधली करने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया।

जेल भरो आंदोलन पर अड़े मौलाना तौकीर, प्रशासन ने की सख्ती

जागरण संवाददाता, बरेली

इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आइएमसी) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर पर पुलिस-प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। वह बिना अनुमति इस्लामिया कालेज के मैदान में भीड़ जुटाने और उसके बाद गिरफ्तारी पर अड़े हैं। उनके तेवर देख गुरुवार को मैदान के सभी गेट बैरियर लगाकर सील कर दिए गए। एक हजार पुलिसकर्मियों को आसपास तैनात किया गया है।

एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने बताया कि बिना अनुमति भीड़ जुटी तो कार्रवाई तय है। बुधवार को कुछ लोगों ने मैदान पहुंचने की अपील करते हुए आपत्तिजनक भाषा वाले पर्चे बांटे थे। इस संबंध में मौलाना समेत 25 लोगों को नोटिस दिया गया है। यदि कोई अप्रिय स्थिति बनी तो इन सभी पर लोक व्यवस्था भंग करने की धारा में प्राथमिकी पंजीकृत की जाएगी। बुधवार को बरेली विकास प्राधिकरण ने मौलाना के भतीजे तौफीक के अवैध बाजार ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया था। गुरुवार को प्राधिकरण की टीम मौलाना की संपत्तियों की जांच में जुट गई। तौकीर रजा का आरोप है कि अयोध्या के बाद अब वाराणसी और मथुरा की भूमि भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार बेईमानी कर रही इसलिए गिरफ्तारी देंगे। गुरुवार शाम वह दिल्ली में थे। उन्होंने फोन पर कहा, शुक्रवार दोपहर को नमाज के बाद इस्लामिया मैदान जरूर पहुंचेंगे।

बरेली का इस्लामिया मैदान सील, एक हजार पुलिसकर्मी तैनात

बरेली में इस्लामिया मैदान के बाहर तैनात पुलिस। तौकीर रजा ने यहीं भीड़ जुटाने की घोषणा की है।

****

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 9 फरवरी, 2024
आजकल
14
www.jagran.com

आजाद भारत में पहली जनगणना के लिए सूची बनाने का काम शुरू हुआ

1951 में आज ही के दिन स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना शुरु हुई थी। गणना प्रक्रिया 28 फरवरी तक जारी रही। देश की जनसंख्या 36,10,88,090 दर्ज की गई। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) तैयार किया गया। जनगणना अधिनियम 1948 में लागू हुआ था।

भारतीय उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनीं अन्ना चांडी

1959 में आज ही के दिन अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुई थीं। इसी के साथ वह भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं। चांडी ने आपराधिक मामलों के वकील के तौर पर भी अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी।

ग्रैंडमास्टर जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं परिमार्जन

शतरंज ग्रैंडमास्टर परिमार्जन नेगी का जन्म 1993 में आज ही के दिन उत्तराखंड में हुआ था। वर्ष 2002 में तेहरान में अंडर-10 डिवीजन में एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप जीतकर पहली अंतरराष्ट्रीय सफलता हासिल की। वर्ष 2005 में हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस में अपने करियर का पहला ग्रैंडमास्टर नार्म हासिल किया। वर्ष 2006 में 13 वर्ष की उम्र में रूस में चेल्याबिंस्क रीजन सुपरफाइनल चैंपियनशिप में अपना तीसरा और अंतिम जीएम नार्म अर्जित कर भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर बन गए।

गर्म होती धरती का सर्वेक्षण करने रवाना हुआ पेस

मौसम के अन्य पूर्वानुमानों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी

केप केनवेरल, एपी : गर्म होती धरती के महासागरों और वायुमंडल का अंतरिक्ष से विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का जलवायु उपग्रह स्पेसएक्स के फाल्कन राकेट से गुरुवार को रवाना हो गया।

इस मिशन के तहत अंतरिक्ष से धरती पर मौजूद महासागरों, झीलों और नदियों का सर्वेक्षण किया जाएगा। मिशन का नाम प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम (पेस) है। विज्ञानियों को उम्मीद है कि एक या दो महीने में डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। उपग्रह कम से कम तीन साल तक 676 किलोमीटर ऊपर से महासागरों के साथ-साथ वायुमंडल का अध्ययन करेगा। पेस महासागरीय जीव विज्ञान का अध्ययन करने के लिए अब तक लांच किया गया सबसे उन्नत मिशन है। विज्ञानी जेरेमी वेर्डेल के अनुसार वर्तमान

फ्लोरिडा के केप केनवेरल से नासा का जलवायु उपग्रह स्पेसएक्स के फाल्कन राकेट से रवाना हुआ। रायटर

पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह सात या आठ रंगों की पहचान कर सकते हैं, जबकि पेस 200 रंगों में दिखेगा।

जनवरी में औसत वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री से ऊपर पहुंचा

नई दिल्ली, प्रेट्र : जलवायु परिवर्तन का असर साफ दिख रहा है। पिछले साल जून के बाद यह लगातार आठवां महीना है जब रिकार्ड टूटा है। इस साल दुनिया ने सबसे गर्म जनवरी का अनुभव किया। पहली बार वैश्विक तापमान पूरे 12 महीने की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत वार्मिंग सीमा को पार कर गया है।

जनवरी में पिछले 12 महीनों में वैश्विक औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। यह 1850-1900 के जनवरी के औसत तापमान से 1.66 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यूरोपीय संघ की जलवायु परिवर्तन निगरानी सेवा ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। हालांकि, इसका मतलब पेरिस समझौते में निर्दिष्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा का स्थायी उल्लंघन नहीं है, क्योंकि यह कई वर्षों में दीर्घकालिक वार्मिंग को संदर्भित करता है। कापरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस (सी3एस) ने कहा कि 13.14 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान के साथ जनवरी 2024 पिछले सबसे गर्म जनवरी 2020 की तुलना में 0.12 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था। सी3एस के विज्ञानियों ने कहा कि पिछले 12 महीनों (फरवरी 2023-जनवरी 2024) का वैश्विक औसत तापमान रिकार्ड के अनुसार सबसे अधिक था। यह 1850-1900 पूर्व-औद्योगिक औसत से 1.52 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ता में देशों ने ग्लोबल वार्मिंग को दो डिग्री सेल्सियस (3.6 डिग्री फारेनहाइट) से नीचे रखने और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य रखा था, जो कि सबसे गंभीर परिणामों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण माना जाने वाला स्तर है। कुछ विज्ञानियों ने कहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को अब वास्तविक रूप से पूरा नहीं किया जा सकता और सरकारों से लक्ष्य से अधिक मात्रा होने से रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए तेजी से कार्य करने का आग्रह किया है।

1850-1900 के जनवरी के औसत तापमान से 1.66 डिग्री सेल्सियस अधिक था

12 महीने के लिए पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत वार्मिंग सीमा को किया पार

बेहद रोचक है महिला कार्निवल दिवस

पश्चिम जर्मनी के कोलोन शहर में महिला कार्निवल दिवस पर जोकर बनी रेवलर। इस उत्सव की शुरुआत बेहद रोचक ढंग से होती है, जिसे 'वेइबरफास्टनैच' कहा जाता है। जिसमें भीड़भाड़ और शोरगुल मचाती भीड़ के बीच महिलाएं पुरुषों की टाई उतारकर उनका मजाक उड़ाती हैं। उस उत्सव पर महिलाएं स्वयं को पुरुष की तरह पेश करती हैं। एएफपी

इधर-उधर की

...जब गिलहरी की वजह से बज गया घुसपैठ अलार्म

वाशिंगटन, एजेंसी: अमेरिका के मिसौरी में पुलिस को एक बंद पड़े घर से घुसपैठ अलार्म (किसी इमारत या क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश पर बजने वाला अलार्म) बजने की सूचना मिली। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। मिसौरी पुलिस ने उस क्षण का बाडी कैमरा फुटेज इंटरनेट मीडिया पर साझा किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदूक तानकर पुलिस संदिग्ध घुसपैठिये को ढूंढ़ रही है। तभी एक गिलहरी निकलती है। अचानक हुई इस हलचल से एक अधिकारी की चीख निकल जाती है। इस वीडियो के साथ पुलिस ने पोस्टर साझा किया है, कि गिलहरी फरार है...सावधान रहें।

इंटरनेट पर प्रसारित किया जा रहा घटना का वीडियो ● इंटरनेट मीडिया

लकवा के कारण आवाज गंवाने वाले मरीजों के इलाज में मददगार हो सकती है संगीत थेरेपी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- **एम्स का न्यूरोलाजी विभाग आइआइटी दिल्ली के साथ मिलकर इस पर शुरू कर रहा है शोध**
- **जल्दी ही शुरू किया जा रहा है ट्रायल**

21% से 38 प्रतिशत मरीज ठीक से बोल नहीं पाते लकवा के कारण, मस्तिष्क हो जाता है क्षतिग्रस्त

संगीत थेरेपी है कारगर। फाइल

एम्स का न्यूरोलाजी विभाग आइआइटी दिल्ली के साथ मिलकर लकवा के कारण आवाज गंवाने वाले मरीजों के इलाज में संगीत थेरेपी के इस्तेमाल पर शोध शुरू कर रहा है। एक वर्ष के अंदर लकवा से पीड़ित ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते वे इस ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए एम्स में संपर्क कर सकते हैं। एम्स के डाक्टरों का कहना है कि विदेशों में हुए ट्रायल में इस बात के प्रमाण मिले हैं कि लकवा के कारण आवाज गंवाने वाले मरीजों के इलाज में संगीत मददगार हो सकती है। यही वजह है कि यहां भी ट्रायल शुरू किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे।

एम्स के डाक्टरों का कहना है कि देश में लकवा मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा मौत और दिव्यांगता का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। लकवा के कारण मरीजों का मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने से 21 से 38 प्रतिशत मरीज ठीक से बोल नहीं पाते। मरीजों की आवाज चली जाती है। ऐसी मरीजों की समय से स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी को रिहैबिलिटेशन में शामिल करने से बेहतर परिणाम हो सकते हैं। विदेशों में हुए कई शोध में पाया गया है कि संगीत थेरेपी से ऐसे मरीजों की आवाज में सुधार हो सकता है। लेकिन अभी तक देश में इस तरह का ट्रायल नहीं हुआ है। इसलिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) द्वारा जारी फंड से एम्स में इसका ट्रायल शुरू किया गया है। ट्रायल में शामिल होने के लिए सोमवार से शुक्रवार को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक मोबाइल नंबर 8929466866 पर संपर्क कर सकते हैं। ट्रायल में हिस्सा लेने वाले वाले लोगों की निशुल्क संगीत थेरेपी और आवश्यक जांच की जाएंगी।

संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मीनारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रतिष्ठित संगीतकार 83 वर्षीय प्यारेलाल शर्मा को कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मीनारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संगीतकार एल सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा लक्ष्मीनारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि वह बहुआयामी हैं और उन्होंने सेमी क्लासिकल से लेकर आइटम नंबर तक विभिन्न फिल्मी शैलियों में शानदार काम किया है। शानदार संगीतकार, अरेंजर और वायलिन वादक को पुरस्कार देना एक बड़ा सम्मान था। प्यारेलाल शर्मा व सहयोगी लक्ष्मीकांत कुडालकर ने 35 वर्षों से अधिक के करियर में 700 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत तैयार किए।

प्यारेलाल शर्मा। फाइल

मस्तिष्क का आंतरिक कंपास दिखाता है हमें सही दिशा

अनुसंधान

आसपास की दुनिया में भ्रमण के लिए हमें दिशा की समझ होनी आवश्यक है। यह मस्तिष्क के आंतरिक कंपास के रूप में कार्य करती है, जिससे हमरा मार्गदर्शन होता है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जब हम गलत रास्ते पर जा रहे होते हैं तो यही आंतरिक कंपास हमें सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता है।

मस्तिष्क में नेविगेशन कैसे काम करता है, इस पर बड़े पैमाने पर शोध के बावजूद विज्ञानियों में इस बात लेकर भ्रम रहा है कि यह आंतरिक कंपास सीधे व्यवहार को कैसे निर्देशित करता है। लेकिन अब हार्वर्ड मेडिकल कालेज के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में मक्खियों (फ्रूट फ्लाई) पर किया गया एक अध्ययन नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि मस्तिष्क के दो अलग-अलग क्षेत्र, कंपास की सीट और स्टीयरिंग सेंटर नेविगेशन के दौरान कैसे संवाद करते हैं। शोध का निष्कर्ष नेचर पत्रिका में हाल ही में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने एक विशेष दिशा में दौड़ते समय रास्ते से भटक जाने वाली मक्खियों के दिमाग की जांच की। उन्होंने पाया कि न्यूरान्स के तीन अलग-अलग समूह मस्तिष्क के कंपास और स्टीयरिंग क्षेत्रों के बीच संचार स्थापित करते हैं, और मक्खी को दिशा-सही बनाने में मदद करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इस तरह न्यूरान्स मक्खी को सही दिशा में ले जाने के लिए उसके आंतरिक कंपास से संकेतों को व्यवहार में उतारते हैं। अध्ययन के वरिष्ठ लेखक राचेल विल्सन ने बताया कि कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि दिशा की भावना, जो एक आंतरिक संज्ञानात्मक स्थिति है, एक जानवर द्वारा दुनिया में किए जा रहे कार्यों से कैसे संबंधित है। अपने छोटे आकार के बावजूद फ्रूट फ्लाई का दिमाग और व्यवहार जटिल होता है। (एएनआइ)

स्क्रीन शाट

करीना के साथ काम करने के लिए अलग कमरे में रहेंगे सैफ

सैफ और करीना संग करेंगे काम। (इंस्टाग्राम)@kareenakapoorkhan

हर कलाकार की एक प्रक्रिया होती है, जिसके तहत वह अपने पात्र की तैयारियां करते हैं। कोई उस पात्र में इतना रम जाता है कि उसी की तरह बर्ताव करने लग जाता है, तो कोई सेट के बाद उस किरदार से आसानी से बाहर निकल आता है। हालांकि अभिनेता सैफ अली खान का अंदाज थोड़ा सा अलग है। अगर प्रोजेक्ट में उनकी पत्नी और अभिनेत्री करीना कपूर होंगी, तो वह उनसे अलग रहेंगे। हाल ही में सैफ और करीना ने बताया कि दोनों कई वर्षों के बाद साथ में एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं। शादी से पहले दोनों ने संग टशन, एजेंट विनोद और कुर्बान जैसी फिल्में की हैं। लेकिन शादी के बाद दोनों केवल विज्ञापनों में ही साथ दिखे। करीना ने बताया कि हम दोनों को एक प्रोजेक्ट पसंद आया है। पहले सैफ कह रहे थे कि साथ में फिल्म नहीं करेंगे। लोगों को दिलचस्प नहीं लगेगा। टशन और कुर्बान फिल्में नहीं चली थी। लेकिन मैंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी फिल्म होगी, तो लोग हमें देखना चाहेंगे। हमें कुछ पसंद आया है। अब हम बतौर कलाकार काफी सहज हो गए हैं। इस पर सैफ ने कहा कि हां, इस बार मैं अच्छे से एक्टिंग करूंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, जब मैं यह फिल्म शूट करूंगा। मैं एक अलग रूम में रहूंगा। करीना ने कहा कि हां प्लीज ये करो। सैफ ने हंसते हुए कहा कि हां ताकि जब हम सेट पर मिलेंगे, तो फिर हमारे बीच रोमांस होगा।

नई प्रतिभाओं को मौका देने में विश्वास रखते हैं बादशाह ● सिडे आर्काइव

एक्टिंग का कीड़ा मेरे अंदर नहीं

सात सवाल

बड़े दर्शक वर्ग के बीच अपनी जगह बनाने के लिए कंसर्ट और लाइव शो नई प्रतिभाओं के लिए बड़े माध्यम होते हैं। गायक और रैपर आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया उर्फ बादशाह ऐसे ही हिप हाप शो बूम बाक्स के दूसरे सीजन से भी बतौर लीड परफार्मर जुड़े हैं। बादशाह से नई प्रतिभाओं, वैश्विक मंच पर भारतीय संगीत और उनके पेशेवर सफर से जुड़ी बातचीत के अंश :

● नई प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए आपका क्या प्रयास रहता है?

-मैं नई प्रतिभाओं का सपोर्ट करता आया हूं। उनके साथ मिलकर काम करता हूं। जब हम खुद नए थे, फिर थोड़ी सी पहचान बनी। आस्था गिल और रीत तलबार (गायिकाएं) के साथ काम किया। थोड़ी और पहचान बनने के बाद मैंने कई सारी नई प्रतिभाओं के साथ काम किया। अपने आगामी प्रोजेक्ट्स में भी कई नई प्रतिभाओं के साथ काम कर रहा हूं।

● नई प्रतिभाओं को किन बिंदुओं पर तौलते हैं?

-कई बार कुछ चीजें आपको बहुत दिलचस्प लग सकती हैं। जैसे अगर मुझे किसी नए रैपर के साथ काम करना होता है, तो उनका गाना और काम देखने के बाद मैं सोचता हूं कि क्या मैं अपने दिमाग में ये सोच सकता हूं? अगर उनका काम मेरी सोच से परे होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके साथ काम करूं। जिससे मैं कुछ नया सीखूं और अपने आप को टेस्ट करूं। अपने आप को पालिश रखने का यह एक अच्छा तरीका होता है।

● हाल ही में शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड मिला, वैश्विक मंच पर भारतीय संगीत के बढ़ रहे इस वर्चस्व को कैसे देखते हैं?

-वैश्विक मंच पर भारतीय संगीत का वर्चस्व तो हमेशा से था। उनको (ग्रैमी की टीम) अभी दिख रहा है। हमारी संस्कृति, हमारा संगीत हमेशा से ही बहुत समृद्ध रहा है। हम पता नहीं क्यों किसी अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से मिली वैधता के पीछे भागते हैं। ग्रैमी जैसे पुरस्कार समारोह में ज्यादा कोई गड़बड़ नहीं होती है, वहीं हमारे यहां ऐसा कोई अवार्ड नहीं है, जिस पर आप इतना विश्वास कर सकें। इसलिए शायद ग्रैमी की इज्जत बहुत होती है और कलाकारों में उसकी महत्वाकांक्षा होती है। हालांकि, हमारे संगीत का वैश्विक स्तर पर बहुत वर्चस्व है, उन्होंने इसे पहचानने में काफी देर कर दी। मुझे तो लगता है छैयां छैयां.. गाना ग्रैमी जैसे अवार्ड के योग्य था। जब वो आया था, तो मैंने पहले ऐसा कोई गाना सुना ही नहीं था।

आपके हर गाने में रहने वाले तकिया कलाम शब्द 'इट्स योर ब्वाय बादशाह..' के पीछे की क्या कहानी है?

(मुस्कुराते हुए) अब तो यह इस तरह पहचान बन चुका है कि लोग कहते हैं कि गाना-वाना मत गाओ, बस यह बोल दो। यह लगभग 10-12 साल पहले की बात है, मैं कोई गाना रिकार्ड कर रहा था और उसी बीच प्रवाह में ये शब्द भी मुंह से निकल गए। उसके बाद तो यह चीज साथ में जुड़ गई। उसके बाद मैं कहीं और दूसरा गाना कर रहा था, तो उसके निर्माता ने मुझसे कहा कि वो लाइनें तो बोल दो।

● बादशाह और आदित्य प्रतीक सिंह, दोनों नामों में से कहां किस नाम से ज्यादा बुलाए जाते हैं?

-मेरे प्रशंसकों में कई लोग मुझे आदित्य बुलाते हैं, घरवाले भी आदित्य ही बुलाते हैं। बादशाह तो कम ही लोग बोलते हैं। हां, जब कभी एयरपोर्ट या कंसर्ट जैसे किसी सार्वजनिक स्थान पर जाता हूं, तो वहां लोग बादशाह बुलाते हैं। नहीं तो ज्यादातर लोग आदित्य ही बुलाते हैं।

● फिल्म खानदानी शफाखाना से अभिनय में कदम रखा था। उसके बाद अभिनय में और कुछ क्यों नहीं किया?

-फिर कदम बाहर भी रख लिया था। मुझे एक्टिंग करने में मजा तो बहुत आया। वो फिल्म भी अच्छी थी। हालांकि, अब एक्टिंग करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरे अंदर एक्टिंग का कोई कीड़ा नहीं है। हाल ही में मैं गुरु (गायक गुरु रंधावा) से बात कर रहा था, वह कुछ फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भी कि भाई तुम कैसे कर रहे हो? मुझे तो म्यूजिक से ही समय नहीं मिल रहा है। कइयों का एक्टिंग में झुकाव होता है। मेरी झुकाव नहीं है। मैं अपने काम से खुश हूं।

● जब आप इंडस्ट्री में आए तो किन चीजों में आपको सुधार करने की जरूरत दिखी और आपने उस पर काम भी किया?

-जब हम बड़े हो रहे थे, तो हमारे दिमाग में यही होता था कि म्यूजिक ऐसे क्यों नही करते हैं, वैसे क्यों नहीं करते हैं? थोड़ा बेस और ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा और कैंडिड होना चाहिए। गानों की पंक्तियों में थोड़ा और वास्तविक मुद्दों पर बात करनी चाहिए। हर दस साल में नई पीढ़ी के कलाकार आकर पुरानी पीढ़ी के बारे में ऐसा सोचते हैं। अब भी ऐसे कई कलाकार हैं, जो मेरा गाना सुनने के बाद बोलते होंगे कि अरे इसको इस तरह से क्यों नहीं बनाया। मैं स्वयं ऐसा कलाकार बनकर रहना चाहता हूं, जो ये सोचे कि फलां गाना ऐसे क्यों नहीं बना। (दीपेश पांडेय)

एक और दक्षिण भारतीय फिल्म लगी जाह्नवी के हाथ

दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपने पैर जमाने वाले बालीवुड कलाकारों में अभिनेत्री जाह्नवी कपूर का नाम भी शुमार है। वह एक ओर जहां जूनियर एनटीआर के साथ तेलुगु फिल्म देवरा की शूटिंग कर रही हैं। वहीं पर अब अभिनेता राम चरण के साथ भी वह फिल्म करने की तैयारी में हैं। बालीवुड गलियारों की खबरों के अनुसार जाह्नवी ने आरसी 16 यानी राम चरण की 16वीं फिल्म साइन कर ली है। फिलहाल यह फिल्म का वर्किंग टाइटल है। फिल्म का शीर्षक अब तक रखा नहीं गया है। फिल्म से जुड़े करीबी सूत्रों के अनुसार जाह्नवी बेहद खुश और उत्साहित हैं कि उन्हें राम चरण के साथ इतने बड़े बजट की अखिल भारतीय फिल्म में काम करने का अवसर मिला है। इस फिल्म के अलावा जाह्नवी की झोली में निर्देशक राकेश ओमप्रकाश मेहरा निर्देशित फिल्म कर्ण भी है। खबरों के अनुसार जाह्नवी इस फिल्म में द्रौपदी का रोल निभाएंगी। इस रोल के लिए जाह्नवी कई लुक टेस्ट भी कर चुकी हैं। इन दो बड़े बजट की फिल्मों के साथ ही वह अभिनेता वरुण धवन के साथ एक माडर्न रोमांटिक कामेडी फिल्म भी कर रही हैं, जिसका निर्माण करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनी कर रही है।

इस साल तीन नई फिल्मों पर काम शुरू करेंगी जाह्नवी। फाइल

परेश ने इस तरह तय की अपने पेशेवर जीवन की दिशा

जिंदगी की दिशा तय करने में हमेशा योजनाएं ही नहीं काम आती हैं। कई बार संयोग और परिस्थितियां भी जीवन की दिशा तय कर देते हैं। फिल्म डाक्टर जी और कड़क सिंह के परेश पाहुजा ने कभी यह नहीं सोचा था कि अभिनय को अपने पेशे के तौर पर चुनेंगे। इस बारे परेश बताते हैं, 'मैंने जिंदगी में बहुत देर से यह तय किया था कि मुझे अभिनय में अपना पेशा बनाना है। हर सामान्य मध्यमवर्गीय लड़के की तरह मेरी सोच भी यही थी कि पहले पढ़ाई करेंगे फिर कोई नौकरी करेंगे। उसके बाद जिंदगी के जो शौक होंगे वो देखेंगे। इसी बीच मैं कालेज की ड्रामा सोसाइटी से जुड़ गया। फिर मुंबई आकर मास मीडिया की पढ़ाई की और एक विज्ञापन कंपनी में काम करने लगा। फिर प्रोडक्शन कंपनी में काम करना शुरू किया। वहां मैंने सिनेमा से जुड़ी चीजें जब अपनी आंखों के सामने देखीं, तो एक्टिंग का शौक भी पूरा करने की उम्मीद दिखने लगी। मैं अपने जिन दो दोस्तों के साथ रहता था, वो कास्टिंग विभाग में काम करते थे, उनके माध्यम से ही मुझे पहला विज्ञापन मिला। मुझे सेट पर बहुत मजा आया।' परेश फिल्म आपरेशन वैलेंटाइन में वायुसेना पायलट की भूमिका में नजर आएंगे।

फिल्म आपरेशन वैलेंटाइन में वायुसेना पायलट की भूमिका में होंगे परेश। (इंस्टाग्राम) @pareshpahuja

बाबी, अक्षय और अमीषा की हमराज की भी सीक्वल आई कतार में

वर्तमान दौर में हिंदी सिनेमा में चल रही फ्रेंचाइज और सीक्वल फिल्मों की लहर में कोई फिल्मकार खुद को पीछे छूटते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ज्यादातर फिल्मकारों की कोशिश है कि कैसे अपनी पहले की लोकप्रिय फिल्मों की लोकप्रियता को भुनाया जाए। इस कड़ी में अब साल 2002 में प्रदर्शित बाबी देओल, अक्षय खन्ना और अमीषा पटेल अभिनीत फिल्म हमराज का नाम भी जुड़ गया है। फिल्म को निर्देशक जोड़ी अब्बास-मस्तान ने निर्देशित किया था। इस थ्रिलर फिल्म के सीक्वल को लेकर निर्माता रतन जैन से अब्बास-मस्तान की बातचीत पिछले करीब दो वर्षों से चल रही है।

एक बार फिर साथ आ सकते हैं बाबी और अक्षय। फाइल

इस बीच अब्बास-मस्तान और रतन ने कई कहानियों पर विचार किया। सिनेमाई गलियारों की रिपोर्ट्स के अनुसार, करीब महीने भर पहले उन्हें अब ऐसी कहानी मिल गई है, जो हमराज की सीक्वल के तौर पर बनाई जा सकती है। निर्माताओं को यह कहानी मूल फिल्म से ज्यादा बड़े स्तर की और बेहतर लगी। अब अब्बास-मस्तान इसी कहानी पर फिल्म की पटकथा तैयार करेंगे। चूंकि फिल्म की कहानी तय हो चुकी है, तो जल्द ही इसकी कास्टिंग पर काम किया जाएगा। हमराज 2 में मूल फिल्म के कलाकारों को दोहराया जाएगा या इसे नए कलाकारों के साथ बनाया जाएगा, इसको लेकर अभी संशय बरकरार है। हालांकि, निर्माता रतन जैन के आफिस से कुछ संकेत आए हैं कि सीक्वल फिल्म में भी बाबी और अक्षय खन्ना को वापस लाने की कोशिशें हैं।

हर तरह के विवादों के लिए तैयार हूं : आदित्य धर

देश से जुड़े कुछ मुद्दों पर बनी फिल्में अक्सर रिलीज से पहले ही चर्चाओं में आ जाती हैं। निर्देशक-निर्माता आदित्य धर की फिल्म आर्टिकल 370 भी इन दिनों सुर्खियों में है। पांच अगस्त साल 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करते हुए राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इसी ऐतिहासिक घटना के पीछे की कहानी आदित्य अपनी फिल्म में लेकर आ रहे हैं। उनकी साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक को प्रापगेंडा फिल्म कहा गया था। क्या आदित्य 23 फरवरी को प्रदर्शित हो रही इस फिल्म को लेकर ऐसे विवादों के लिए तैयार हैं? इस पर आदित्य ने गुरुवार को मुंबई में फिल्म के ट्रेलर लांच के दौरान कहा, 'वर्तमान सरकार को चुनाव जीतने के लिए मेरी छोटी सी फिल्म की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमारे लिए राम मंदिर बनवा दिया है। मुझे नहीं लगता है कि उन्हें वोट पाने के लिए हमारी आवश्यकता है। इस फिल्म को बनाने का इरादा अच्छा है। मैं हर तरह के विवादों के लिए तैयार हूं। दर्शकों को पता होता है कि कौन सी प्रापगेंडा फिल्म है, कौन सी नहीं। मैं जब तक फिल्मकार रहूंगा, फिल्मों को बनाने का मेरा इरादा हमेशा सही होगा। जिस दिन इरादे गलत हो जाएंगे, मैं फिल्में बनाना बंद कर दूंगा।' आगे आदित्य ने खुशखबरी साझा करते हुए कहा, 'वह जल्द ही पिता बनने वाले हैं। उनकी पत्नी और अभिनेत्री यामी गौतम गर्भवती हैं।'

जल्द माता-पिता बनने वाले हैं यामी और आदित्य ● टीम आदित्य

****